वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2015-2016

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का संगठन)

National Institute of Agricultural Extension Management

(An Organization of Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt of India)

www.manage.gov.in

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	महानिदेशक का संदेश	
1	**मैनेज - एक परिचय**	**1-7**
2	**प्रशिक्षण कार्यक्रम 2015-16**	**8-19**
3	**अनुसंधान**	**20-23**
4	**योजनाएँ**	**24-41**
	एग्री क्लिनिक तथा एग्री बिजनेस केन्द्रीय योजना	24-35
	किसान कॉल सेंटर	36-37
	निवेश डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवा (देसी)	38-40
	ग्रमाणी युवाओं का कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई) और कृषिकों की क्षमता का आंकलन और प्रमाणीकरण (एफसीएसी)	41
5	**प्रबंध शिक्षा कार्यक्रम**	**42-51**
	प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (कृषि व्यवसाय प्रबंध) (पीजीडीएम) (एबीएम)	42-49
	कृषि विस्तार प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएईएम)	50-51
6	**सूचना, प्रलेखन और प्रकाशन**	**52-53**
7	**राजभाषा की प्रगति**	**54-55**
8	**प्रशासन एवं लेखा**	**56**
9	**परिशिष्ट**	
	परिशिष्ट I - मैनेज के महापरिषद का गठन	59-61
	परिशिष्ट II - मैनेज के कार्यकारी परिषद का गठन	62-63
	परिशिष्ट III - मैनेज संकाय, अधिकारी और कर्मचारियों के विवरण	64-69

CONTENTS

S.No.	Description	Page No.
	Message from the Director General	
1	**MANAGE- an Overview**	**71-77**
2	**Training Programs 2015-16**	**78-89**
3	**Research**	**90-92**
4	**Schemes**	**93-110**
	Agri-Clinics and Agri-Business Centres Scheme	93-104
	Kisan Call Centre	105-106
	Diploma in Agricultural Extension Services for Input Dealers (DAESI)	107-109
	Skill Training of Rural Youth (STRY) & Farmers Capacity Assessment & Certification (FCAC)	110
5	**Management Education Programs**	**111-119**
	Post-Graduate Diploma in Management (Agri Business Management) PGDM (ABM)	111-117
	Post-Graduate Diploma in Agricultural Extension Management (PGDAEM)	118-119
6	**Information, Documentation and Publications**	**120-121**
7	**Promotion of Official Language**	**122-123**
8	**Administration and Accounts**	**124**
9	**ANNEXURES**	
	Annexure I -Composition of the General Council of MANAGE	127-129
	Annexure II -Composition of the Executive Council of MANAGE	130-131
	Annexure III -List of MANAGE Faculty, Officers and Staff	132-135

Message from the Director General

This year, MANAGE launched some innovative programs keeping farmers in focus. A Help Desk for farmers was initiated to provide necessary advisory to farmers through print and electronic media. MANAGE also initiated a Certified Crop Advisor Program, to link extension officers with ICAR Institutes on a particular crop. Some new training programs included Induction Programs for newly recruited functionaries, training on greenhouse cultivation and maintenance for farmers; industry oriented agri skill development for rural youth; rooftop / backyard gardening for residents, etc.

Institutional collaboration was an important point on the agenda. MANAGE and National Institute of Plant Health Management (NIPHM), Hyderabad joined hands to organize the Induction Training for newly recruited officers of State Departments of Agriculture and allied departments. MANAGE entered into an MoU with Indian Institute of Oilseeds Research (ICAR-IIOR) to collaborate in joint research and extension projects. A Memorandum of Understanding (MoU) was also signed with the Department of Agriculture, Govt. of Odisha for Capacity Building Activities and other initiatives.

MANAGE achieved 100% placements yet again for its PGDM (ABM) program. The Association of Indian Universities also accorded equivalence to PGDM(ABM) with an MBA degree of an Indian University. This will facilitate students who have completed PGDM(ABM) to pursue PhD in any of the Universities. In order to enable start-up ventures by students, MANAGE entered into an MoU with RenB, Mumbai to set up an Incubator Center.

Some visitors at MANAGE included senior administrators and faculty from Agriculture and Forestry University (AFU), Nepal as a part of Agricultural Innovation Partnership (AIP) project of USAID and a team from Afghanistan.

We are grateful for the support from the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, our General Council, Executive Council and Academic Committee. We also value the support from the State Departments of Agriculture and allied departments, State Agricultural Universities and other institutions. We look forward to continue receiving such support in our future endeavor to meet the needs of our stakeholders.

V. Usha Rani, IAS
Director General

महानिदेशक का संदेश ...

इस वर्ष मैनेज ने किसानों को ध्यान रखते हुए कुछ नवीन कार्यों का आरंभ किया है। किसानों के लिए इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट माध्यमों के द्वारा आवश्यक सलाहकारी सेवा प्रदान करने के लिए फार्मर्स हेल्प डेस्क प्रारंभ किया गया। मैनज ने एक विशेष फसल पर विस्तार कर्मियों को आई सी ए आर संस्था के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रमाणित फसल सलाहकारी सेवा प्रारंभ किया है। नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नव नियुक्त विस्तार कर्मियों के प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रीन हाऊस कल्टिवेशन तथा किसानों के लिए उसका रखरखाव, ग्रामीण युवा के लिए उद्योग अभिमुख कृषि कौशल विकास, छत पर/पिछवाड़े में बगीचे बनाना सम्मिलित है।

इन कार्यक्रमों में संस्थागत सहयोग एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैनज और राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान (एनआईपीएचएम) के संयुक्त तत्वधान में कृषि एवं तत्संबंधी विभागों में नवनियुक्त अधिकारियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान के साथ मैनेज ने समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि संयुक्त रूप से अनुसंधान एवं विस्तार परियोजनाएं संपन्न कर सके। मैनेज ने कृषि विभाग, ओडिसा सरकार के साथ क्षमता निर्माण तथा अन्य क्रियाकलापो हेतु समझोते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

मैनेज ने फिर से पी जी डी एम (ए बी एम) कार्यक्रम के लिए 100 प्रतिशत कैम्पस रोजगार प्राप्त किया। दि एसोसियेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीस ने भी पी जी डी एम (ए बी एम) को एक भारतीय विश्वविद्यालय के एम बी ए के साथ समानता प्रदान की जिसमें पी जी डी एम (ए बीएम) पाठ्यक्रम संपन्न होने के बाद छात्र अन्य विश्वविद्यालयों में पी एच डी कर सके। छात्रों द्वारा स्टार्ट-अप वेंचरों को प्रारंभ करने के लिए एक इंक्युबेशन केंद्र स्थापित करने के लिए मैनेज ने **रेन बी,** मुंबई के साथ एम ओ यू किया।

इस वर्ष मैनेज में पधारे अतिथियों में वरिष्ठ प्रशासक एवं संकाय, कृषि एंव वानिकी विश्वविद्यालय (एएफयू), नेपाल ने दौरा किया यह यू एस ए आई डी के कृषि नवोन्मेशन भागीदारी परियोजना (एआईपी) तथा अफगानिस्तान दल सम्मिलित थे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, हमारे महापरिषद, कार्यकारी परिषद तथा अकादमिक समितियों को उनके सतत समर्थन हेतु आभारी है। हम राज्य कृषि विभागों तथा तत्संबंधी विभागों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य साथी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सहयोग को पहचानते है और अभार प्रकट करते हैं। भविष्य में इसी प्रकार का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त करने की आशा करते है और हम अपने लक्ष्यों की दिशा में तथा अपने स्टेकहोलडरों की आवश्यकताओं की पूर्ती हेतु निरंतर कार्य करेंगे।

वी. उषा रानी, भा.प्र.से.
महानिदेशक

1 मैनेज - एक परिचय

1.1 राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज) भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषिसहकारिता एवं किसान कल्याण, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। जिसकी स्थापना 1987 में तेजी से बढती हुई उन्नति तथा कृषि क्षेत्र की भिन्नताओं में कृषि विस्तार की चुनौतियों की प्रतिक्रिया के रूप में हुई है। भारतीय कृषि का वाणिज्य तथा विपणन गतिविधियों में परिवर्तन और कृषि तकनीक में बढती हुई क्लिष्टताओं ने कृषि विस्तार व्यवस्था के पुनराभिमुखीकरण तथा आधुनिकीकरण की ओर कदम बढाने की मांग की है। व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा कार्मिकों के कौशलीय प्रशिक्षण द्वारा वर्तमान ढांचे में परिवर्तन लाने के लिए विस्तार व्यवस्था के प्रबंधन के प्रभावशाली तरीकों की आवश्यकता है और मैनेज ने इस आवाष्यकता की पूर्ती के लिए पर्याप्त कार्य किया।

1.2 मैनेज को एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में दिनांक 11 जून, 1987 में आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) के अंतर्गत सार्वजनिक सोसाइटी में पंजीकरण अधिनियम, 1350 फसली (1350 एफ का अधिनियम) के तहत पंजीकृत किया गया है।

1.3 अधिदेशानुसार मैनेज को विस्तार कर्मियों के ज्ञान कौशल तथा व्यवहार में बढोत्तरी सहित कृषि एवं तत्संबंधी क्षेत्रों में नीतियों तथा कार्यक्रमों के द्वारा सेवा सुपुर्दगी तंत्रों को विकसित करने में भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा संध राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना है। प्रशिक्षण शिक्षा, अनुसंधान, परामर्शी सेवा तथा सूचना प्रलेखन के साथ-साथ कुछ सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर संस्थान ध्यान केंद्रित करता है।

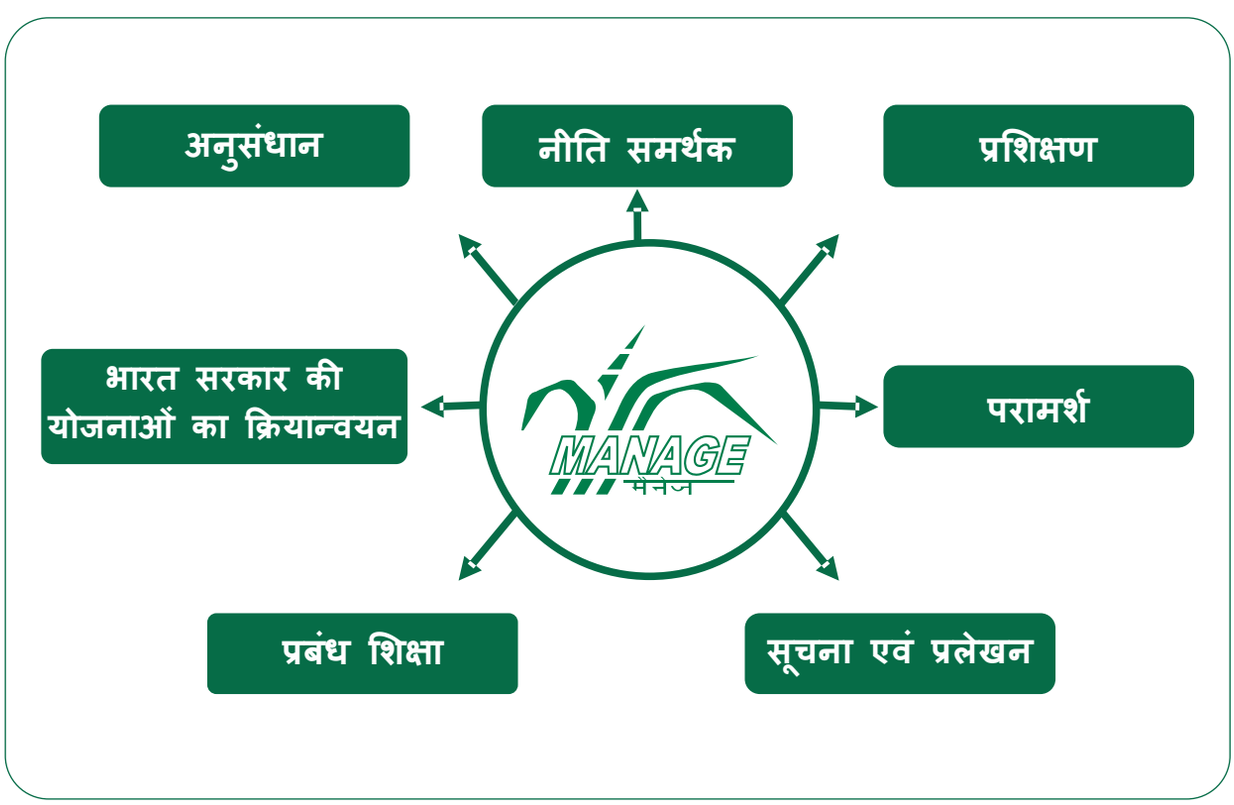

1.4 मिशन

मैनेज का मिशन कृषि अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विस्तार अधिकारी, प्रबंधक, वैज्ञानिक और प्रशासनिकों द्वारा प्रबंधकीय और तकनीकी कौशल प्राप्त करने में सहायता करना, जिससे सतत कृषि अपनाने के लिए किसानोंऔर मछुवारों को समर्थ बनाने में सहायता उपलब्ध हो सके।

1.5 विज़न

विश्व में अग्रणी, नवोन्मेषी, प्रयोक्ता स्नेही तथा स्व-समर्थित कृषि प्रबंध संस्थानों में शामिल होना है।

1.6 अधिदेश

कृषि विस्तार प्रबंध तथा कृषि विकास से संबंधित मुख्य राज्य, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ संयोजन विकसित करना।

कृषि विस्तार प्रबंध और नीतियों से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना

संकाय संसाधनों के आदान-प्रदान के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोगात्मक संयोजनों को बढाना।

कृषि विस्तार संस्थानों की प्रभावशालिता में सुधार हेतु आधुनिक प्रबंध उपकरणों के अनुप्रयोग का विकास और बढाना।

वरिष्ठ तथा मध्य स्तर के कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण का आयोजन करना।

कृषि विस्तार प्रबंध पर समस्या अभिमुख अध्ययन का आयोजन करना।

विषयों पर सूचना का संग्रहण, भण्डारण, प्रसंस्करण तथा संचरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र के रुप में काम करना है।

1.7 मुख्य मूल्य

प्रयोक्ता स्नेही

ग्राहक केन्द्रित प्रक्रिया परामर्श

सभी व्यावसायिक सेवाओं में किसान सकेन्द्रित दृष्टकोण

प्रतिक्रियात्मक और प्रयोगात्मक रुप से सीखने की क्रियाविधि

सुसाध्यकर्ताओं के साथ संकाय विकास और नेटवर्किंग

वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का दृढ संकल्प

1.8 मैनेज के कार्यक्रम एवं क्रियाकलाप सरकारी एवं निजी संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों, किसान समूहों तथा संगठनों, निजी विस्तार सेवा प्रदाताओं, कृषि व्यापार कंपनियों तथा सहकारी संस्थानों के अलावा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषक संस्थानों के लिए करता है।

1.9 मैनेज सरकारी विस्तार कर्मियों से विभिन्न राज्यों के कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा, मत्स्यपालन, कोशकीट पालन विभागों में कार्यरत है, कृषि विज्ञान केंद्रों, आई सी ए आर संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों तथा निजी क्षेत्र के कार्यकारियों के लिए प्रशिक्षण, कार्यशालाए तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है। मैनेज के कार्यक्रम भारत सरकार/केन्द्र शासित संगठन तथा निजी क्षेत्र के अनुरोध के अनुरुप भी तैयार किए जाते है।

1.10 मैनेज में अनुसंधान की केंद्र बिन्दु कृषि विस्तार प्रबंध के समकालीन विषयों से संबद्ध रखना हैं। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों/परियोजनाओं का मूल्यांकन उनकी प्रभावशालिता का आकलन करने किया जाता है। मैनेज क्षेत्र विषयों में सीमित मात्रा एवं क्षेत्र में विचार/संकल्पनाओं/ तकनीकों का पाईलेट परीक्षण करने 'एक्शन रीसर्च' भी करता है। इसके अलावा, कृषि एवं तत्संबंधी विभागों/एजेन्सियों के अनुरोध पर रणनीतियों एवं कार्यक्रम के विकास में परामर्शी सेवा भी प्रदान की जाती है।

1.11 प्रबंध शिक्षा मैनेज का एक और ध्यानाकर्षक क्षेत्र है मैनेज स्नातकोत्तर कृषि व्यापार प्रबंध डिप्लोमा[(पी जी डी एम (ए बी एम)] प्रदान करता है जिसका प्रारंभ वर्ष 1996 में टेक्नो मैनेजर्स को तैयार करने के लिए हुआ था। एक और कार्यक्रम स्नाताकोत्तर कृषि विस्तार प्रबंध डिप्लोमा (PGDAEM) का प्रारंभ 2007 में हुआ जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के आधार पर सेवारत विस्तार कर्मियों के लिए एक वर्षीय निरंतर शिक्षा कार्यक्रम है।

1.12 मैनेज भारत सरकार की कुछ योजनाओं जैसे "एग्रि क्लिक एवं एग्रि बिजिनेस केंद्र योजना (AC&ABC) किसान कॉल सेंटर (KKC), इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवा डिप्लोमा (DAESI), ग्रामीण एवं युवाओं का कौशल प्रशिक्षण (STRY) एवं किसान क्षमता का आकलन एवं प्रमाणीकरण (FCAC) का कार्यान्वयन भी करता है।

ए सी ए बी सी योजना का प्रारंभ 2002 में लोक विसतार को पूरक मदद देना ता साथ में कृषि स्नातकों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। किसान कॉल सेंटर किसान समुदाय के लिए स्थानीय भाषाओं कें विस्तार सेवाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय टेलिकॉम सुविधाओं की गति को तीव्र करने का प्रयास करता है।

देसी (DAESI) कार्यक्रम का आरंभ व्यावसायिक इनपुट डीलरों को "कॉनटैक्ट कलास-सह-दूरस्थ शिक्षा आधार" पर कृषि से संबद्ध तकनीकी विषयों पर व्यावहारिक विषय ज्ञान प्रदान करने के लिए किया गया है।

एस टी आर वाई का लक्ष्य कृषि एवं तत्संबंधी क्षेत्रों के कृषि आधारित व्यावसायिक विषयों पर ग्रामीण युवाओं को कौशल आधारित रोजगार को प्रोत्साहित कर सके और कृषि गैर-कृषि कार्यों में कौशलयुक्त कर्मियों को तैयार कर सके।

एफ सी ए सी का लक्ष्य कृषि और संबंधित क्षेत्रों में कौशल युक्त होने के बावजूद प्रमाणपत्र नहीं रहने के कारण अकुशल मजदूर के रूप में माने जाने वाले किसानों को एक पहचान प्रदान करना है।

1.13 मैनेज में केंद्र

मैनेज के मुख्य क्रियाकलाप आठ विषय आधारित केन्द्रों एवं एक कृषि व्यापार प्रबंधन स्कूल के माध्यम से चलाये जाते हैं।
प्रत्येक केन्द्र का विवरण निम्नानुसार है:-

1. कृषि विस्तार नीति, सुधार तथा प्रक्रिया केंद्र

इस केंद्र का मुख्य कार्य कृषि विस्तार प्रबंधन है - शिक्षा - कृषि विस्तार प्रबधकों के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना, ऑनलाइन पर प्रशिक्षण तथा परीक्षण मॉड्यूल को विकसित करना, कृषि विस्तार समाधान, तकनीकी नवोन्मेशन तथा सुधारों को प्रदान करना है।

2. कृषि-संस्थान क्षमता निर्माण का केंद्र

इस केंद्र का मुख्य केंद्र बिन्दु विस्तार कार्यकर्ताओं, संस्थानों तथा अन्य स्टेक हॉल्डरों, का क्षमता निर्माण करना, परियोजना योजना तथा क्रियान्वयन, प्रशिक्षण संस्थानों तथा प्रशिक्षकों का प्रामाणीकरण, पद्धति का निर्माण, विभिन्न स्टेकहोल्डरों की क्षमता परीक्षण के अभ्यासों व्यवस्थाओं तथा प्रणालियों को विकसित करना, संस्थानात्मक उत्कृष्टता को प्राप्त करने के अभ्यासों को विकसित करना तथा विस्तार प्रयासों के प्रभावी निर्धारण हेतु कार्यप्रणालियों को विकसित तथा परिचालन करना है।

3. कृषि बाजार, आपूर्ति श्रुंखला प्रबंधन तथा विस्तार परियोजना केंद्र

इस केंद्र का मुख्य केंद्र बिन्दु बाजार चालित विस्तार हेतु अभ्यास तथा नमूने विकसित करना, बाजारों से किसानों का संपर्क स्थापित करना, माइक्रो तथा माक्रो दोनों स्तर पर आपूर्ति श्रुंखला प्रक्रिया अभिमुख बनाने से संबंधित प्रभावी विस्तार सेवाएं प्रदान करना।विस्तारपरियोजना योजना व प्रबंधन पर, विस्तार परियोजनाओं में अभिसरण को बढ़ावा देना तथा बाजार क्रियाकलापों के संदर्भ मे विस्तार सेवाओं के प्रभावी सुपुर्दगी पर भी यह केंद्र ध्यान देता है।

4. संबंधित विस्तार

इस केंद्र की मुख्य केंद्र बिन्दु विस्तार प्रबंधन के लिए प्रणालियों, विचारों तथा अभ्यासों को विकसित करना तथा एकीकृत विस्तार कृषि व्यवस्था के अधार पर बागवानी, मत्स्य, पशुपालन, दुग्ध, कृषि-वन्य, मुर्गी तथा पुष्प कृषि के लिए विस्तार समर्थन प्रदान करना, जल विस्तार बडे व मध्यम क्षेत्र के समतल सिंचाई परियोजनाओं के लिए विस्तार प्रबंधन प्रणालियों को विकसित करना, विभिन्न जल तथा निवेश प्रबंधन प्रणालियों में विस्तार प्रबंधन के अभ्यासों में एक्शन रीसर्च चलाना है।

5. ज्ञान प्रबंधन, आईसीटी तथा मास मीडीया का केंद्र

इस केन्द्र का मुख्य उद्देश्य केंद्र ज्ञान प्रबंधन रणनीति के परिचालन तथा संविचारों को विकसित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। कृषि विस्तार से संबंधित प्रलेखों के भंडार के रुप में कार्य कर रहा है। विस्तार सिफारिशों का डेटाबेस तैयार करता है, एनएमएईटी के कार्यान्वयन हेतु साफ्टवेर विकास समर्थन तथा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी पर क्षमता निर्माण करना, किसान स्तर पर ई-साहित्य विकसित करना तथा कृषि-संचार सेवाएं, ई-विस्तार, मास मीडिया का समर्थन करना है।

6. युवावर्ग, पीपीपी तथा कृषि उद्यमिता का केंद्र

इस केंद्र का मुख्य कार्य कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार/रोजगार के अवसरों को बढाना, रोजगार तथा आय उत्पन्न करने के लिए कृषि उद्यमिता को बढावा देना, कृषि व्यापार के लिए मैनपावर विकसित करना, कृषि को कृषि उद्यमिता के रूप में तथा कृषक को कृषि उद्यमी के रूप में अंतरण करना, कृषि में युवा वर्ग को रखना, सरकारी-निजी भागीदारी इत्यादि है।

7. महिला व घरेलु खाद्य एवं पौष्टिक सुरक्षा, शहरी कृषि तथा हरी सब्जियों की उपज का केंद्र

इस केंद्र का मुख्य कार्य कृषि विस्तार प्रबंधन मे महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण करना,कृषक परिवारों को खाद्य एंव पोषण सुरक्षा पर उनकी जानकारी मे सुधार लाना, पौष्टिकता का बजट बनाना तथा नियोजन संकल्पना का विकास एवं परिचालन, हरितीकरण से खाद्य योग्यहरितीकरण की ओर तथा लैंडस्केपिंग से खाद्य योग्य लैंडस्केपिंग की ओर बढना तथा उचित प्रशिक्षण मॉड्यूलों को विकसित करना है।

8. कृषि संबंधी अध्ययन, लाभवंचित क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधन प्रबंध विस्तार तथा सामाजिक जुटाव का केंद्रः

इस केंद्र का ध्यान, मुख्य रूप से एग्रेरियन स्टडीज पर होता है जिसमे लाभवंचित क्षेत्र विस्तार विभिन्न स्थानीय एवं सामाजिक चुनौतियों का सामना करने हेतु विशेष विस्तार रणनीतियों तथा अभ्यासों को तैयार करना; क्षेत्रीय समानता को बढावा देना एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंध विस्तार है। इसके अतिरिक्त यह केंद्र एन.एम.ए.ई.टी. में सामाजिक जुटाव तथा सामाजित समांतरता और किसान चार्टर का विकास एवं परिचालन के लिए विशेष कार्यक्रमों में विभिन्न सामाजिक समूहों तथा सामाजिक जुटाव के लिए सामाजिक समांतरता को प्रोत्साहित करने पर ज़ोर देता है।

9. कृषि व्यापार प्रबंधस्कूल

यहस्कूल व्यापारिकरण में परिवर्तित लक्ष्यों की स्थिति में युवा मस्तिष्कों को कृषि व्यापार प्रबंध की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने हेतु स्नातकोत्तर कृषि व्यापार प्रबंध डिप्लोमा प्रदान करता है।

1.14 कृषि उन्नति में मैनेज

मैनेज ने भाग लिया कृषि उन्नति मेले में और अपने नवीन कार्यों का प्रदर्शन किया। यह कृषि विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

द्वारा आयोजित मेला-सह-प्रदर्शनी है जो 19 से 21 मार्च, 2016 के दौरान आई ए आर आई नई दिल्ली में आयोजित की गयी थी। एग्रि-क्लिनिक्स एवं एग्रि-बिजिनेस केंद्र योजना (ACABC) के तहत प्रशिक्षित पाँच उत्तम एग्रिप्रेन्यूरों को अपने उद्यमों को प्रदर्शित करने के लिए मेले में आमंत्रित किया गया था।

1.15 संस्थागत सहयोग मैनेज और राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान (NIPHM), हैदराबाद दोनों मिलकर राज्य कृषि, बागवानी, पशुपालन, बीज प्रमाणीकरण एवं कृषि विपणन विभागों के नव नियुक्त अधिकारियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया है जिस का उद्देश्य किसानों तक तकनीकियों को प्रभावी एवं सक्षम रूप से अंतरण करने हेतु युवाओं को ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना है।

मैनेज के स्टॉल को देखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
के केंद्र मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी

1.16 मैनेज ने अनुसंधान एवं विस्तार परियोजनाओं में सहयोग हेतु 26 जनवरी, 2016 को आई सी ए आर के तहत भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान के साथ समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका लक्ष्य दोनों संस्थानों के बीच अतिथियों एवं प्रशिक्षार्थियों के लिए अकादमिक व अनुसंधान सहयोग को सरल बनाना है।

1.17 मैनेज एवं कृषि विभाग, ओडिसा सरकार ने एक समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जिसका उद्देश्य दक्षता विकास क्रियाकलापों तथा कृषि में आई सी टी की उपयोगिता, किसान कॉल सेंटरों की वृद्धि, सी सी के एन - आई ए, ई-गवर्नेन्स के क्षेत्रों में ओडिसा सरकार के प्रारंभिक कार्यों का समर्थन करना है।

संस्थागत नवोन्मेशन तथा समाचार

1.18 किसानों के लिए हेल्प डेस्क का प्रारंभ

किसानों को वैज्ञानिक एवं कृषि के लाभकारी विधियों संबंधी उपयुक्त सूचना देने की आवश्यकता महसूस करते हुए जिससे वे चुनौतियों का सामना कर सके, मैनेज ने प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से किसानों को आवश्यक सलाहकारी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से फार्मर्स हेल्प डेस्क को प्रारंभ किया है।

1.19 प्रमाणित फसल सलाहकार

"प्रमाणित फसल सलाहकार" कार्यक्रम के माध्यम से विस्तार अधिकारियों को आई सी ए आर संस्थाओं के साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम मैनेज ने प्रारंभ किया। इस पाठ्यक्रम में अधिकारियों को तीन महीने तक ऑनलाईन कोर्स कराया जाता है और हैण्ड होल्डिंग समर्थन सहित एक विशेष फसल हेतु आई सी ए आर संगठनों के साथ जोड़ा जाता है।

1.20 मैनेज प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु मोबाईल ऐप

मैनेज ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रबंधन हेतु एक एन्ड्राइड मोबाईल एप विकास किया है। इस ऐप के माध्यम से कृषि अधिकारी मैनेज कैलेंडर कार्यक्रमों की जानकारी लेकर उपयुक्त प्रशिक्षण का चयन कर इसी एप द्वारा पंजीकृत भी कर सकते है। डैटा बेस में विवरण दर्ज होते ही कार्यक्रम निदेशक एवं आवेदक अधिकारी को ई-मेल भेजा जाएगा।

1.21 मैनेज में इन्कुबेशन केंद्र

मैनेज के पी जी डी एम - ए बी एम छात्रों के लिए स्टार्टअप - इन्कुबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए मैनेज ने रेन बी, मुम्बई के साथ समझौता के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जो वर्तमान एवं पूर्व छात्रों को अपने विचारों एवं नवोन्मेशनों के आधार पर व्यापार प्रारंभ करने में जानकारी एवं अवसर में वृद्धि करेगा।

अतिथि

1.22 कृषि एवं वनविज्ञान विश्वविद्यालय (AFU), नेपाल के संकाय एवं वरिष्ठ प्रशासकों ने 8 सितंबर, 2015 को मैनेज का दौरा किया। यह कोरनेल सतगुरू, हैदराबाद द्वारा संस्थागत दक्षता, मानव संसाधनों का विकास एवं संगठनात्मक क्रियाकलापों की वृद्धि हेतु यू एस ए आई डी के कृषि नवोन्मेशन भागीदारिता (AIP) परियोजना के तहत आयोजित किया गया था।

1.23 1अक्तूबर, 2015 को अफगानिस्तान के 11 सदस्यों के एक दल ने मैनेज का दौरा किया था। इस दौरे का प्रायोजन बारानी क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICARDA) द्वारा किया गया था। इस दल में आई सी ए आर डी ए के प्रतिनिधि तथा जल संसाधन, जलागम, प्राकृतिक संसाधन, वन विज्ञान से निपट रहे अफगानिस्तान के मंत्री उपस्थित थे।

1.24 श्री राजेन्द्र सिंह, जिन्हें "वाटर मैन ऑफ इंडिया" के नाम से जाना जाता है ने 20 जनवरी, 2016 को मैनेज का दौरा किया। श्री राजेन्द्र सिंह राजस्थान के अलवर जिले में कार्य करते है जो जल संरक्षक के रूप में सुपरिचित है और वे "तरूण भारत संघ" के नाम पर एक गैर सरकारी संगठन को भी चला रहे है। उन्होंने मैनेज के संकाय प्रशिक्षण में आए कार्यकारियों को संबोधित किया और जल संरक्षण के महत्व को समझाया।

2 प्रशिक्षण कार्यक्रम 2015 - 16

2.1 कृषि एवं तत्संबंधी क्षेत्रों के वरिष्ठ एवं मध्यस्तरीय कर्मियों का दक्षता निर्माण कराना मैनेज के अधिदेश का एक मुख्य भाग है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कृषि एवं तत्संबधी विभागों राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक तथा आई सी ए आर संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों क कार्यकारियों हेतु कृषि विस्तार प्रबंध में उभर रहे नए क्षेत्रों में मैनेज प्रशिक्षण कार्यशालाओं तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है, ताकि वे सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर सके तथा इस क्षेत्र की चुनौतियों का सामना कर सके। ये कार्यक्रम कृषि विस्तार प्रबंध के विभिन्न वर्तमान विषयों पर उपयोग करने की जानकारी के आधार पर संकल्पनात्मक समझ प्रदान करते है। कार्यक्रमों को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि विस्तार कर्मी तथा अन्य व्यवसायिक चुनौतियों को सामना करने योग्य बने तथा सरकार के विभिनन फ्लैगशिप कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन कर सके।

2.2 वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर वार्षिक प्रशिक्षण योजना कार्यशाला में लिये गये निर्णयो के आधार पर तैयार किया जायेगा। इस कार्यशाला में ई ई आई व समेतियों के निदेशकों, कृषि एवं तत्संबंधी विभागों के प्रतिनिधियों/प्रशिक्षण संचालकों तथा आई सी ए आर/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक भाग लेते है तथा अपना मूल्यवान सुझाव प्रदान करते हैं। यह कार्यशाला प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर सूचना, प्रस्तावित कार्यक्रमों की विषय वस्तु तथा अपनाए गए नवोन्मेशी अभिगमों एवं संभव सहयोगों संबंधी सूचना का आदान प्रदान करने का मंच प्रस्तुत करता है। कार्यक्रमों के विषय वस्तु तथा कार्यक्रमों को तैयार मैनेज के आठ केंद्रों के विषय वस्तु के अनुरुप होगा। वर्ष 2015-16 के लिए कुल 188 कार्यक्रमों को आयोजित करने का प्रस्ताव है। वार्षिक प्रशिक्षण योजना कार्यशाला पर लिये गए के आधार पर तैयार की गयी है।

विधि

2.3 ऑन कैम्पस कार्यक्रमों में छः दिवसीय कार्यक्रम का अनुसरण किया गया जबकि प्रथम चार दिवस मुख्य विषय वस्तु के निवेश तथा एक दिन साफ्ट स्किलस के लिए रखा गया जिसका केंद्र कार्यक्रम में आने वाले कार्यकारियों की विशिष्ट आावश्यकताओं पर होगा जिसमें प्रेरणा संपर्क, नेतृत्व आदि सम्मिलित है। एक अर्ध दिवस मॉड्यूल कृषि में लिंग सुग्राह्यता तथा आई सी टी सत्र कार्यक्रम के दौरान आयोजित किए जाएंगे। ऑफ-कैम्पस कार्यक्रम विषय वस्तु की आवश्यकतानुसार 3-4 दिन की होगी।

2.4 विभिन्न सत्रों से शिक्षा प्राप्त करने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी विधि का अनुपालन किया जाता है। भाषण सह- विचार-विमर्श, केस स्टडीज, रोल प्ले जैसी प्रशिक्षण विधियों का तथा क्षेत्रीय दौरे का आयोजन उचित प्रक्रियाओं की सीधी जानकारी प्राप्त करने के लिए किए जाते है।

वार्षिक प्रशिक्षण योजना कार्यशाला

प्रबंध खेल के माध्यम से साफ्ट स्किल्स

वर्ष 2015-16 आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

2.5 पुनरावलोकित 2015-16 वर्ष के दौरान मैनेज ने 5,129 कार्यकारियों के लिए 198 कार्यक्रम आयोजित किया है। केन्द्र अनुसार सविवरण आयोजित प्रशिक्षण, पुनश्चर्या कार्यक्रम तथा कार्यशालाये तालिका- 1 में प्रस्तुत है।

क्र. सं	केंद्र का नाम	आयोजित कार्यक्रम			आयोजित कार्यक्रम	भागीदारों की संख्या
		प्रशिक्षण कार्यक्रम	कार्यशाला	पुनश्चर्या कार्यक्रम		
1.	कृषि विस्तार नीति, सुधार तथा प्रक्रिया केंद्र	17	-	-	17	435
2.	कृषि-संस्थान क्षमता निर्माण का केंद्र	21	1		22	580
3.	कृषि बाजार, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तथा विस्तार परियोजना केंद्र	21	2	10	33	888
4.	संबंधित विस्तार का केंद्र	15	-	-	15	406
5.	आईसीटी, मास मीडीया तथा ज्ञान प्रबंधन का केंद्र	35	3	10	48	1075
6.	कृषि उद्यमिता, युवावर्ग तथा सरकारी निजी भागीदारीता का केंद्र	6	2	20	28	744
7.	महिला वघरेलु खाद्य एवं पौष्टिक सुरक्षा, शहरी कृषि तथा हरी सब्जियों की उपज का केंद्र	16	1	-	17	398
8.	कृषि संबंधी अध्ययन, लाभवंचित क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधन प्रबंध विस्तार तथा सामाजिक जुटाव का केंद्र	17	1		18	603
	कुल	**147**	**10**	**41**	**198**	**5129**

उपर्युक्त कार्यक्रमों में केर-इनडिया तथा नारियल विकास बोर्ड के लिए आयोजित परामर्शी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सम्मलित है।

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

2.6 मैनेज ने चौथा भारत-अमरीका-अफ्रिका (भा-अ-आ) त्रिकोणीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि विस्तार प्रबंध के नए आयाम पर केन्या, लाइबीरिया व मालावी के 39 कार्यकारियों के लिए 16 जुलाई, 2015 से 13 सितंबर, 2015 के दौरान आयोजित किया।

दो माह की अवधि के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम सं.रा. अमरीका सरकार के ग्लोबल हंगर और फुड सेक्सूरिटी इनिशिएटिव फीड द फ्युचर द्वारा समर्थित भारत एवं सं.रा. अमरीका के बीच भागीदारिता के फल स्वरूप प्रारंभ किया गया है। इस भागीदारीता का लक्ष्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना तथा केन्या, लाइबीरिया और मलावी में बाजार संस्थानों का समर्थन देना है।

भा-अ-आ त्रिकोणीय प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त होने के तुरन्त बाद, भागीदारों के सर्वेक्षण के भाग के रूप में केन्या, लाइबीरिया और मालावी में निम्न तीन राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया।

1. केन्या में राष्ट्रीय सम्मेलन 24 नवंबर, 2015, नैरोबी, केन्या
2. लाइबीरिया में राष्ट्रीय सम्मेलन 27 नवंबर, 2015, मोनरोविया, लाइबीरिया
3. मालावी में राष्ट्रीय सम्मेलन 27 नवंबर, 2015, लिलोंग्वे, मलावी

नवप्रवर्तित विषय वस्तु

2.7 इस वर्ष के दौरान मैनेज ने निम्न नवीन कार्यों को प्रारंभ किया

कृषि, बागवानी तथा पशुचिकित्सा विभागों मे नव-नियुक्त कर्मियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

मेदक जिले के किसानों के लिए ग्रीन हाऊस कल्टिवेशन और उसका रख रखाव।

ग्रामीण युवा के लिए उद्योग अभिमुख कृषि कौशल विकास

एन आई पी एच एम के सहयोग में ए सी ए बी सी योजना के तहत विस्तार कर्मी तथा नोडल प्रशिक्षण संस्थानों के लिए पौध स्वास्थ्य प्रबंध पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम।

हैदराबाद वासियों के लिए छत पर/पिछवाड़े में बगीचा लगाना।

विभिन्न केंद्रों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. कृषि विस्तार नीति, सुधार तथा प्रक्रिया केंद्र

इस केंद्र द्वारा अलग अलग अवधि के कुल 17 कार्यक्रम, जिनमें 60 दिनों का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम भी सम्मिलित है। जिसमें कुल 435 कार्यकारियों ने भाग लिया ।

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	भागीदारों की संख्या
1.	कृषक से कृषक तक विस्तार	2	48
2.	विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए फार्म पत्रकारिता कौशल	1	26
3.	एन आई पी एच एम के पी जी डी एम छात्रों के लिए कृषि विस्तार प्रबंध	1	10
4.	इनोवेटिव विस्तार के प्रयास	2	46
5.	एसआरईपी की पुनरीक्षा" पर प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	2	79
6.	आफ्रिका एवं आसिया के विस्तार कर्मियों के लिए कृषि विस्तार के नए आयाम पर चौथा भारत-अमरीकी -अफ्रिका त्रिकोणीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	39
7.	गांवों के समेति एंव आत्मा अधिकारियों के लिए विस्तार सुधार पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	37
8.	कृषि आजीविकाओं की आयोजना और प्रबंधन	1	29
9.	नैरोबी में भारत अ-आ त्रिकोणीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम पर राष्ट्रीय सम्मेलन	1	24
10.	मोनरोविया, लाईबीरिया में भ-अ-आ त्रिकोणीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम पर राष्ट्रीय सम्मेलन	1	28
11.	लिलोंग्वें मलावी में भ-अ-आ त्रिकोणीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम पर राष्ट्रीय सम्मेलन	1	29
12.	कृषि, एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए प्रारंभिक सह-पुनश्चर्या कार्यक्रम	3	40
	कुल	**17**	**435**

2. कृषि संस्थाओं के क्षमता निर्माण को केंद्र

इस केन्द्र के अधीन 580 कार्यकारियों के लिए 22 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों की विषय वस्तुएं तथा कार्यक्रमों में उपस्थित कार्यकारियों की संख्या निम्नतालिका में प्रस्तुत है:

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	कार्यकारियों की संख्या
1.	वैयक्तिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से स्व-प्रबंधन	3	83
2.	डब्ल्यूटीओ और भारतीय कृषि पर इसकी विवक्षाएं	2	32
3.	एकीकृत जलसंभार प्रबंध परियोजनाओं (आईडब्ल्यूएमपी) की योजना और प्रबंधन पर प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	2	52
4.	विकासात्मक व्यावसायिकों के लिए कार्य नैतिकता	2	60
5.	कृषि संबंधी विस्तार संस्थानों तथा संबद्ध विभागों के प्रशिक्षकों के लिए व्यावसायिक कौशल	3	61
6.	उत्पादक समूहों एवं संगठनों के गठन एवं प्रबंधन पर प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	23
7.	विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए प्रभावी संप्रेषण	2	46
8.	प्रशिक्षकों के लिए प्रबंधन खेल	1	20
9.	कृषि विस्तार में आभिसरण हेतु प्रबंधकीय कौशल	3	86
10.	प्रशिक्षकों के लिए प्रबंध विकास कार्यक्रम	1	38
11.	सी ए आर ई भारत भुवनेश्वर के लिए कृषि उद्यमिता पर फेसिलिटेटर प्रशिक्षण	1	10
12.	वार्षिक प्रशिक्षण योजना कार्यशाला	1	69
	कुल	**22**	**580**

3. कृषि बाजार, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तथा विस्तार परियोजना केंद्र

इस केंद्र के तहत इस वर्ष के दौरान 888 कार्यकारियों के लिए निम्न विषयवस्तु पर 33 प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उपस्थित कार्यकारियों की संख्या निम्नतालिका में प्रस्तुत है:

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	भागीदारों की संख्या
1.	कृषि विपणन - नये अयाम	6	160
2.	किसानों को बाजारों से जोडना	4	160
3.	कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन	5	123
4.	पौध-स्वास्थ्य प्रबंधन तथा कृषि विस्तार पर प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	2	44
5.	परियोजना आयोजन और प्रबंधन	1	30
6.	देसी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी/फेसिलिटेटरों का पूर्वाभिमुखी करण कार्यक्रम	1	32
7.	नारियल उत्पादन कंपनियों के निदेशकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	2	48
8.	कृषि विस्तार में "बाजार सकेंद्रण" को पहचानना - उत्पादन से आगे की सोच पर राष्ट्रीय कार्यशाला	1	36
9.	देसी कार्यक्रम के परिचालक निदेशसूत्रों पर स्टेकहोल्डरों का संवेदीकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला	1	26
10.	देसी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित इनपुट डीलरों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम	10	888
	कुल	**33**	**888**

4. कृषि संबंधित विस्तार का केंद्र

इस अवधि के दौरान निम्न विषयवस्तु पर 406 कार्यकारियों के लिए 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं 6 प्रारम्भिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	भागीदारों की संख्या
1.	मेघालय के लिए विस्तार प्रबंधन दृष्टिकोण	1	10
2.	कृषि एवं बागवानी विभागों में नव-नियुक्त कर्मियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	126
3.	पशुपालन/बागवानी क्षेत्र हेतु फार्म व्यापार प्रबंधन	3	68
4.	मत्स्यपालन की बढोत्तरी के लिए विस्तार प्रबंध अभिगम	1	25
5.	मेदक जिले के किसानों के लिए ग्रीन हाऊस उत्पादन तथा उसका रख-रखाव	1	59
6.	पशुपालन में क्षेत्र स्तरीय समस्याओं के समाधान करने के लिए विस्तार कर्मियों को सक्षम बनाने पर कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण	1	37
7.	रंगारेड्डी जिले के किसानों के लिए ग्रीन हाऊस उत्पाद तथा उसका रख रखाव	1	40
8.	तेलंगाना राज्य के पुनरीक्षित एस आर ई पी के प्रलेखन पर पूर्वीभिमुखिकरण कार्यक्रम	1	17
9.	पशुपालन विभग में नव-नियुक्त कर्मियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	24
	कुल	**15**	**406**

5. ज्ञान प्रबंधन, आई सी टी तथा मास मीडिया

इस केन्द्र के द्वारा तीन राष्ट्रीय कार्यशालाओं सहित कुल 48 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें 1075 अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	भागीदारों की संख्या
1.	कृषि विकास के लिए समुदाय रेडियो पर कार्यशाला	3	67
2.	कृषि ज्ञान प्रबंधन पर उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	165
3.	एम-किसान व ई एम एस पर प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	2	22
4.	कृषि सूचना एवं ज्ञान के प्रभावी आदान-प्रदान के लिए सोशल मीडिया	4	115
5.	संशोधित विस्तार सुधार में आईसीटी का अनुप्रयोग	6	194
6.	प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए लेखन	2	17
7.	कृषि विकास में रिमोट सेन्सिंग और जीआईएस	2	49
8.	माइक्रोसॉफ्ट परियोजना का प्रयोग करते हुए परियोजना एवं प्रबंधन	2	40
9.	कृषि में ई-शासन सुधार	2	58
10.	कृषि नवाचारों के लिए प्रक्रिया प्रलेखन	4	85
11.	कृषि विस्तार प्रबंधन में (आईसीटी)	2	52
12.	कृषि विस्तार तथा तकनीकी पर राष्ट्रीय मिशन के तहत आई सी टी का उपयोग	1	27
13.	सीसीकेएन-आईए पर राष्ट्रीय कार्यशाला	1	29
14.	कृषि में आईसीटी पर राष्ट्रीय कार्यशाला	1	42
15.	सामुदायिक रेडियो पर राष्ट्रीय कार्यशाला	1	17
16.	किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञों-स्तर - I और स्तर- II के लिए प्रशिक्षण-सह-पुनरीक्षा कार्यशाला	10	96
	कुल	**48**	**1075**

6. कृषि उद्यमीता, युवावर्ग और सरकारी निजी भागीदारिता

इस केन्द्र के द्वारा कुल 28 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 744 कार्यकारियों ने भाग लिया। विवरण निम्ननुसार है :

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	भागीदारों की संख्या
1.	कृषि विस्तार प्रबंध में सरकारी-निजी भागीदारी	2	42
2.	पी पी पी मोड़ पर कृषि व्यापर केन्द्रों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण युवाओं में कृषि उद्यमिता विकास पर पुनश्चर्या कार्यक्रम	1	13
3.	पी पी पी मोड़ पर कृषि व्यापर केन्द्रों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण युवाओं में कृषि उद्यमिता विकास पर पूर्वाभिमुखीकरण कार्यक्रम	1	32
4.	ए सी व ए बी सी के तहत एग्रिवेंचरों की स्थपना के लिए राष्ट्रीय निदानात्मक कार्यशाला	1	33
5.	महाराष्ट्र में ए सी व ए बी सी के क्रियान्वयन पर केरल अधिकारियों का शिक्षण-सह-दौरा कार्यक्रम	1	6
6.	ए सी व ए बी सी योजना के तहत राष्ट्र स्तरीय नोडल अधिकारी कार्यशाला	1	64
7.	ग्रामीण युवाओं के लिए उद्योग अभिमुख कृषि कौशल विकास	13	9
8.	ए सी व ए बी सी के तहत व्यापर विस्तार दक्षताओं पर स्थापित कृषि उद्यमियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम	19	491
9.	वेगनिन्जेन विश्वविद्यालय, नेदरलैंड्स तथा लिंडसे, यू एस ए के सहयोग से ए सी ए बी सी योजना के तहत जल प्रबंधन में उद्यमिता अवसरों पर स्थापित कृषि उद्यमियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	24
	कुल	**28**	**744**

7. महिला व घरेलु खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, शहरी कृषि तथा हरी सब्जियों की उपज का केंद्र

इस केन्द्र के द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यशाला सहित कुल 17 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 398 अधिकारियों ने भाग लिया। विवरण निम्ननुसार है :

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	भागीदारों की संख्या
1.	एन आई पी एच एम के सहयोग से ए सी व ए बी सी योजना के तहत नोडल प्रशिक्षण संस्थानों के विस्तार कर्मियों और संकाय के लिए पौध स्वास्थ्य प्रबंधन पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम	4	80
2.	शहरी कृषि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	27
3.	ग्रामीण परिवारों का खाद्य तथा पोषण सुरक्षा -महिलाओं की भूमिका	1	21
4.	विकास क्षेत्र में महिलाओं के लिए प्रबंध विकास कार्यक्रम	1	22
5.	कृषि में महिलाओं को मुख्यधारा में जोडने के लिए जेंडर बजटिंग	2	58
6.	जलवायु परिवर्तन और कृषि	2	26
7.	हैदराबाद वासियों के लिए छत पर/पिछवाडे में गार्डेनिंगपर प्रशिक्षण	2	82
8.	ग्रामीण परिवारों का खाद्य, पौषण तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दें-महिलाओं की भूमिका	1	23
9.	जेंडर बजेटिंग पर टीओटी- महिलाओं को मुख्यधारा में जोड़ना	1	14
10.	स्नातकोत्त्र कृषि विस्तार प्रबंध डिप्लोमा पर पुनावलोकन कार्यशाला	1	19
11.	देसी कार्यक्रम हेतु संवेदीकरण पर कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण	1	26
	कुल	**17**	**398**

8. कृषि संबंधि अध्ययन, लाभवंचित क्षेत्र, प्रकृतिक संसाधन प्रबंध विस्तार तथा सामाजिक जुटाव का केंद्र

इस केंद्र ने 18 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 603 भागीदारों ने भाग लिया। विवरण निम्ननुसार है :

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	भागीदारों की संख्या
1.	सततत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (एन एम एस ए) पर		
	कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण	4	111
2.	कृषक उत्पादक संगठनों का विकास और संपोषणीयता	4	142
3.	मत्स्यपालन विषय के विशेष संदर्भ में वर्षा आधारित		
	कृषि का पुनर्निर्माण	3	84
4.	पशुपालन विषय के विशेष संदर्भ्में वर्षा आधारित		
	कृषि का पुनर्निर्माण	2	64
5.	कृषि परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन	2	62
6.	वर्षा आधारित कृषि के उत्तम अभ्यासों के प्रलेखने पर राईट शॉप	1	61
7.	समेकित जलागाम प्रबंधन कार्यक्रम पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला	1	39
8.	किसान उत्पादक समूहों के लिए मुद्दों व चुनौतियों पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला	1	40
	कुल	**18**	**603**

3 अनुसंधान

3.1 मैनेज की अनुसंधान गतिविधियाँ समकालीन संगत विषयों पर ध्यान देती है। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों/परियोजनाओं का मूल्यांकन उनके प्रभावा का आकलन करने के लिए किया जाता है। क्षेत्रों स्थितियों में विचारों, संकल्पनाओं तथा तकनीकियों को पाइलेट टेस्ट कर के एक्शन रीसर्च भी किया जाता है। इसके अलावा कृषि एवं तत्संबंधी विभागों/एजेन्सियों के लिए उनके अनुरोध पर कार्यक्रमों व रणनीतियों के विकास हेतु परामर्शी सेवा भी प्रदान किया जाता है।

3.2 वर्ष 2015-16, के दौरान निम्नलिखित अध्ययन किए गए है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	टिप्पणी
1.	विस्तार सुधार योजना के तहत महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए किए गए मध्यस्ताओं का प्रभाव	पूर्ण हुआ है
2.	कन्सोर्टियम विधि में ग्रामीण युवा में कृषि उद्यमिता विकास	पूर्ण हुआ है
3.	कृषि के क्षेत्र में महिला उद्यमियें का विवेचनात्मक विश्लेषण	प्रगति पर है
4.	कृषि एवं तत्संबी विभागों के विस्तार कर्मियों के लिए ई-टी एन ए की रचना एवं विकास	प्रगति पर है
5.	कृषि विपणन के आधुनिक उपकरणों को अपनाने में विनियमन की भूमिका - एक तुलनात्मक अध्ययन	प्रगति पर है
6.	कृषि संबंधी क्षेत्रों मे विस्तार अभिगामों का विश्लेषण	प्रगति पर है

1. विस्तार सुधार योजना के तहत महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए किए गए मध्यस्ताओं का प्रभाव

यह अध्ययन महिला किसानों पर आत्मा के मध्यस्ताओं के प्रभाव का आकल करने के लिए किया गया है। राज्यों के भौतिक एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन के आधार पर, छः राज्यों का चयन किया गया है यथा: झारखण्ड, असम, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड महिला किसान हितकारियों का साक्षात्कार करने के लिए प्रत्येक राज्य के एक जिला एवं प्रत्येक जिले के तीन से छः खण्डों को चुना गया। यह अध्ययन पूर्ण हुआ और रिपोर्ट जुलाई 2015 में प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन के परिणाम : समस्याओं पर विचार करने के लिए जी बी और बी एफ ए सी स्तर पर महिला किसानों का उचित चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सिफारिश की जाती है कि बी एफ ए सी महिला प्रतिनिधियों का सही चयन कर उन्हें विस्तार सुधार योजना एवं उसके क्रियान्वयन में उनकी भूमिका पर पूर्वाभिमुखीकरण प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि, ये महिलाएं महिला समूहों को तैयार करने में सक्रिय भाग ले सके। उनकी आवश्यकताओं को पहचान सके, बैठकों में फीडबैंक दे सके तथा

कार्ययोजनाओं में महिला किसान आवश्यकताओं को सम्मिलित करने का अश्वासन करना तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए बजट का आबंटन हो सके।

इस अध्ययन ने विस्तार सुधार के तहत महिलाओं की समस्याओं को मुख्यधारा में लाने के लिए कई उत्तम अभ्यासों को एवं दृष्टिकोणों को पहचाना है। महिला किसान प्रतिनिधियों ने गाँवों के चयन में, हितकारी महिला किसान के पश्चात् समूहों को तैयार कर बढ़ाने में विस्तार क्रियाकलापों के आयोजन को सरल बनाने तथा पहचानी गयी समस्याओं के समाधान में पुनर्विवेशन प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाई है। प्रगतिशील महिला किसानों को कब प्रशिक्षकों के रूप में उपयोग किया है (किसान से किसान तक विस्तार संकल्पना के तहत) तब महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आदि में अन्य महिला किसानों तक सफल रूप से अंतरण में परिभाषित हुए है। महिला किसानों तक सफल उपयोगी कोनोवीडर, पैडी ड्रम सीडर, पामरे एक्सट्राक्टर, कोकोआ हार्वेस्टर सीड ट्रीटमेंट ड्रम, स्पाइरेल सोयाबीन सेपरेटर इत्यादि विभिन्न राज्यों में आत्मा के माध्यम से महिला/महिला समूहों को दिए गए है और महिला समूहों ने अनुभव किया है कि तकनीकियों ने उनके कठिन परिश्रम को कम किया है और समय को कम कर उनके दक्षता में विकास लाया है। यह सिफारिश किया गया है कि अधिक से अधिक महिलाओं किसानों को लाभ प्रदान करने हेतु इन तकनीकियों को लोकप्रिय बनाना है। अध्ययन में सामूहिक कार्य एवं सामूहिक विपणन कुछ महिला समूहों में किया जाता या जिससे समहिलाओं को लाभ हुआ है। यह सिफारिश किया जाता है कि इन उत्तम अभ्यासों को दृढ़ बनाकर अन्य राज्यों में भी इनका अनुसरण किया जाए।

2. कन्सोर्टियम विधि में ग्रामीण युवा में कृषि उद्यमिता विकास

मैनेज और सिंजेटा फाउन्डेशन इंडिया (एसएफआई) ने 'कृषि उद्यमिता विकास' नाम पर एक्शन रीसर्च कार्यक्रम के परिचालन हेतु समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। इस कार्यक्रम का मूख्य लक्ष्य किसानों को मूल्य जोड़ सेवाएं प्रदान करने योग्य एग्रिप्रेन्यूरों के रूप में ग्रामीण युवाओं को परिवर्तीत करना है। सिन्जेन्टा फाउन्डेशन इंडिया कन्सोर्रियम में प्रधान है, दक्षता निर्माण समर्थन मैनेज द्वारा प्रदान किया जाता है, एक परामर्शी सेवा फर्म "स्मार्ट स्टेप्स" हैण्ड होल्डिंग समर्थन देता है, आई डी बी आई बैंक एग्रिप्रेन्यूरों को ऋण सहायता देना है तथा प्रदान (पीआरएडीएएन) के माध्यम से उद्यम सेवा क्षेत्र के किसानों से जुड़े है। मैनज ने उचित उद्यम अवसरों को पहचानना सीखने के लिए (भागीदारों के सहायता करने प्रशिक्षण मॉड्यूल विकास किया है) सविवरण परियोजना रिपोर्ट, एग्रिप्रेन्यूरों एवं सभी संसाधनों के बीच संबंधों को जानना तथा छोटे उद्यमों की सततता तथा उनकी सफल स्थापना हेतु आवश्यक सेवाओं को प्रदान करना है।

कुल 29 एग्रिप्रेन्यूरों ने (महाराष्ट्र के 7, झारखण्ड के 9 मध्यप्रदेश के छः, आंध्र प्रदेश के 2, ओडिसा के 3 तथा पश्चिमबंगाल के 2) मैनेज द्वारा 28 अप्रैल से 7 मई, 2014 के दौरान प्रदान, मध्यप्रदेश में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है। 29 भागीदारों में से 22 आवेदकों ने एग्रिवेंचरों को एग्रि इनपुट शॉप, वेजिटेबुल नर्सरी, बीज उत्पादन सूनिट, कृषि परामर्शी सेवा इत्यादि क्षेत्रों में स्थापित किए है। एक्शन रीसर्च के द्वितीय चरण में सिंजेंटा फाउन्डेशन इंडिया तथा मैनेज ने संयुक्त रूप से 23 से 26 सितंबर, 2015 के दौरान बी सी टी - के वी के हरिपुरम, विशाखापट्नम, आंध्र पद्रेश में स्थापित एग्रिप्रेन्यूरों के लिए चार दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। इस एक्शन रीसर्च कार्यक्रम का प्रभाव महत्वपूर्ण प्रारंभिक कार्यो में

दिखाई दे रहा है। इनमें है: 13 आवेदकों के एग्रि वेंचर्स निम्न क्षेत्रों में स्थापित करने एग्रि इनपुट शॉप से निपटान, वेजिटबुल नर्सरी, बीज उत्पादन यूनिट इत्यादि के लिए, अपना व्यापार प्रारंभ करने एस एफ आई ने रू. 30,000/- प्रत्येक एग्रिप्रेन्यूर के लिए बीज राशि के रूप में प्रदान किया है। एस एफ आई ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ एग्रिप्रेन्यूरों को ऋण सहायता देने हेतु समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सभी एग्रिपेन्यूरों ने लाइसेन्स के लिए आवेदन किया है। उन्होंने अपने उत्पादनों को बेचने के लिए नामी कंपनियों से मुख्य प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया है। लगभग सभी एग्रिप्रेन्यूरों ने आई डी बी आई को शाखाओं के साथ बिजिनेस करस्पॉडेन्ट के रूप में पजीकृत हुए है। आई डी बी आई के साथ प्रत्येक एग्रिप्रेन्यूरों के अधीन कुल 150-200 किसान पंजीकृत हुए है और सभी पंजीकृत किसानों को किसान क्रेडिट कार्डस दिए गए है। किसानों के साथ किए जाने वाले प्रत्येक लेन देन पर एग्रिप्रेन्यूरों की 0.5 प्रतिशत कमिशन प्राप्त होता है। सभी एग्रिप्रेन्यूर थोक डिस्ट्रिब्यूटरों के साथ (एग्रि-इनपुट) जुड़े रहेंगे, जहाँ एग्रिप्रेन्यूर लगभग रू. 2-3 लाख की सामग्री क्रेडिट पर (एस एफ आई का गारंटी पर) प्राप्त करेंगे।

3. कृषि के क्षेत्र में महिला उद्यमियें का विवेचनात्मक विश्लेषण

इस अध्ययन का उद्देश्य सफल कहानियों को प्रलेखित करना तथा महिलाओं में कृषि के क्षेत्र में उद्यमों की सफलता के कामों का विश्लेषण करना, महिलाओं पर उद्यमिता का आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव का आकलन करना, महिलाओं में कृषि के क्षेत्र में उद्यमिता के आरंभ तथा सततता पर लिंग भेद आधारित कठिनाईयों का विश्लेषण तथा कृषि के क्षेत्र में महिलाओं में उद्यमिता कौशलों को बढाने तथा अनुसरण करने की रणनीति का सुझाव देना है। तीन राज्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्यों को चुना गया है। प्रत्येक राज्य से एक जिले को कृषि के क्षेत्र में महिला उद्यमियों का साक्षात्कार लेने के लिए चुना गया है। डाटा एन्ट्री और विश्लेषण पूरा हुआ है रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

4. कृषि एवं तत्संबी विभागों के विस्तार कर्मियों के लिए ई-टी एन ए की रचना एवं विकास

प्रशिक्षण आवाश्यकता का आकलन प्रशिक्षण का अंक आंतरिक भाग है जिसका लक्ष्य वे संगठनात्मक आवश्यकताएं होंगे जिन्हें व्यक्त किया गया है या पहचाना गया है और उनकी पूर्ती उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन से किया जाता है। प्रशिक्षण आवश्यकता का आकलन तीन चरणों की प्रक्रिया है जिसमें सूचना का संकलन, विश्लेषण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संरचना समाहित है। सर्वेक्षण विधि द्वारा प्रशिक्षण आवश्यकता का आकलन करने में उत्पन्न कठिनाइयों को (संरचना प्रश्नावली को भेजना पेपर और पेन्सिल विधि) ऑनलाईन विधि द्वारा दूर किया जा सकता हे। परम्परागत विधि से ऑनलाईन विधि में अंतरण के संभावित लाभ में व्यय में कमी, समय की भी कमी, जवाब देने वाले अपने कार्य स्थल से ही जवाब देना सरल होगा। व्यय की कमी, समय की बचत, प्रकृति (लचीली) तथा उपयोग करने में आसान प्रभावशाली जैसे लाभ को ध्यान रखते हुए चालू अनुसंधान अध्ययन का लक्ष्य ई-टी एन ए (ऑनलाईन प्रशिक्षण आवश्यकता का स्वतः आकलन) के लिए एक प्लैटफार्म का संरचना व विकास जिला स्तरीय कृषि अधिकारियों के लिए करना, अपने प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर कृषि अधिकारियें का स्व-अनुभूति तथा उनके स्वानुभूति की तीव्रता का आकलन तथा विभागाध्यक्षों की स्वानुभूति को पता लगाना, उच्च अधिकारियों द्वारा उनके अधीनस्तों की प्रशिक्षण आवाश्कताओं का पता लगाना। पुनरावलोकन अवधि के दौरान, कृषि विभाग में कार्यरत कर्मियों की प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन के लिए ऑनलाईन ई-टी एन ए प्रोफार्मा का पुनरावलोकन किया जाएगा।

5. कृषि विपणन के आधुनिक उपकरणों को अपनाने में विनियमन की भूमिका - एक तुलनात्मक अध्ययन।

इस अध्ययन का लक्ष्य कृषि के संपूर्ण विकास पर बाजार विनियम के प्रभाव का निर्धारण करना है। इस अध्ययन के उद्देश्य कर्नाटक एवं ओडिसा राज्यों में कृषि विपणन पर विनियम की स्तर का आकलन करना, फसल विधिकरण, निर्यात, प्रसंस्कारण, किसान आय तथा उत्तम विपणन अभ्यासों जैसे कारकों के साथ विनियमन की मात्रा के बीच संबंध का पता लगाना, कृषि विपणन के आधुनिक उपकरणों को अपनाने में राज्यों की तत्परता तथा विनियमन की मात्रा के बीच संबंध स्थापित करना तथा कृषि विपणन व्यवस्था में आधुनिक उपकरणों को अपनाने में आनेवाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सलाह देना है।

6. कृषि संबंधी क्षेत्रों मे विस्तार अभिगामों का विश्लेषण:

इस अध्ययन का उद्देश्य कृषि संबंधी विभागों के अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली विधियों एवं दृष्टिकोणों को जानना, विभिन्न विस्तार दृष्टिकोणों पर अधिकारियों के ज्ञान के स्तर का आकलन करना। विस्तार सेवा सुपुर्दगी की ओर किसानों के विचारों का पता लगाना, विस्तार दृष्टिकोणों को अपनाने में तथा विस्तार सेवाओं के अभिसरण में आने वाले अड़चनों को समझना तथा कृषि संबंधी क्षेत्रों में विस्तार सेवा सुझाव देना है।

4 योजनाएं

एग्रि क्लीनिक एवं एग्रि बिजिनेस केंद्र योजना (एसी व एबीसी)

4.1 विस्तार में गुणवत्तापूर्ण कर्मियों की कमी प्रभावी विस्तार सेवाओं को प्रदान करने में बहुत बड़ा अड़चन हैं। एक और समस्या यह है कि अधिक संख्यक कृषि व्यवसायी लाभदायक रोजगार भी प्राप्त नहीं कर पा रहे है। अतः, इन समस्याओं के समाधान के रूप में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2002 में एग्रि क्लीनिक एवं एग्रि बिजिनेस केंद्र योजना (एसी व एबीसी) का आरंभ किया।

श्री परीश्रित डी. बोकारे, कृषि उद्यमी, अहमदनगर महाराष्ट्र द्वारा "काटन क्राप" और "आई पी एम" पर विकसित ऐप

4.2 एसी व एबीसी योजना के उद्देश्य निम्नानुसार है:

(i) लक्ष्य निर्धारित किसान समूह के स्थानीय जरुरतों व सामर्थ्य, कृषि उद्यमी के व्यापार नमूनों के अनुसार मुफ्त/आदायगी के आधार पर किसानों को आवश्यक रूप से सरकारी विस्तार द्वारा प्रदान की जाने वाली विस्तार एवं अन्य सेवा प्रयासों का अनुपुरण करना

(ii) कृषि विकास को समर्थन प्रदान करना; तथा

(iii) बेरोजगार कृषि तथा संबंधित स्नातकों, कृषि डिप्लोमा धारकों, कृषि में पास हुए इंटरमीडियेट तथा जैव विज्ञान स्नातक सहित कृषि संबंधित पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर को स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना

महिला स्वयं सेवी सगठनों के लिये हैड्रोफोनिक कल्टिवेशन पर प्रशिक्षण देते हुये श्री अविनाश सालुंखे,एग्रिप्रेन्यूर,श्रीरामपुर,माहाराष्ट्र

4.3 मैनेज को प्रशिक्षणों के संचालन तथा योजना के तहत चुने गए कृषि व्यावसायिकों के हैंड होल्डिंग करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। मैनेज देश भर के 72 केंद्रक प्रशिक्षण संस्थानों (एन.टी.आई) द्वारा चयनित कृषि व्यावसायिकों को अपने अपने राज्य में कृषि उद्यमिता विकास हेतु 2 महीने का आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रशिक्षण के बाद कृषि उद्यम स्थापित करने हेतु एक वर्ष का एनटीआई से हेंडहोल्डिंग समर्थन प्राप्त होता है। प्रशिक्षित कृषि उद्यमियों को बैंकों एवं नाबार्ड द्वारा स्टार्ट अप ऋण तथा क्रेडिट लिंकेड बैक एंडेड कंपोसिट सब्सिडी की सहायता मिलती है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

4.4 राज्य कृषि विश्व विद्यालयों तथा केंद्र कृषि विश्व विद्यालयों/ आई सी ए आर/ यू जी सी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयों के कृषि एवं तत्संबंधी विषयों के स्नातक; राज्य कृषि विश्व विद्यालयों के कृषि एवं तत्संबंधी विषयों के डिप्लोमा धारक; कृषि एवं तत्संबंधी विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त जीव विज्ञान स्नातक तथा माध्यमिक शिक्षा स्तर पर कृषि से संबंधित पाठ्यक्रम पढे हुये आवेदक जिन्हे कम से कम 55% प्राप्त हो, वे इस योजना के तहत लाभ पाने के लायक होंगे ।

4.5 अभ्यर्थियों का चयन एक चयन प्रक्रिया द्वारा एन.टी.आई स्तर पर राज्य कृषि विकास, नाबार्ड, एन.टी.आई, मैनेज, के.वी.के, बैंक तथा कृषि व्यवसाय कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाता है।

4.6 प्रशिक्षण के दौरान आवेदकों को कृषि विस्तार एवं कृषि उद्यमिता पर आधारभूत ज्ञान प्रदान किया जाएगा, कृषि उद्योगों से परिचित कराया जाएगा, मार्केट सर्वेक्षण के आधार पर किसी परियोजना चयन में निर्देश दिया जाएगा तथा कार्य अनुभव हेतु हैंड्स-आन अवसर प्रदान किया जाएगा, ताकि वे बैंकों में प्रस्तुत करने हेतु सविवरण परियोजना रिपोर्ट तैयार कर सके। कृषि उद्यमों की सफल स्थापना के आश्वासन के लिए प्रशिक्षण के पश्चात एन टी आई के माध्यम से एक वर्ष का हैंड होल्डिंग समर्थन प्रदान किया जाएगा।

देसी कार्प मछली की सुरक्षा हेतु डा. जेहरूल इस्लाम, कृषि उद्यमी असम में एक मछली तालाब का निर्माण किया

4.7 रियायत प्रयोजन हेतु योजना के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना का मूल्य रु. 20.00 लाख है तथा 5 सदस्यों के समूह परियोजना का रु. 100.00 लाख है। सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए सब्सिडी कुल वित्तीय परिव्यय का 36% है, तथा महिला आवेदकों/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों तथा उत्तर पूर्वी पहाडी राज्यों के आवेदकों के लिए 44 प्रतिशत है। निर्धारित बैंकों से ऋण की सुविधा प्रदान की गई है तथा नाबार्ड के जरिए उधार लिंक की रियायत को जोडा गया है।

वर्ष 2015-16 के दौरान ए सी ए बी सी की प्रगति

4.8 इस वर्ष के दौरान 5258 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षिण 73 एन टी आई के माध्यम से किया गया है जिनमें से 2587 ने क्रिया कलापों के 28 वर्गों मे कृषि उद्यम स्थापित किए हैं, इस प्रकार प्राप्त सफलता का दर 49.22 प्रतिशत है। इन सबका विवरण निम्न प्रकार से हैः

किसानों को बागवानी में सुरक्षित फसलोपादन पर परमर्शी सेवा प्रदान करते हुए श्री हार्दिक रोकड़, कृषि उद्यमी, अमरेली, गुजरात

वर्ष 2015-16 के दौरान एसी एवं एबीसी योजना की प्रगति

क्र.सं.	राज्य	प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या	स्थापित कृषि उद्यमों की संख्या	एन.टी.आई. की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	22	33	2
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1
3	असम	69	11	1
4	बिहार	279	93	2
5	छत्तीसगढ	114	27	3
6	दिल्ली	10	0	0
7	गुजरात	154	41	2
8	हरियाणा	62	17	1
9	हिमाचल प्रदेश	1	0	0
10	जम्मु और कश्मीर	88	5	1
11	झारखंड	49	13	2
12	कर्नाटक	132	88	7
13	केरल	2	0	1
14	मध्य प्रदेश	209	106	5
15	महाराष्ट्र	1488	753	15
16	मणिपुर	24	3	1
17	मेघालय	1	0	0
18	नागालैंड	0	0	1
19	उडीसा	15	0	1
20	पॉण्डीचेरी	23	9	1
21	पंजाब	35	17	1
22	राजस्थान	212	93	3
23	सिक्किम	0	1	1
24	तमिलनाडु	806	426	6
25	तेलंगाना	58	9	3
26	उत्तर प्रदेश	1197	743	8
27	उत्तरांचल	43	40	1
28	पश्चिम बंगाल	165	59	3
	कुल	**5258**	**2587**	**73**

वर्ष 2015-16 के दौरान स्थापित कृषि उद्योगों का गतिविधी-वार वर्गीकरण

क्र.सं.	कृषि-उद्यम	संख्या
1.	एग्री-क्लीनिक	444
2.	एग्री-क्लीनिक एवं एग्री-बिजनेस केंद्र	462
3.	पशु फीड यूनिट	2
4.	जैव-उर्वरता उत्पादन तथा विपणन	4
5.	संविदा कृषि (कान्ट्राक्ट फार्मिंग)	1
6.	औषधि पौधों की खेती	1
7.	कृषि यंत्र इकाई	133
8.	मत्स्य विकास	37
9.	पुष्प कृषि	10
10.	बागवानी निदान	32
11.	लैंडस्केपिंग + पौधशाला	2
12.	पौधशालाएं	50
13.	जैविक उत्पादन/ खाद्य श्रंखला	1
14.	कीटनाशक उत्पादन तथा विपणन	5
15.	मूल्य जोड़ (वेल्यू एडिशन)	20
16.	मत्स्य अस्पताल	1
17.	बीज प्रसंस्करण तथा विपणन	18
18.	मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं	1
19.	सब्जी उत्पादन तथा विपणन	50
20.	वर्मी कम्पोस्टिंग/जैविक खाद	12
21.	पशु-पालन चिकित्सा	27
22.	कृषि उत्पादन	6
23.	दुग्ध/कुक्कट/सूकर/बकरी इकाई आदि	1227
24.	ग्रामीण गोदाम	2
25.	उत्पादन एवं जैव नियंत्रण मार्केटिंग एजेंट	4
26.	कोशकीट-पालन	6
27.	कुक्करमुत्ता खेती	16
28.	मधुमक्खी पालन	13
	कुल	**2587**

2002-2015 के दौरान प्रगति

4.9 प्रारम्भ से लेकर 31 मार्च 2016 तक, कुल 47,815 आवेदक प्रशिक्षित हुये तथा 20,450 कृषि उद्यम स्थापित किए गए, जिसकी सफलता का दर 42.76% है। विवरण निम्नानुसार है:

2002-2016 के दौरान एग्रि क्लीनिक्स एवं एग्रि बीजिनेस केंद्र योजना की प्रगति

क्र.सं.	राज्य	प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या	स्थापित कृषि उद्यमों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	846	317
2	अरुणाचल प्रदेश	32	3
3	असम	632	206
4	बिहार	3422	1246
5	चंडीगढ़	3	1
6	छत्तीसगढ़	543	253
7	दिल्ली	26	3
8	गोवा	9	4
9	गुजरात	1366	515
10	हरियाणा	614	205
11	हिमाचल प्रदेश	418	108
12	जम्मु और कश्मीर	1333	176
13	झारखंड	632	162
14	कर्नाटक	3102	1295
15	केरल	184	51
16	मध्य प्रदेश	1399	576
17	महाराष्ट्र	10994	5178
18	मणिपुर	437	128
19	मेघालय	11	3
20	मिजोरम	34	0
21	नागालैंड	174	21
22	उडीसा	521	106
23	पॉण्डीचेरी	124	77
24	पंजाब	566	203
25	राजस्थान	2764	1012
26	सिक्किम	9	1
27	तमिलनाडु	5493	2914
28	तेलंगाना	1007	362
29	त्रिपुरा	2	1
30	उत्तर प्रदेश	9883	4929
31	उत्तरांचल	414	138
32	पश्चिम बंगाल	821	256
	कुल	**47815**	**20450**

श्री चिन्ना जलाकी, कृषि उद्यमी हुबली, कर्नाटक के दिशानिर्देश के तहत श्री बसवेश्वर सौहार्द सहकारी नियमिता ने परिणाम प्रदर्शन किया

जम्मू और कश्मीर में योजना की प्रगति

4.10 इस वर्ष के दौरान 88 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया तथा उनमें से 5 ने कृषि उद्यमों को जम्मू कश्मीर के तीन एन टी आई की सहायता से स्थापित किया है। आरंभ से 1333 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया तथा 176 ने कृषि उद्यम स्थापित किया।

उत्तर-पूर्व राज्यों में योजना की प्रगति

4.11 योजना के अंतर्गत उत्तर पूर्वी राज्यों में सात प्रशिक्षण केंद्र कृषि व्यवसायिकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस वर्ष के दौरान 94 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से 14 अभ्यर्थियों ने कृषि उद्यमों को स्थापित किया है। योजना के आरंभ से कुल 1331 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से 363 ने कृषि उद्यमों को स्थापित किया।

एग्रिप्रेन्यूर ई-बुलेटिन का प्रकाशन:-

4.12 लागत प्रभावी ढ़ंग से अधिक संख्या में स्टेकहोल्डरों तक पहुँचने के लिए मैनेज एग्रिप्रेन्यूर - एक मासिक ई बुलेटिन का प्रकाशन कर रहा है। वर्ष 2015-16 के दौरान बुलेटिन के 12 अंक प्रकाशित हुए है और उन्हें विश्व भर में 18,091 पाठकों तक पहुँचाया गया है। इस ई-बुलेटिन को हिन्दी में भी कृषि उद्यमी के नाम पर प्रकाशित किया जा रहा है। एग्रिप्रेन्यूर ई-बुलेटिन का वेब साईट www.agriclinics.net पर उपलब्ध है।

4.13 एग्रिप्रेन्यूर के लिए समर्पित वेबसाइट

योजना के सभी स्टेकहोल्डरों के हित में मैनेज यिमित रूप से विशेष रूप से तैयार की गई वेब साईट www.agriclinics.net का नवीकरण करता है। यह वेब साईट यथा स्थिति विवरण प्रशिक्षण एग्रिप्रेन्यूर स्थापित उद्यम राज्य एवं जिलानुसार वर्गीकरण, निलंबित परियोजनाएं ई बुलेटिन, नवीनतम सरकारी आदेश तथा योजना संबंधी सभी जानकारी पणधारियों को प्रदान करती है।

एग्रिप्रेन्यूरों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन

एग्रिप्रेन्यूरों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन

4.14 एग्रिप्रेन्यूरों की आवश्यकताओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए तथा ए सी ए बी सी योजना के सभी स्टेकहोल्डरों को प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी लाने हेतु मैनेज ने अक्तूबर 2013 से एक टॉल फ्री हेल्प लाईन नंबर 1800-425-1556 को आरंभ किया।

कॉल करने वालों को हेल्पलाईन योग्यता,

1. राज्य में एन टी आई, ऋण, सब्सिडी, पुनश्चर्या कार्यक्रम तथा योजना से संबंधित अन्य मुद्दों पर सहायता एवं सूचना प्रदान करता है।
2. कॉल सेंटर प्रशिक्षण एवं हैण्ड होल्डिंग पर प्रतिपुष्ठि एवं सुझावों को भी प्राप्त करता है तथा कृषि उद्यमियों एवं एग्रिप्रेन्यूरों के संपर्क विवरणों को नवीकृत करता है।
3. ऋण, सब्सिडी
4. पुनश्चर्या कार्यक्रम

कॉल सेंटर प्रशिक्षण एवं हैण्ड होल्डिंग पर प्रतिपुष्ठि एवं सुझावों को भी प्राप्त करता है तथा कृषि उद्यमियों एवं एग्रिप्रेन्यूरों के संपर्क विवरणों को नवीकृत करता है।

राष्ट्रीय संस्थानों में पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम

4.15 वर्ष 2015-16 के दौरान मैनेज ने देश भर के 513 स्थापित कृषि उद्यमियों के लिए 20 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRDPR), हैदराबाद राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान (NIPHM), हैदराबाद स्टेट बैंक ग्रामीण विकास संस्थान (SBIRD), हैदराबाद राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल विस्तार शिक्षा संस्थान जोरहाट तथा दीप नाराण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (DNSRICM), पटना में आयोजित किए गए है। प्रशिक्षण की केंद्र बिन्दु पुनरावलोकित ए सी ए बी सी निदेशसूत्र पर जानकारी प्रदान करना। एग्रिप्रेन्यूरों के बीच बिजिनेस तंत्र स्थापित करना तथा कृषि उद्यमियों के नयी/परिवर्तित/वृद्धि हुई व्यापारिक कार्यक्रलापों के लिए बैंक ऋण योग्य परियोजनाएं तैयार करने के साथ-साथ विशेष क्षेत्र सम्मिलित है।

राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, करनाल, हर्यायाणा में आयोजित पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम

ए सी ए बी सी के तहत राष्ट्र स्तरीय नोडल अधिकारी कार्यशाला

4.16 इस वर्ष के दौरान मैनेज ने 21 से 22 दिसंबर, 2015 के दौरान राष्ट्र स्तरीय नोडल अधिकारी कार्यशाला को मैनेज, हैदराबाद में एन टी आई के प्रशिक्षण संयोजकों तथा नोडल अधिकारियों के लिए आयोजित किया था। कार्यशाला में विशेष रूप से एन टी आई के नोडल अधिकारियों के कार्यनिष्पादन का पुनरावलोकन, एन टी आई के फीडबैक के आधार पर ए सी ए बी सी योजना का सुदृढ़ीकरण, स्टेकहोल्डरों जैसे डी ए सी, मैनेज, बैंक, नाबार्ड, एन टी आई एग्रिप्रेन्यूरों के बीच प्रभावी सहयोग जिससे कि किसानों को दीर्घकालीन विस्तार सेवा प्रदान करने हेतु योजना के नियमों का सुधार और रूपरेरखा को पुन: तैयार कर सके।

4.17 ए सी बी सी योजना के तहत कृषि उद्यमों की स्थापना हेतु राष्ट्र स्तरीय निदानात्मक कार्यशाला।

ए सी ए बी सी योजना के तहत कृषि उद्यमों की स्थापना हेतु एक राष्ट्र स्तरीय निदानात्मक कार्यशाला का आयोजन 11 दिसंबर, २०१५ को किया गया ताकि प्रशिक्षित कृषि उद्यमीयों द्वारा कृषि उद्यम स्थापित नहीं करने के पीछे के कारणों को समझ सके। इस कार्यशाला में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,नाबार्ड के प्रतिनिधि तथा नोडल अधिकारी एवं असफल कृषि उद्यमियों ने भाग लिया। कार्यशाला में कृषि उद्यमों की असफलता का गंभीर रूप से परीक्षण किया तथा एक कार्य योजना तैयार किए है।

अध्ययन-सह-जानकारी दौरे

4.18 केरल समेति (SAMETI) ने मैनेज को ए सी ए बी सी योजना के भाग के रूप में एन टी आई बनने की ओर रूचि दिखाया। उस राज्य में ए सी ए बी सी योजना को दृढ़ बनाने के कदम के रूप में मैनेज ने केरल के छ: राज्य कृषि अधिकारियों को 16 से 21 फरवरी, 2016 के दौरान महाराष्ट्र का दौरा करवाया ताकि वे ए सी ए बी सी योजना की क्षेत्र स्तरीय समस्याओं सहित विभिन्न संघटकों को जान सकें। इस दौरान अधिकारियों ने महाराष्ट्र के विभिनन एन टी आई के नोडल अधिकारियों से बातचीत की और उनके अनुभवों से इस योजना के सफल आयोजन करने को सीखा। अधिकारियों ने पूणे के आस-पास के सफल एग्रिप्रेन्यूरों से भी मिले और योजना के उद्देश्य एवं कार्य विधि के बारे में जानकारी प्राप्त किया साथ ही आत्मा (ATMA) के अधिकारियों से भी मिले। यह दौरा केरल में योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार करने से पूर्ण हुआ।

भारत अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में प्रतिभागिता

4.19 मैनेज तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा फेसिलिटेटेड, 14 नवंबर, 2015 को नई दिल्ली में संपन्न आई आई एफ टी एफ में सात राज्यों के एग्रिप्रेन्यूरों ने भाग लिया। जिस्का उद्देश्य कृषि उद्यमिता एवं कृषि विकास में उस्की भूमिकाकी क्षमता के बारे में विभिन्न पणा धारियों में जागरूकता लाना है।

कृषि उन्न्ति- 2015 में प्रतिभागिता

4.20 मैंनेज तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फेसिलिटेटेड, दिल्ली में आयोजित कृषि उन्न्ती - 2-15 में चार राज्यो के चार कृषि उद्यमियों ने भाग लिया।

कृषि उद्यमियों को प्राप्त पुरस्कार

4.21 वर्ष 2015-16 के दौरान अपने उत्तम कार्यों के लिये पुरस्कार प्राप्त कृषि उद्यमी

शेतकरी पुरस्कार

Winner
₹ 1,50,000

किसान कॉल सेंटर

4.22 भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग ने 2004 में देश भर के किसान समुदाय द्वारा उठाए गाय मुद्दों का समाधान क्षेत्रीय भाषाओं में देने के लिए किसान कॉल सेंटर को आरंभ किया। इन केंद्रों के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों को राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा संबंधित राज्य विभागों के विषय विशेषज्ञों द्वारा समाधान किया जाता है। आज तक इस प्रकार के 25 केंद्र देश भर के विभिन्न राज्यों में कार्यरत हैं।

परिचालन तंत्र

4.23 केसीसी तीन स्तरों पर परिचालन करता है जैसे - स्तर -I स्तर -II तथा स्तर -III। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए किसान को टोल फ्री नं. 1551 (लैंड लाइन से) या 1800-180-1551 (मोबाइल से) को डायल करना होता है। राज्य के कॉल सेंटरों में किसानों द्वारा स्तर -I, में दर्ज किया जाता है,जो किसानों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए मुख्य जानकारी को दर्ज/रिकॉर्ड कर लेता है।

4.24 यदि स्तर -I प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है तो फसल प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों को राज्य कृषि विश्वविद्यालय/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विषय विशेषज्ञों को पहुँचाया जाता है, जो उनसे संबंधित राज्य के कृषि, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, विपणन आदि विभागों के कार्यक्रमों/योजना ओं में कार्य कर रहे स्तर-II तकनीकी अधिकारी होंगे ।

4.25 यदि स्तर -II भी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता है तो इसे स्तर -III को पहुँचाया जाता है जो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग की संबंधित राज्य में एक संस्था है जिसके माध्यम से किसानों के प्रश्नों के उत्तर 72 घंटों में पहुँचाया जाता है।

मैनेज की भूमिका तथा मध्यस्थता

4.26 मैनेज, किसान कॉल सेंटर के कार्य में जुटी कृषि एवं सहकारिता विभाग के स्तर-III की एक संस्था के रुप में कार्य कर रहा है। के सी सी - हैदराबाद में स्तर -I तथा स्तर -II के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है।

वर्ष 2015-16 में किसानों के कॉलों का विवरण

4.27 के सी सी - हैदराबाद में प्राप्त कॉलों का विवरण निम्न प्रकार से हैः

क्र.सं.	2015-16**		
	महीना	कॉल	उत्तर कॉल
1	अप्रैल, 2015	31494	26644
2	मई, 2015	27546	24481
3	जून, 2015	38935	31888
4	जुलाई, 2015	44825	36262
5	अगस्त, 2015	51498	31399
6	सितम्बर, 2015	59431	28526
7	अक्तूबर, 2015	53171	30575
8	नवम्बर, 2015	60996	28957
9	दिसम्बर, 2015	41362	26458
10	जनवरी, 2016	38186	28609
11	फरवरी, 2016	28887	24700
12	मार्च, 2016	20684	18940
	कुल	**497015**	**337439**
	मासिक	**41418**	**28120**
	दैनिक	**1380**	**937**

** स्रोत: http://dackkms.gov.in/KKMS/homepage.do

प्रशिक्षण कार्यक्रम

4.28 इस अवधि के दौरान नौ एक दिवसीय प्रशिक्षण -सह - पुनरावलोकन कार्यशालाओं का आयोजन के सी सी-हैदराबाद के स्तर - I और स्तर-II के अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया। इन्हें मैनेज और राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान (NIPHM), में आयोजित किया गया है। विवरण निम्न तालिका में है। क्षेत्र स्तर की समस्याओं पर विचार विमर्श करने एवं समाधान प्राप्त करने चार अवसरों पर के सी सी कर्मियों एवं जिला स्तरीय कृषि अधिकारियों के बीच मैनेज ने विडियो आधारित पार्स्परिक चर्चा को आयोजित किया है।

प्रशि.सं.	आयोजित दिनांक	स्थान	प्रतिभागी सं.
1	मई 12, 2015	मैनेज, हैदराबाद	08
2	जून 29, 2015	मैनेज, हैदराबाद	08
3	अगस्त 19, 2015	मैनेज, हैदराबाद	07
4	सितम्बर 21, 2015	मैनेज, हैदराबाद	08
5	नवम्बर 03, 2015	मैनेज, हैदराबाद	10
6	दिसम्बर 11, 2015	एनआईपीएचएम, हैदराबाद	12
7	दिसम्बर 15, 2015	एनआईपीएचएम, हैदराबाद	11
8	मार्च 15, 2016	एनआईपीएचएम, हैदराबाद	12
9	मार्च 16, 2016	एनआईपीएचएम, हैदराबाद	13

इनपूट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवा डिप्लोमा (देसी)

4.29 मैनेज ने वर्ष 2003 में एक वर्षीय इनपूट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवा डिप्लोमा को प्रारंभ किया ताकि सम्बद्ध कृषि ज्ञान प्रदान कर सके, जो इनपुट डीलरों को पारा-एक्सटेन्शन प्रोफेशनल के रुप में परिवर्तित कर सके, जिससे वे कृषकों के क्षेत्रस्तरीय समस्याओं का समाधान कर सके।

4.30 कार्यक्रम के उद्देश्यः

स्थान विशिष्ट फसल उत्पादन टैकनोलॉजी पर इनपुट डीलरों का ओरिएंटेशन।

निवेशों के प्रभावी रखरखाव में निवेश डीलरों का क्षमता निर्माण।

कृषि निवेशों के विनियामक नियमों की जानकारी प्रदान करना ।

किसानों कें लिए गाँव स्तर पर (एक स्टॉप शॉप) कृषि सूचना के लिए निवेश डीलरों को प्रभावी स्रोत के रूप में तैयार करना।

कार्यप्रणाली

4.31 यह कार्यक्रम जिला स्तर पर कॉन्टैक्ट क्लास-सह-दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के आधार पर क्षेत्रीय दौरों के साथ आयोजित किया जा रहा है। देसी (**DAESI**) कार्यक्रम को इस प्रकार बनाया गया है कि इनपुट डीलर अपने दैनिक व्यापार में अड़चन लाए बिना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता हैा यह कार्यक्रम 48 सप्ताहों में बाँटा गया है, जो 40 कक्षागत सत्र एवं विभिनन संस्थानों एवं फार्मर फील्ड के लिए 8 क्षेत्रीय दौरों का आयोजन किया जाता है। कक्षागत सत्र और क्षेत्र दौरों को रविवार और स्थानीय बाजार के छुट्टियों के दिन आयोजित किए जाते है। क्षेत्र दौरों का आयोजन स्थान विशेष के कृषि समस्याओं तथा संबंद्ध तकनीकियों से अवगत कराने के लिए आयोजित किए जाते है। उन्हें कीटों की पहचान, तथा पौष्टिकता संबंधी कमियों को पहचानने में प्रशिक्षण दिया जाता है। पाठ्यसामग्री स्थानीय भाषा में दिया जाता है और कक्षाओं में मल्टीमीडिया उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

क्षेत्र दौरे पर इनपुट डीलर

मूल्यांकन

4.32 प्रत्येक निवेश डीलर का मूल्यांकन द्विमासिक प्रश्नमच, अर्ध वार्षिकएवं वार्षिक परीक्षा तथा अंतिम प्रयोग परीक्षा में कौशल प्रदर्शन,नाश कीटों के नमूनों की पहचान, रोग और पौष्टिक कमियों के बाद वाइवा के आधार पर किया जाता है। डिप्लोमा को प्राप्त करने के लिए आवेदक की उपस्थिति कम से कम 80 प्रतिशत और 40 प्रतिशत नम्बर होने चाहिए।

पाठ्यक्रम शुल्क

4.33 पाठ्यक्रम का आयोजन स्ववित्तपोषण के आधार पर रु. 20,000/- शुल्क नामित इनपुट डीलरों से लेकर किया जाता है। तथापि, ओडिसा और तमिलनाडु के राज्यों ने आर के वी वाई निधि का भाग देसी कार्यक्रम संचालन के लिए उपयोग कर रहा है। इस कार्यक्रम की महत्व को पहचानते हुए भारत सरकार ने देसी कार्यक्रम को 15 अक्तूबर, 2015 केन्द्र क्षेत्र नियोजन योजना के रूप में बना दिया है, जहाँ पाठ्यक्रम शुल्क को रू.10.000 की सीमा तक प्रत्येक इनपुट डीलर के लिए सबिसडी दिया जाएगा।

4.34 समेतियों (**SAMETIS**) की सहायता से मैनेज इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है। समेति जिला स्तर पर नोडल प्रशिक्षण संस्थानों जैसे कृषि महाविद्यालयों, के वी के, आत्मा (**ATMA**) तथा एन जी ओ के मध्यम से कार्यक्रम को आयोजित करता है।

वर्ष 2015-16 के दौरान की गयी प्रगति

4.35 वर्ष 2015-16 के दौरान, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना राज्य, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आयोजित 16 बैचों में, देसी (डीएईएसआई) कार्यक्रम में कुल 586 निवेशकों ने भाग लिया।

4.36 इसके अतिरिक्त वर्तमान में 26 बैचों में कुल 1095 इनपुट डीलर देसी प्रशिक्षण ले रहे हैं जिसका निधीयन समर्थन केन्द्रीय क्षेत्र योजना के माध्यम से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक राज्य कर रहे है। 50 प्रतिशत पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में भारत सरकार के हिस्से के रूप में केन्द्रीय नियोजन योजना के तहत देसी कार्यक्रम के 26 बैचों को चलाने हेतु इन आठों राज्यों को रू. 99.26. लाख की राशी मंजूर की गयी है।

4.37 देसी की प्रगति एवं सुदृढीकरण

नए निर्देश सूत्रों के अनुसार देसी कार्यान्वयन पर जानकारी प्रदान करने के लिए स्टेकहोल्डरों हेतु 1.12.2015 को मैनेज में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें कृषि विभाग, समेतियों, आत्मा के वरिष्ठ अधिकारियों, एन टी आई/एन जी ओ के प्रतिनिधि और देसी के फेसिलिटटरों ने भाग लिया।

समेति गुजरात में 11.01.2016 को एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा कृषि विभाग, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा समेति के प्रतिनिधियों को देसी के नए निर्देश सूत्रों पर पूर्वाभिमुखीकरण किया गया।

देसी के परिचालन हेतु दिवसीय पूर्वाभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम नोडल अधिकारी/संचालक तथा विभिन्न राज्यों के पहचाने गए फेसिलिटेटरों के लिए 13 से 14 फरवरी, 2016 के दौरान मैनेज में आयोजित किया गया।

के वी के कार्यक्रम संचालकों, आत्मा अधिकारियों, समेति तथा तेलंगाना राज्य के कृषि विभाग के अधिकारियों के लिए 9/3/2016 को मैनेज में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

229 इनपूट डीलरों के लिए एन आई पी एच एम के सहयोग में देसी के तहत वर्ष 2015-16 के दौरान दो दिन की अवधि के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम 10 बैचों में आयोजित किया गया।

रू.2.45 करोड की राशि वर्ष 2016-17 के लिए देसी कार्यक्रम के लिए आबंटित किया गया है तदनुसार 16 राज्यों के लिए 12 बैच दिए गए।

ग्रमाणी युवाओं का कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई) और कृषिकों की क्षमता का आंकलन और प्रमाणीकरण (एफसीएसी)

4.38 ग्रामीण युवाओं का कोशल विकास भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्ययोगिकी मिशन (एनएमएईआी) के कृषि विस्तार के उप-मिशन (एसएएई) के अंतर्गत 2015-16 और 12वीं योजना की बाकी अवधि में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति, 2015 के अनुपालन में कौशल विकास के घटकों जैसे ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई), कृषकों की क्षतमा का आंकलन और प्रमाणीकरण (एफसीएसी) को लागू करवाने की पहल की है।

4.39 ग्रामीण युवाओं का कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई) का लक्ष्य कृषि और गैर-कृषि कार्यो के लिए कुशल कामगारों को तैयार करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कृषि और उसके संबंधित क्षेत्रों में कृषि-आधारित व्यावसायकि पाठ्यक्रमों में ग्रामीण युवाओं को कौशल-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना है। 18 वर्ष ओर उसके ऊपर के ग्रामीण युवा जिनकी न्यूनतम अहर्ता 5वीं पास है (अनिवार्य नहीं हैं) उनको कौशल प्रशिक्षण के योग्य माना जाएगा। भारत सरकार ने कृषि, बागवानी, पशु-पालन, डेरी और मत्स्यपालन जैसे 50 कौशल क्षेत्रों के विस्तार का चुनाव किया है।

4.40 कृषक क्षमता का आंकन और प्रमाणीकरण (एफसीएसी) का लक्ष्य है उन कृषकों को मान्यता प्राप्त करवाना जिन्होंने कृषि और संबंधित क्षेत्रों में आवश्यक कौशल प्राप्त कर लिया है फिर भी उन्हें प्रमाण पत्र के अभाव में अकुशल माना जाता है। 18 वर्ष और उसके ऊपर के कृषक जिनकी न्यूनतम अहर्ता 5वीं पास है (अनिवार्य नहीं है) उन्हें आंकलन और प्रमाणीकरण के योग्य माना जाएगा।

4.41 मैनेज को यह योजना नवम्बर, 2015 में चुने गए 10 राज्यों में 2015-16 और 2016-17 के दौरान लागू करवाने के लिए सौपी गयी है। मैनेज ने चुने गए 10 राज्योंके एस ए एम ई टी आई के निदेशकों को दिनांक 11.01.2016 के पत्र द्वारा संबोधित करते हुए कहा है कि मैनेज को सूचित किया जाए की 31.03.2016 से पहले कितने कौशल विकास कार्यक्रम और एस टी आर वाई और एफ़ सी एसी आयोजित किए जा सकते हैं। मैनेज के पत्र की प्रतिक्रिया में चुने गए दस में से पाँच राज्यों से उत्तर प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश,मणिपुर और मिज़ोरम ने कार्यक्रमों के आयोजन की प्रतिक्रिया दी है और तदनुसार फ़रवरी और मार्च 2016 में इन राज्यों के लिए निधि भी आवंटित की जा चुकी है। निधि के संशोधित आवंटन के आधार पर, मंत्रालय ने एस टी आर वाई को रु.32.76 लाख और एफ़ सी ए सी को रु.17.2 4 लाख आवंटित किए है। पाँच राज्यों को दी गयी निधि का विवरण नीचे दिया गया है।

5 प्रबंध शिक्षा कार्यक्रम

स्नातकोत्तर प्रबंध डिप्लोमा (कृषि व्यापार प्रबंध) पीजीडीएम (एबीएम)

प्रारंभ

5.1 आर्थिक सुधारों नें अर्थ व्यवस्था में ढांचे गत परिणाम लाया है जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि परिदृश्य में भी काफी परिवर्तन आया है। कृषि का रुप जीवन निर्वाह से वाणिज्यिक बनने की ओर बदल गया है। परिणामतः कृषि व्यापार के क्षेत्र में कई अवसर जैसे मूल्य जोड़, पैकेजिंग एवं तकनीक के उच्चस्तर के साथ कृषि उत्पादनों का निर्यात आदि उत्पन्न हुए हैं। आगे,वैश्वीकरण के नियमों के कारण कई उत्तम अवसर प्राप्त होने के साथ-साथ कई चुनौतियों को भी सामने रखा है। इन कारणों ने तथा परिवर्तन की अन्य सहगामी शक्तियों ने एग्रि बिजिनेस के क्षेत्र में प्रबंधकीय कौशल की मांग की।

5.2 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एग्रि बीजिनेस्स क्षेत्र में अत्यंत क्षमता है। इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए दक्ष (तकनीकी प्रबंधकीय) मानवशक्ति की अत्यंत आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैनेज ने दो वर्षीय पूर्ण कालिक, आवासीय स्नातकोत्तर प्रबंध डिप्लोमा (कृषि व्यापार प्रबंध) को वर्ष 1996 में स्व-वित्तीयन आधार पर प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की मान्यता प्राप्त हुई है।

उद्देश्य

5.3 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि, खाद्यान्न, कृषि बैंकिंग तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में केरियर के लिए कृषि व्यापार नेताओं एवं टेक्नो-प्रबंधकों को तैयार करना है।

कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- एग्री-व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त विषय का विकास करना ताकि युवा व्यवसायिकों को सक्षम प्रबंधकों के रुप में तैयार कर सकें।
- एग्रि बिजिनेस क्षेत्र में प्रबंधकीय निर्णायन हेतु एग्री-व्यापार क्षेत्रों का पर्याप्त जानकारी, कौशल तथा उचित व्यवहार प्रदान करना ।
- कृषि में बदलाव लाने के लिए उन्हें प्रभावी उद्यमकर्ता के रुप में तैयार करना।

प्रवेश प्रक्रिया

5.4 मैनेज ने आवेदकों की संक्षिप्त सूची तैयार करने तथा उनके चयन हेतु कैट (सीएटी) स्कोर, सामूहिक विचार-विमर्श, प्रपत्र लेखन, एक्सटेम्पोर /माइक्रो प्रजन्टेशन, कार्यानुभव, अकादमिक अभिलेखों तथा वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर उद्देश्य आधारित मापदण्ड को अपनाया है।

कार्यक्रम डिजाईन

5.5 कृषि व्यापार क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरुप इस कार्यक्रम की रुपरेखा को तैयार किया गया है जिसे 116 क्रेडिटों के साथ VII तिमाहियों में बाँटा गया है। इस कार्यक्रम के 43 विषयों को व्यापक रुप से आधारभूत, फ़ंक्शनल, सेक्टोरल तथा सामान्य पाठ्यक्रमों के रुप में बाँटा गया है। इस पाठ्यक्रम में एग्रि-इनपुट मार्केटिंग, कृषि निर्यात, प्रबंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रोक्यूरमेंट प्रबंधन, सप्लाई-चेन मैनेजमेंट, ग्रामीण विज्ञापन तथा संचार, कमोडिटी फ्यूचर्स तथा व्यापार, भागीदारी विस्तार प्रबंध, कृषि के लिए क्वांटीटेटिव एड्स, खाद्य फुटकर, सूक्ष्म वित्त, ग्रामीण साख, कृषि-वित्त तथा बैंकिंग इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

सम्मर इंटर्नशिप

5.6 छात्रों को प्रायोगिक क्षेत्र स्तरीय अनुभव प्रदान करने हेतु चौथी तिमाही सम्मर इंटर्नशिप के लिए रखा गया है। जिसके दौरान छात्र कृषि व्यापार-कंपनियों द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करना तथा उन्हें क्षेत्रगत प्रबंधकीय कौशलों में दक्ष बनाना है। परिस्थितियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कराकर ग्रीष्म परियोजनाओं जिसके 10 क्रेडिट हैंऔर सौ अंकों के लिए होता है, का मूल्यांकन इंटर्नशिप प्रदान करने वाली कंपनी के निरीक्षक या किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है। 2015-17 बैच के सभी छात्र सम्मर इंटर्नशिप के लिए चुने गए है।

5.7 छात्रों को अपने यहाँ इंटर्नशिप प्रस्तावित करने वाली कंपनियाँ हैं- 'भारत कीटनाशक लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, डाउ ऐग्रोसाइंस इं.प्रा.लि.,ग्रामको इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, एच डी एफ सी बैंक, आई सी आर आई एस ए टी, आई टी सी-एबीडी, लाइट माइक्रो फाइनेंस, मार्स इंटरनेशनल इंडिया प्रा.लि मि टेड, मोरडरइंटेलिजेंस, नागार्जुन ग्रुप, एन सी डी ई एक्स, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, पीआई इंडस्ट्रीज, पीडब्ल्यूसी, रासीसीड्स, समुंती, सुमितोमोके मिकलइं.प्रा.लि.,, सगेंटा, टीस्टेंस लिमिटेड, टैफे, टाटारैलिस"। इसके अलावा छात्र अन्य अल्पकालिक तथा आवंटित परियोजनाओं को भी निष्पादित करते है।

औद्योगिक दौराः

5.8 पांचवे ट्रइमिस्टर में विद्यार्थियों द्वारा औद्योगिक दौरा किया जाता है। औद्योगिक दौरे के उद्देश्य कई कम्पनियों तक पहुँचना और पीजीडीएम (एबीएम) की अनोखी विशेषताएं और सामर्थ्य का मूल्यांकन करना है। यह इन कंपनियों में अंतिम अवस्थापन और सम्मर इंटर्नशिप की संभावनाओं का पता लगाने में सुअवसर उपलब्ध कराता है। 2014-16 बैच के विद्यार्थियों ने 200 से अधिक कंपनियों के वरिष्ट कार्यपालकों के समक्ष प्रस्तुतीकरण दियाहै।

स्पाइस समाचारपत्र

5.9 इस त्रैमासिक पत्रिका पी जी डी एम (ए बी एम) के छात्रों द्वारा प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका में इंडस्ट्री इंटरफेस कार्यक्रम, गेस्ट लेक्चर्स, अनेक कार्यक्रम, छात्रों के प्रपत्र तथा संकाय पुनर्निवेशन सहित नवीन कैंपस समाचार प्रस्तुत किया जाता है।

अंतिम स्थापनाः

5.10 2014-16 बैच के सभी छात्रों को नियुक्ति प्रदान की 28 कंपनियों ने मैनेज का दौरा किया तथा सभी छात्रों की नियुक्ति करने के द्वारा 100 प्रतिशत प्लेसमेंट प्राप्त किया। औसतन सीटीसी रु. 7.7 लाख प्रति वर्ष के अनुसार नियुक्ति प्रदान की गयी जिसमें राशि रु. 5.00-18.00 लाख प्रति वर्ष के दर से रहा है ।

5.11 छात्रों को नियुक्त किये कंपनियाँ हैं -"एबीविस्टा, एडीएम, कोरोमंडल इंटर नेशनल लिमिटेड, डीसीएम, धानुका, डिलसा, एक्सेलक्रॉप केयर लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई सीआई बैंक, आईकेएसएल, आईटीसी-एबीडी, जनालक्ष्मी, के आर आई बी एच सी ओ, एल एंड टी फाइनेंस, महिंद्रा, माहिको, मोरडोर इनटेलिजेंस, एन ए बी सी ओ एन एस पी डब्ल्यू सी, रासी सीड्स, सुमुंती, स्काईलार्क, सुमितोमो, टीस्टेंस, टाटारैलिस, तेलंगाना सीड्स कॉर्पोशन, यूपीएल तथा यसबैंक "।

कार्यक्रम प्रबंधः

5.12 शैक्षणिक समिति, परिक्षा समिति और अपील समिति द्वारा कार्यक्रम का दिग्दर्शन किया जाता है।

पीजीडीएम (एबीएम) श्रेणीकरण

5.13 मैनेज देश के उत्तम बी- स्कूलों में से एक के रूप में गिना जाता है। कार्यक्रम को दी गयी श्रेणी निम्न रुप से है:-

आउटलुक रैंक 2015

द्वितीय सेक्टोराल - बी स्कूल
दक्षिण में चौथा उत्तम बी स्कूल
10 वीं उत्तम सरकारी बी स्कूल
10 वीं उत्तम बी स्कूल एवं व्यक्तित्व विकास एवं उद्योग एक्सपोजर
13 वीं उत्तम बी स्कूल एवं आरओआई
21 वीं उत्तम बीस्कूल भारत में शीर्ष 100 बिजनेस स्कूलों में

बिजिनेस टुडे रैंक 2015 में

प्रथम उत्तम - बी स्कूल हैदराबाद
तीसरा उत्तमबी स्कूल
दक्षिण में तीसरा उत्तम बी स्कूल
17 वीं उत्तमबी स्कूल
22 वां उत्तम बी स्कूल एवं आरओआई
30 वांउत्तम बीस्कूल भारतमें

बिजिनेस स्कूल रैंक 2015 में

चौथा उत्तम सेक्टर - बी स्कूल भारत
9 वां उत्तम बीस्कूल बुनियादीढांचाऔरसुविधाएं
23 वांउत्तम बीस्कूल भारतमें
25 वांउत्तम बीस्कूल भारतमेंप्लेसमेंट

बिजिनेस लीडरों के साथ परिचर्चाः

5.14 इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप उद्योग अंतरापृष्ट है जिसमें उद्योग जगत और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा करते है। समीक्षा अवधि के दौरान विद्यार्थियों के साथ जिन कंपनियों ने परिचर्चा की है वे निम्नानुसार है।

प्रशि.सं.	नाम	संगठन	पदनाम
1	रमन सिंह सलूजा	रमन सिंह सलूजा	संस्थापक
2	नितिन चौधरी	समुंती वैलुचैन फाइनेंस	सह-संस्थापक
3	टी अरविंद	सेंगेंटा फाउंडेशन इंडिया	मैनेजर
4	शैलेश कनानी	एडीएम	हेड - कॉर्मिशियल
5	बेथओसोवसकि	एडीएम	ग्रेजुएट टैलेंट कॉर्डिनेटर
6	ग्रेजुएट टैलेंट कॉर्डिनेटर	टाटा रैलिस	हेड-सीड
7	तुषार सेठी	जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज	हेड - टैलेंट एक्वाजिशन लक्ष्मी
8	तेजस्वी राम	अर्नस्टऔरयंग	कार्यकारी उपाध्यक्ष
9	दिनेश भोसले	एबीविस्ता	निदेशक दक्षिण एशिया
10	वेलुमुरगम	महिंद्रा एग्री बिजनेस डिवीजन	बिजनेस हेडसीड
11	पीरवींद्रन	टी स्टेंस	वरिष्ठमहा प्रबंधक (बिक्री और विपणन)
12	टी गौरी शंकर	नागार्जुन एग्रो केमिकल्स	हेड - मानव संसाधन
13	अजय ककरा	पीडब्ल्यूसी	निदेशक - कृषिऔरप्राकृतिकसंसाधनविभाग
14	मिहिर ज्योति मोहंत	मदरडेयरी	जीएम - आपूर्ति श्रृंखला
15	साईकौशल्या	ग्रीनएक्सचेंज- कॉमर्शियल	संस्थापक
16	माधव अधिकारी	कोरोमंडल इंटरनेशनल	जीएम और डिवीजन लहेड - पूर्व
17	गुलशन धनजाल	एचयूएल	वैश्विक खरीद प्रबंधक वाणिज्यिक
18	कमल कुमार	धानुका एग्रीटेक	एचआरहेड- कॉर्मिशियल
19	सोमनाथ बेरा	पी एस इंटरनेशनल इंडिया प्रा.लि	निदेशक और कंट्री मैनेजर
20	विश्वजीत नायक	श्रीराम बायोसीड जेनेटिक्स इंडिया लिमिटेड	अखिल भारतीय उत्पाद प्रबंधक
21	आशुतोष कुमार सिन्हा	विलग्रो	संस्थापक

गौरवान्वित क्षण

5.15 वर्ष के दौरान विद्यर्थियों ने अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और सम्मानित हुए। विवरण निम्नानुसार है।

स्पर्धा 2016- वमनिकोम,पुणे फरवरी 2016 में आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार।

स्पर्धा 2016- "निबंध लेखन वमनिकोम, पुणे फरवरी 2016 में आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार।

स्पर्धा 2016- बिजनेस क्विज वमनिकोम, पुणे फरवरी 2016 में आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार।

दृष्टि 2015 प्रबंधन केस स्टडी" एसआईबीएम (सिम्बायोसिस), पुणे दिसंबर, 2015 में आयोजित प्रतियोगिता में तीसरा स्थान।

मार्क मंत्रा प्रपत्र लेखन, अई अई एफ टी, कोलकता में जंवरी 2016 में प्रथम पुरस्कार

5.16 मैनेज पी जी डी एम (ए बी एम) ने 27 से 28 सितंबर, 2015 को 'कृषि चाणक्य' बी-फेस्ट - 2015 का आयोजन किया। अन्य विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए वे हैं (i) बी-प्लैन (आकांक्षा) (ii) के स्टडी सुशीघ्र (iii) चक्रव्यूह (वाद-विवाद) तथा (iv) प्रपत्र प्रस्तुतीकरण (समीक्षा) का आयोजन बी-फेस्ट के दौरान किया गया। इन कार्यक्रमों के अलावा, मानव संसाधन सम्मिट तथा कई खेल-संबंधी कार्यक्रम फोटोग्राफी, फिगर मेंकिग, टर्न कोट, फेस पेइंटिंग भी आयोजित किए गए। नामी अतिथियों एवं विभिन्न बी-स्कूलों के छात्रों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

5.17 मैनेज में इनकुबेशन: मैनेज के पी जी डी एम - ए बी एम छात्रों के लिए स्टार्टअप - इनकुबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए मैनेज ने रेन बी, मुम्बई के साथ समझौता के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जो वर्तमान एवं पूर्व छात्रों को अपने विचारों एवं नवोन्मेशनों के आधार पर व्यापार प्रारंभ करने में जानकारी एवं अवसर में वृद्धि करेगा।

स्नातकोत्तर कृषि विस्तार प्रबंध डिप्लोमा (पीजीडीएईएम)

5.18 मैनेज ने वर्ष 2007-08 के दौरान दूरस्थ शीक्षा प्रणाली के आधार पर एक वर्षीय स्नातकोत्तर कृषि विस्तार प्रबंध डिप्लोमा का प्रारंभ किया। यह कार्यक्रम कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार विस्तार सुधार योजना के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों का समर्थन के भाग के रुप में प्रायोजित किया जा रहा है।

5.19 कार्यक्रम के उद्देश्य

- विस्तार कर्मियों की तकनीकी - प्रबंधकीय (टेक्नो-मैनेजीरियल) दक्षताओं में वृद्धि करना।
- विस्तार कर्मियों को कृषि एवं तत्संबंधी क्षेत्रों के नवीन कार्यों से अवगत कराना
- विस्तार कर्मियों को भागीदारी निर्णायन हेतु नवीन उपकरणों तथा तकनीकों संबंधी ज्ञान प्रदान करना
- कृषि मूल्य-श्रृंखला (एग्रि वैल्यू-चेन) में समृद्ध बनाने हेतु विभिन्न विस्तार नमूनों पर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में विस्तार कर्मियों की सहायता करना।

5.20 इसके अलावा, पी जी डी ए ई एम के 8वें बैच के लिए दिसंबर 2015 में इस कार्यक्रम के लिए 14726 आवेदक नामांकित हुये और 9वें बैंच की प्रक्रिया जारी है।

5.21 यह कार्यक्रम मैनेज के मिशन के अनुरूप है जो कि विस्तार अधिकारियों, प्रबंधकों, वैज्ञानिकों तथा प्रशासकों द्वारा प्रबंधकीय व तकनीकी कौशल प्राप्त करने को सरल बनाना है। इसे कृषि अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में करना है ताकि उन्हें किसानों एवं मछुवारों द्वारा दीर्घ कालिक कृषि करने में समर्थन प्रदान कर सके।

5.22 इस कार्यक्रम की अवधि एक वर्ष है,जो अर्धवार्षिक में बाटा गया है, 32 क्रेडिट के साथ जहाँ प्रत्येक में 5 पाठ्यक्रम है साथ ही एसइंनमेंट एवं परियोजना कार्य भी है। सरकारी व निजी दोनों विस्तार कर्मियों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क रु. 15,000/- है। सरकारी विस्तार कर्मचारियों का पाठ्यक्रम शुल्क विस्तार सुधार योजना के निधि में से वहन किया जाएगा ।

5.23 इस कार्यक्रम का आयोजन दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के आधार पर किया जा रहा है जिसका समर्थन सभी विषयों से संबंधित हिन्दी व अंग्रेजी में मुद्रित पठन सामग्री,वीडियो लेक्चर तथा कांटैक्ट क्लासेस के साथ किया जाता है। ये कक्षाएं विभिन्न राज्यों के समेतियों में प्रत्येक सत्र में पाँच दिनों के लिए परीक्षाओं से पहले आयोजित किए जाते है। पुनरावलोकित अध्यापन के भाग के रूप में पठन सामाग्री के वीडियो लेक्चरों को मैनेज वेबसाइट पर रखा गया है। ये लेक्चर आवेदकों को विषय विशेषज्ञों को प्रत्यक्षतः सुनने मे सहायक होंगे जिससे इस कार्यक्रम को कक्षा गत परिस्थितियों के बहुत करीब ला सकते है।

5.24 पाठ्यक्रम मॉड्यूल

सत्र - 1

पाठ्यक्रम 101: कृषि विस्तार प्रबंध की प्रस्तावना (4 क्रेडिट)

पाठ्यक्रम 102: कृषि नवोन्मेषण का संचार और प्रसार(3 क्रेडिट)

पाठ्यक्रम 103: विस्तार प्रबंधके सिद्दान्त और पद्दति (3 क्रेडिट)

पाठ्यक्रम 104: कृषि विस्तार में सहभाग दृष्टिकोण (2 क्रेडिट)

पाठ्यक्रम 105: कृषि विस्तार में अनुसंधान पद्दति(2 क्रेडिट)

सत्र - II

पाठ्यक्रम 201: बाजार उन्मुख विस्तार (4 क्रेडिट)

पाठ्यक्रम 202: एग्री बिजनेस तथा उद्यमशीलता विकास (3 क्रेडिट)

पाठ्यक्रम 203: कृषि विस्तार में परियोजना प्रबंध (2 क्रेडिट)

पाठ्यक्रम 204: कृषि विकास के लिए सूचना और संचार टैकनोलॉजी (3 क्रेडिट)

वैकल्पिक पाठ्यक्रम 205 A: सतत कृषि विकास (3 क्रेडिट)

वैकल्पिक पाठ्यक्रम 205 B: सतत पशुधन विकास (3 क्रेडिट)

वैकल्पिक पाठ्यक्रम 205 C: सतत मत्स्य विकास (3 क्रेडिट)

पाठ्यक्रम 206: परियोजना कार्य (3 क्रेडिट)

प्रगति

5.25 प्रारंभिक वर्ष 2007 से लेकर अबतक कुल 14726 आवेदक (14614 सरकारी क्षेत्र से तथा 112 निजी क्षेत्र से, इस कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किए है जो 34 राज्यों/संघ राजय क्षेत्रों है। प्रारंभ से लेकर, 10246 आवेदकों ने इस कार्यक्रम को सफलता पूर्वक पूरा किया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 2119 आवेदक पीजीडीएईएम के 8 वीं बैच के लिए नामांकित हुए है, जिनमें से 1108 आवेदक परीक्षा में सफल हुये एवं बाकी के लिए इस कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए एक वर्ष का और समय है।

5.26 दिसंबर 2015 के दौरान, वर्ष 2007-08 से 2012-13 बैचों के 1954 बैकलोग आवेदकों के लिए 2013-14 के बैकलोग आवेदकों के साथ विशेष पूरक परीक्षा का अवसर दिया गया। वर्ष 2007-08 से 2012-13 बैचों एवं 2013-14 के आवेदकों के साथ विशेष पूरक परीक्षा का अवसर दिया गया। जिन आवेदकों ने इस अवसर का उपयोग किया उनमें से 349 आवेदक परीक्षा में सफल हुये। जिन आवेदकों ने इस अवसर का उपयोग किया उनमें से 368 आवेदक पीजीडीएईएम परीक्षा में सफल हुये। इसके अलावा, पी जी डी ए ई एम के 9वें बैच के लिए मार्च 2016 में इस र्यक्रम के लिए 23 राज्यों से 1049 आवेदक नामांकित हुये।

5.27 विशेष कार्य

एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 18 राज्यों के निदेशक/कार्यक्रम संचालक उपस्थित थे तथा तकनीकी संघटक को जोड़ने के लिए परियोजना कार्य निर्देशों का पुनरावलोकन किया गया और अनिवार्य क्षेत्र कार्य विषय को ए - तकनीकी, बी - सरकारी योजनाएं (राज्व व केंद्र) तथा सी - विस्तार अभिगाम के रूप में किया गए।

बैकलॉग को कम कर उत्तीर्णता दर को बढ़ाने के लिए मैनेज पी जी डी ए ई एम ने महत्वपूर्ण प्रयास किए है।

सहयोगी कार्यक्रम के तहत, एन आई पी एच एम और मैनेज संयुक्त रूप से कृषि परिवेशिक प्रणाली विश्लेषण आधारित पौध स्वास्थय प्रबंधन और बायो-सेक्यूरिटी के क्षेत्रों में 55 भागीदारों (पी जी डी ए ई एम) को कौशल प्रदान किए जिससे तकनीक के साथ विस्तार प्रबंध के उचित सम्मिश्रण प्राप्त कर सके।

मैनेज फेसिलिटेटरों के सक्षम दल के विकास के लिए सभी पंजीकृत राज्यों के सफल पी जी डी ए ई एम आवेंदकों में से दक्ष आवेदकों के पहचान हेतु एक अभ्यास किया गया और 33 राज्यों के 60 आवेदकों में से 33 को मैनेज पी जी डी ए ई एम फेसिलिटेटर विकास प्रशिक्षण के लिए चुना गया।

18 जनवरी, 2016 को पी जी डी ए ई एम पर एक पुनरावलोकन कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 15 राज्यों के समेतियों व प्रतिनिधित्व करते 18 अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें भागीदारों ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विस्तार सुधार कक्ष के वीडियो कान्फरेंस के माध्यम से पी जी डी ए ई एम के निधी के परिवर्तित विधि पर विचार-विमर्श किया है।

6 सूचना, प्रलेखन एवं प्रकाशन

6.1 मैनेज का पुस्तकालय मैनेज से संबद्ध विषयों पर संकाय, भागीदार एवं छात्रों को प्रलेखन सेवाएं प्रदान करता है और संस्थान के प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान और अन्य परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करता है।

सूचना संसाधन

6.2 उपलब्ध श्रोतों में कृषि एवं तत्संबंधी क्षेत्रों की पुस्तकें, पत्रिकाएं, रिपोर्ट, वीडियो केसेट्स, सीडी/डीवीडी है। पुस्तकालय की पुस्तकों के मुख्य क्षेत्र हैं कृषि विस्तार, कृषि आर्थिकी, प्रबंधन, विपणन, अनुसंधान पद्धति, सहभागीदारी अनुप्रयोग, लिंग अध्ययन, मानव संसाधन विकास, परियोजना प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि-व्यवसाय, उद्यमिता, व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी आदि।

इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस

6.3 इस वर्ष के दौरान,इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेसों में प्रॉवेस तथा इंडिया स्टैट्स मंगाई गई हैं। इंडिया ट्रेड्स विदेशी व्यापार के सांख्यकी को तथा अन्य व्यापार से संबंधित डाटाप्रस्तुत करता है; प्रॉवेस भारतीय कम्पनियों का डाटाबेस है; इंडिया ट्रेड्स एक ऑनलाईन डाटाबेस है जो भारत में सांख्यकी को प्रवेश कराता है। पुस्तकालय में ई-पत्रिका डाटाबेस, एबीआई-सूचना प्रोक्वेस्ट को भी मंगाया जाता है। ई-जर्नल डैटाबेस 'ए बी आई - इनफार्म' भी संकाय, कर्मचारी एवं छात्रों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

स्वचालित पुस्तकालय

6.4 पुस्तकालयडाटाबेस का प्रबंधन ई-ग्रंथालय साफ्टवेयर द्वारा किया जा रहा है। पुस्तकालय सेवाओं में सूचना, डाटाबेसों के प्रयोग में सहायता तथा अन्य सूचना संसाधनों; संदर्भ सेवाएं और साहित्यिक शोध सेवाओं को प्राप्त कराना शामिल है। पुस्तकालय संकाय सदस्यों को पत्रिकाओं में प्रकाशित नए लेखों तथा पुस्तकों के संकलन में जोड़ी गयी नई पुस्तकों की सूचना आवधिक रूप से देती है। इसे वेबसाईट पर पुस्तकालय पेज पर भी रखा गया है।

प्रकाशन

6.5 मैनेज विस्तार प्रणालियों के संबंध में सूचना प्रसार हेतु तथा अभ्यास, विस्तार पर अनुसंधान, प्रभावी संगठन के प्रौद्योगिकी स्थानांतरण और कृषि तथा संबंधित क्षेत्र के नीति निर्माता व उनके लाभार्थ, वैज्ञानिकों और विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए, उनके संबंध में अन्य सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के लिए एक अर्ध वार्षिक पत्रिका **कृषि विस्तार प्रबंधन जर्नल** का प्रकाशन करता है।पुनरावलोकित वर्ष के दौरान इस पत्रिका के दो अंक प्रकाशित किए गए है।

6.6 मैनेज बुलेटिन एक द्वैमासिक समाचार-पत्र है, जिसमें मैनेज की विभिन्न गतिविधियाँ जैसे कि प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान, परामर्श, योजना कार्यान्वयन, को केंद्र बिंदु बनाया जाता है। बुलेटिन को ऑनलाईन से प्राप्त किया जा सकता है।

6.7 "ए हैण्ड बुक ऑन मार्केटिंग एक्सटेन्शन फर एक्सटेन्शन फन्क्शनरीस" मैनज द्वारा प्रकाशित किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी सहायता

6.8 संस्थान में 150 कम्प्यूटरों को एक लीज्ड लाईन के 100 एमबीपीएस एवं 22 एमबीपीएस से 24 घंटे इंटरनेट से जोडा गया है। वीडियो सम्मेलन की सुविधा मंत्रालय तथा अन्य विभिन्न संस्थानों के साथ संपर्क करने को सरल बनाने हेतु उपलब्ध कराई जाती है। अहाता में वाई-फाई उपलब्ध है।

वेब पर मैनेज

6.9 मैनेज की वेबसाईट www.manage.gov.in पर, मैनेज के प्रशिक्षण एवं शिक्षण कार्यक्रमों, परियोजनाओं तथा प्रकाशनों की नवीनतम जानकारी हिन्दी व अँग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई जाती है। वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर ऑनलाईन उपलब्ध है। अकादमिक कैलेंडर मैनेज वेब साईट पर पंजीकरण हेतु मोबाईल याप सहित उपलब्ध है। मैनेज द्वारा क्रियान्वित भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं संबंधी सूचना तथा मैनेज अनंसंधान एवं परामर्शी सेवा परियोजनाओं संबंधी नवीकृत सूचना मैनेज वेबसाईट पर उपलब्ध है।

7 राजभाषा की प्रगति

7.1 पुनरावलोकित वर्ष के दौरान, राजभाषा क्रियान्वयन समिति कि तिमाही बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया गया तथा तिमाही प्रगति रिपोर्टों को राजभाषा विभाग, कृषि मंत्रालय तथा क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, साउथ ब्लॉक, बैंगलूर भेजा गया।

7.2 राजभाषा नियम के अनुसार मैनेज "क और ख" क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों से हिन्दी व अंग्रेजी (द्विभाषी रूप) में पत्राचार कर रहा है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन हेतु सभी दस्तावेजों का द्विभाषीकरण प्रयासरत है। मैनेज के सभी दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास जारी है। वर्ष 2014-15 की 'वार्षिक रिपोर्ट' तथा 'वार्षिक लेखा' द्विभाषी रूप में तैयार किया गया है।

7.3 मैनेज वेबसाईट द्विभाषी रूप में है और इसका निरंतर नवीकरण किया जाता है। "ए हैण्डबुक ऑन मार्केटिंग एक्सटेन्शन फर एक्सटेन्शन फक्शनरीस" जो मैनज द्वारा प्रकाशित किया गया था उसका हिन्दी अनुवाद कर मैनज वेब साईट पर उपलब्ध कराया गया है। कृषि उद्यमियों की सफल कहानियों के पुस्तक को भी हिन्दी में अनुवाद कर मैनेज वेब साईट पर रखा गया है। हाल ही में राजभाषा विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया पारंगत पाठ्यक्रम की एक बैच का आयोजन फरवरी-मार्च, 2016 के दौरान किया गया है।

7.4 मैनेज ने "हिन्दी में तकनीकी साहित्य का सृजन और इसका विस्तृत संचार: कृषि साहित्य के विशेष संदर्भ में" विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 9 दिसंबर, 2015 को किया है। विभिन्न संगठनों के 28 भागीदारों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। भागीदारों में वरिष्ठ वैज्ञानिक, हिन्दी अधिकारी/केंद्र सरकारी संस्थानों के कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों में कार्यरत हिन्दी अनुवादक थे।

7.5 गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मैनेज को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति - 4 (केंद्र सरकार के संगठन) का उत्तरदायित्व सौंपा गया इस नराकास में 51 सदस्य संगठन है।

7.6 राजभाषा की उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए तिमाही कार्यशालाओं का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है। कार्यालयीन संपर्क में हिन्दी टंकरण को प्रोत्साहित करने के लिए कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित हिन्दी में बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण में भेजा जा रहा है। सितंबर 2015 के दौरान हिन्दी पखवाडों का आयोजन किया गया। इसमें कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन कर विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

7.7 मैनेज बुलेटिन और एग्रिप्रेन्यूर ई बुलेटिन को द्विभाषी रूप में तैयार कर मैनेज वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया है।

8 प्रशासन एवं लेखा

8.1 मैनेज के सामान्य पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी महापरिषद की है जिसकी अध्यक्षता माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार द्वारा कीजातीहै। माननीय कृषि राज्य मंत्री और सचिव (कृषि एवं सहकारिता) महापरिषद के दो उपाध्यक्ष है। मैनेज का संपूर्ण नियंत्रण महापरिषद द्वारा किया जाता है और मैनेज के कार्यों के सक्षम प्रबंधन और प्रशासन के लिए निर्देश जारी करता है। मैनेज के महापरिषद का गठन **परिशिष्ट** -I में दिया गया है।

8.2 महापरिषदके संपूर्ण नियंत्रण निर्देशों के आधार पर, कार्यकारी परिषद, नियमों और उप नियमों के अनुसार मैनेज के क्रियाकलापों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है। कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता सचिव (कृषि एवं सहकारिता) द्वारा की जाती है। कार्यकारी परिषद का गठन **परिशिष्ट-II** में दिया गया है।

8.3 भारत सरकार द्वारा महानिदेशक की नियुक्ति होती है और वे संस्थान की गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने के जिम्मेदार होते हैं। संकाय सदस्य, प्रशासन और इंजीनियरिंग विंग महानिदेशक की सहायता करते हैं।मैनेज के संकाय और अधिकारियों की रुपरेखा **परिशिष्ट-III** में दी गई है।

निधि

8.4 प्रत्येक वर्ष भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग मैनेज को अनुदान सहायता देता है। स्थापना एवं प्रशासन पर हुए साठ प्रतिशत व्यय को कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा जारी कीगयी अनुदान राशि मे से लिया जाता है तथा शेष चालीस प्रतिशत व्यय को मैनेज स्वयं के निधि से करता है। तथापि, मैनेज के ढाँचे तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पूरे व्यय को भारत सरकार के निधि से व्यय किया जाता है।

बैठके

8.5 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्न बैठकें आयोजित की गई:

कार्यकारी परिषद

कार्यकारी परिषद की 67वीं बैठक 12 अक्तूबर,2015 को कृषि भवन नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। मैनेज के अकादमि समिति की 20वीं बैठक 1 मार्च, 2016 को संपन्न हुई।

मार्च 2016 में आयोजित अकादमिक समिति की बैठक

परिशिष्ट

मैनेज के महापरिषद का गठन (31/03/2016) को

नियम सं. 3(ए)	महापरिषद का गठन	क्र.सं.	सदस्य क नाम और पता
i	**मैनेज का अध्यक्षः** भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग के प्रभारी मंत्री मैनेज से संबद्व होंगे।	1	श्री राधा मोहन सिंह माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली - 110 001
ii	**मैनेज के दो उपाध्यक्षः**: (क) राज्य मंत्री (कृषि, सहकारिता एवं किसान कलयाण विभाग) कृषि व सहकारिता विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं (ख) सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	2 3	श्री संजीव कुमार बाल्याण माननीय कृषि राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली - 110 001 श्री शोभना के. पट्टनायक, भा. प्र. से., सचिव (कृषि एवं सहकारिता), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग कृषि मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली - 110 001
iii	**एक व्यक्ति** गैर अधिकारी जो भारत की संस्थाओं में कृषि विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हों - सदस्य के रूप में मैनेज के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे।	4	रिक्त (4 अक्तूबर, 2015 से)
iv	**तीन** प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्होंने कृषि विकास के क्षेत्र में तथा संबंधित विषयों में उल्लेखनीय योगदान दिया हो।	5 6 7	रिक्त (4 अक्तूबर, 2015 से) रिक्त (4 अक्तूबर, 2015 से) रिक्त (4 जनवरी, 2016 से)
v	महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पी आर	8	डॉ. डब्ल्यू आर. रेड्डी, भा. प्र. से. महानिदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान,राजेन्द्रनगर हैदराबाद - 500 030

vi	महानिदेशक, एनआईएएम	9	श्रीमती इरिना गर्ग, भा.रा.से., महानिदेशक, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (नियाम) कोटा मार्ग, बंबाला, संगेनर के पास, जयपुर - 303 906
vii	महानिदेशक, आईसीएआर	10	डॉ. त्रिलोचन महापात्रा सचिव (डे र) व महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् कृषि भवन नई दिल्ली - 110 011
viii	क) अपर सचिव ख) प्रभार संयुक्त सचिव विस्तार ग) मैनेज के साथ निपट रहें भारत सरकार के मत्रालय/विभाग में वित्त सलाहकार	11 12 13	श्री राघवेन्द्र सिंह, भा. प्र. से. अतिरिक्त सचिव (कृषि विस्तार) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली - 110 001 श्री नरेन्द्र भूषण, भा. प्र. से संयुक्त सचिव (विस्तार) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली - 110 001 श्री कुमार संजय कृष्ण, भा. प्र. से., अतिरिक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली - 110 001
ix	भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली	14	कृषि आयुक्त, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001

x	भारत सरकार के योजना आयोग विभाग के सचिव या नामित सदस्य जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद के नीचे न हों।	15	सचिव, योजना आयोग भारत सरकार, योजना भवन नई दिल्ली - 110 001
xi	चार सचिव राज्य सरकार/संघ राज्य -क्षेत्र के कृषि उत्पादन के प्रभारी (चक्रानुक्रम में) या उनके नामिती जो राज्य सरकार के उप सचिव पद से नीचे के न हों।	16 17 18 19	रिक्त रिक्त रिक्त रिक्त
xii	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के दो कृषि निदेशक (चक्रानुक्रम द्वारा देश के अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले); या उनके नामिती जो कृषि अपर निदेशक या उसके समतुल्य अधिकारी के पद से नीचे के न हों।	20 21	रिक्त रिक्त
xiii	मैनेज के महानिदेशक जो भारत सरकार, के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नियुक्त किये गये हो। (पदेन सदस्य व सदस्य सचिव)	22	श्रीमती वी. उषारानी, भा. प्र. से. महानिदेशक राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज), राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030 (तेलंगाना राज्य)
xiv	कृषि विश्वविद्यालय के दो उप-कुलपति (चक्रमानुक्रम द्वारा) या उनके नामिती जो निदेशक पद से नीचे के न हों। (पदेन सदस्य)	23 24	रिक्त रिक्त

मैनज के कार्यकारी परिषद का गठन (31.3.2016) को

नियम सं.	कार्यकारी परिषद का गठन	क्र. सं.	सदस्य का नाम एवं पता (अध्यक्ष, अधिकारी एवं गैर - अधिकारी सदस्य)
5.I (i)	**पदेन सदस्य**		
a)	सचिव (कृषि एवं सहकारिता) मैनेज के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष होंगे	1	श्री शोभना के.पट्टनायक, भा.प्र.से. सचिव (कृषि एवं सहकारिता) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली - 110 001
b)	भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग में विस्तार के प्रभारी अपर सचिव मैनेज के क्रिया कलापों से निपट रहे है, कार्यरी परिषद के उपाध्यक्ष होंगे	2	श्री राघवेन्द्र सिंह, भा. प्र. से. अतिरिक्त सचिव (कृषि विस्तार) ,कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
c)	महानिदेशक, मैनेज	3	श्रीमती वी. उषा रानी, भा.प्र.से. महानिदेशक, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज), राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030
d)	भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग में मैनेज के विस्तार एवं वित्त सलाहकार के प्रभारी संयुक्त सचिव होंगे	4	श्री नरेन्द्र भूषण, भा. प्र. से संयुक्त सचिव (विस्तार) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली - 110 001
		5	श्री कुमार संजय कृष्ण, भा.प्र.से. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001

e)	**गैर-अधिकारी सदस्य दो प्रतिष्ठित व्यक्ति** जिन्होंने कृषि विकास के क्षेत्र में/संबंधित विषयों में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया हो उन्हें भारत सरकार द्वारा सामान्य परिषद के सदस्य में से नामित किया जाए	6 7	रिक्त रिक्त
f)	**एक सदस्य** को सामान्य परिषद द्वारा सामान्य परिषद के गैर अधिकारी सदस्यों में से नामित किया जाए	8	रिक्त

मैनेज संकाय एवं अधिकारियों के विवरण

संकाय

श्रीमती वी. उषा रानी,
भा. प्र. से., महानिदेशक

डॉ. वी. पी. शर्मा
निदेशक (आईटीडीपी)
एम.एस.सी. (सांख्यकी) एम.ए. (अर्थशास्त्र); एम.बी.ए. (परिचालन प्रबंधन); पी.एच.डी
vpsharma@manage.gov.in

डॉ. विक्रम सिंह
निदेशक
एम.ए. (मनोविज्ञान);एम.फिल; पी.एच.डी.
vikrams@manage.gov.in

डॉ. पी. चंद्रशेखरा
निदेशक (कृषि विस्तार) एवं कृषि उद्यमिता विकास केंद्र (सीएडी)
पी.एच.डी. (कृषि विस्तार)
chandra@manage.gov.in

डॉ. के.आनंद रेड्डी
निदेशक (मा.सं.वि.) , एवं प्रधान समन्वयक- पी जी डी एम (ए बी एम)
एम.ए.(अर्थशास्त्र); पी.एच.डी (प्रबंधन)
anandreddy@manage.gov.in

डॉ. बी. के. पति
निदेशक (ओएसपीएम)
पी.एच.डी, एम.बी.ए, एम.कॉम.
bkpaty@manage.gov.in

डॉ. के. उमा रानी
निदेशक एवं प्रधान समन्वयक - पीजीडीएईएम
पी.एच.डी. (गृह विज्ञान, विस्तार शिक्षा)
kumarani@manage.gov.in

डॉ. आर. सरवणन
निदेशक(कृषि विस्तार)
एम.एस.सी.(कृषि विस्तार);पी.एच.डी. (कृषि विस्तार)
saravanan.raj@manage.gov.in

डॉ. एम. ए. करीम
उप निदेशक (कृषि विस्तार)
एम.एस.सी.(कृषि विस्तार);पी.एच.डी. (कृषि विस्तार)
makareem@manage.gov.in

डॉ. जी. जया
उप निदेशक (मा.सं.वि.)
एम.बी.ए,पी.एच.डी., (प्रबंध विज्ञान); पीजीडीएईएम
gjaya@manage.gov.in

डॉ. लक्ष्मी मूर्ति
उप निदेशक (प्रलेखन)
एम.ए.(अर्थशास्त्र); एम.एल.आई.एससी.; पी.एच.डी. (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान); एडवांस्ड डिप्लोमा इन फ्रेंच; पीजीडीएईएम
सूचना विज्ञान एवं तक्नीक मे फुलब्रईट स्कालर, कोरनेल विश्वविद्यालय
lakshmi@manage.gov.in

डॉ. एन. बालसुब्रमणी
उप निदेशक (ओएसपीएम)
एम.एससी. (कृषि), पी.एच.डी. (कृषि विस्तार), एम.बी.ए.,पीजीडीएचआरएम
balasubramani@manage.gov.in

डॉ.करबसय्या सी. गुम्मागोलमठ
उप निदेशक (एम&ई)
पी.एच.डी (कृषि अर्थशास्त्र)
kcgum@manage.gov.in

डॉ. बी. रेणुका रानी
सहायक निदेशक (मा.सं.वि.)
एम.एस.डब्लू.; पी.एच.डी. (वुमेन स्टडीस); पीजीडीपीआर (जन संपर्क); पीजीडीएईएम
brenuka@manage.gov.in

श्री जी. भास्कर
सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी)
एमसीए, एमबीए, एमसीएसई, एम.ए.,
आरडीबीएमएस में डिप्लोमाएवंओओपीएस, पीजीडीएईएम
gbhaskar@manage.gov.in

डॉ. पी. लक्ष्मी मनोहरी
सहायक निदेशक (कृषि विस्तार)
एम.एससी (कृषि विस्तार); पी.एच.डी. (कृषि - संचार)
plmanohari@manage.gov.in

डॉ. शाहजी संभाजी फंड
सहायक निदेशक (संबद्ध विस्तार)
एम.वी.एससी (पशुपालन विस्तार शिक्षा), पी.एच.डी. (**पशुपालन विस्तार शिक्षा**)
shahaji@manage.gov.in

श्री के. वेंकटेश्वर राव
कम्प्यूटर प्रोग्रमर
एम.टेक. (सीएसई); एम.एससी (भौतिकी); पीजीडीसीए, पी.एच.डी. (प्रबंध)
kvrao@manage.gov.in

डॉ. अत्तलूरी श्रीनिवासाचार्युलु
अनुसंधान सहायक
एम.एल.आई.एससी.; एम.ए.(दर्शनशास्त्र); पी.एच.डी. (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान); पीजीडीएलएएन; पीजीडीएईएम
ascharyulu@manage.gov.in

डॉ. के. साई महेश्वरी
अनुसंधान सहायक
एम.एससी, (कोश्कीट पालन), पीजी डिप्लोमा; पी.एच.डी. (कोश्कीट पालन); पीजीडीएईएम
kmaheshwari@manage.gov.in

डॉ. बी. वेंकट राव
अनुसंधान सहायक
एमबीए (विपणन); पी.एच.डी. (प्रबंधन)
bvrao@manage.gov.in

डॉ. पी. कनक दुर्गा
अनुसंधान सहायक
एम.ए.(अर्थशास्त्र); एम.फिल.(अर्थशास्त्र); पी.एच.डी (अर्थशास्त्र)
kanakad@manage.gov.in

श्री ए. कृष्ण मूर्ति
प्रलेखन सहायक
एम.ए.(सार्वजनिक प्रशासन); एम.एल.आई.एससी.; स्वचालित पुस्तकालय एवं नेटवर्किंग में पीजी डिप्लोमा
krishnam@manage.gov.in

अधिकारी एवं कर्मचारी

श्री श्रीधर खिस्ते उप निदेशक (प्रशासन)	श्री सी. एच. एन. एम. राव सहायक लेखा अधिकारी
डॉ. जी. राधा रूकमिणी चिकित्सा अधिकारी	श्रीमती एन. उषा रानी महानिदेशक के निजी सचीव
डॉ. के. श्रीवल्ली हिन्दी अनुवादक	श्री ई. नागभूषणम भंडार अधिकारी
श्री ए वी एन एन गुप्ता कार्यालय अधीक्षक	री ई. राजशेखर कार्यालय अधीक्षक
श्री पी. जॉन मनोज सहायक इंजीनियर (सिविल)	श्रीमती वी. मंगम्मा वरिष्ठ लेखा अधिकारी
श्री के. जगन मोहन राव रिसेप्शनिस्ट कम केरटेकर	श्रीमती पी. भारती रानी वरिष्ठ आशुलिपिक
श्रीमती बी. रमनी वरिष्ठ आशुलिपिक	श्रीमती के. उमा महेश्वरी वरिष्ठ आशुलिपिक
श्रीमती बी. मीनाक्षी वरिष्ठ आशुलिपिक	श्रीमती एन. आशालता वरिष्ठ आशुलिपिक (सी ए डी)
श्री बी. चक्रधर राव ईडीपी सहायक (EDP)	श्री एम. श्रीनिवास राव ईडीपी सहायक (EDP)
श्री के. उदय वर्मा टेलिफोन आपरेटर	श्री एम. वेणूगोपाल ईडीपी सहायक (EDP)
श्री वीरय्या कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)	श्री सुनील कुमार मेस मैनेजर
श्रीमती वहीदा मुनावर कनिष्ठ लेखाकार	श्री राम मूर्ति कोषपाल
श्री टी. नागराजु कनिष्ठ लेखाकार	श्री गिरीजेश जोशी हाउस किपर
शश्री एम. शिव कुमार कनिष्ठ लेखाकार	श्रीमती पी. ज्योति कनिष्ठ आशुलिपिक
श्रीमती जी. संध्या रानी प्रवर श्रेणी लिपिक	श्रीमती एम. भाग्यलक्ष्मी सहायक कोषपाल

श्रीमती के. कमला प्रवर श्रेणी लिपिक	श्री वी. वंशी कृष्णा प्रवर श्रेणी लिपिक
श्री टी. फणि कुमार कनिष्ठ आशुलिपिक	सुश्री ए. रोनिता कनिष्ठ आशुलिपिक
श्री के. कृष्णमूर्ति कारचालक (ग्रेड-2)	श्री बी. मल्लेश चालक
श्री सत्यनारायण चालक	श्री जी. एस. पद्‍माराव बाईंडर
श्री एन. रघुपती प्लंम्बर	श्री नंदन गिरी रसोइया
श्री नरसिम्हुलु बहुकार्य कर्मचारी	श्री बी. यादगिरी बहुकार्य कर्मचारी
श्री सी. नारायणा बहुकार्य कर्मचारी	श्री राजा बाबु बहुकार्य कर्मचारी
श्री एन. जी. कोटय्या बहुकार्य कर्मचारी	श्री बी. एल्लामय्या बहुकार्य कर्मचारी
श्रीमति जे. विजया बहुकार्य कर्मचारी	श्री एन. शिवलिंगम बहुकार्य कर्मचारी
श्री बी. रामचंद्र बहुकार्य कर्मचारी	श्री बी. सत्तय्या बहुकार्य कर्मचारी

1 MANAGE – An Overview

1.1 The National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), established in 1987, is an autonomous organization under the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India (GoI). The increasing focus on commercialization and market orientation in agriculture and the complexity of agricultural technologies called for major initiatives towards reorienting and modernizing the agricultural extension system. Further, effective ways of managing the extension system needed to be evolved to transform the existing framework through professional guidance and training of critical manpower and MANAGE responded to this need adequately.

1.2 MANAGE was registered as a Society on 11th June 1987 under the Andhra Pradesh (Telangana areas) Public Societies Registration Act, 1350 Fasli (Act of 1350F).

1.3 The mandate of MANAGE is to assist Government of India and State Governments/UTs to help improve delivery mechanisms in agriculture and allied sectors through need-based changes in policies and programs, and also by way of improving the knowledge, skills and attitude of extension personnel. The Institute focus is on Training, Education, Research, Consultancy and information & documentation, apart from implementing some Central Sector Schemes.

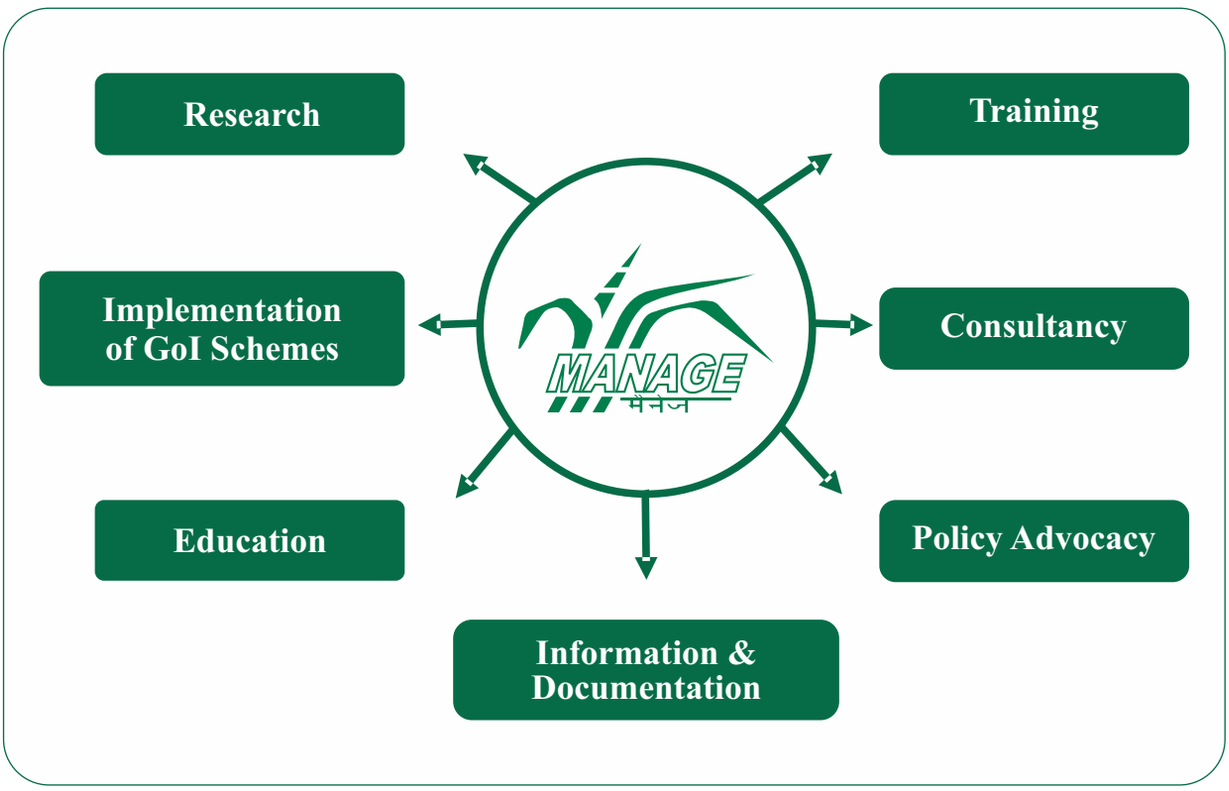

1.4 Mission

The Mission of MANAGE is to facilitate the acquisition of managerial and technical skills by extension officers, managers, scientists and administrators, in all sectors of agricultural economy with a view to enable them to provide the most effective support and services to farmers and fishermen for practicing sustainable agriculture.

1.5 Vision

To be counted among the most pioneering, innovative, user-friendly and self-supporting agricultural management institutes in the world.

1.6 Mandate

- Developing linkages between prominent State, Regional, National and International institutions concerned with agricultural extension management and also agricultural development
- Gaining insight into agricultural extension management systems and policies
- Forging collaborative linkages with National and International institutions for sharing faculty resources
- Developing and promoting application of modern management tools for improving the effectiveness of agricultural extension organizations
- Organizing need-based training for senior and middle level agricultural extension functionaries
- Conducting problem-oriented studies on agricultural extension management
- Functioning as an International Documentation Center for collecting, storing, processing and disseminating information on subjects related to agricultural extension management.

1.7 Core Values

- User-friendliness
- Client-centered process consultancy
- Farmer-focused approach in all professional services
- Interactive and experiential learning methodology
- Faculty development and networking with facilitators
- Determination to achieve financial self-reliance

1.8 The programs and activities of MANAGE cover public and private sector organizations, voluntary organizations, farmers' groups and organizations, private extension service providers, agribusiness companies and cooperatives apart from various national and international funding agencies.

1.9 MANAGE conducts training programs, workshops and refresher programs for public extension functionaries working in departments of agriculture, horticulture, animal husbandry & veterinary science, fisheries, sericulture departments of different States and UTs, scientists of Krishi Vigyan Kendras (KVK), ICAR Institutions and State Agricultural Universities (SAUs) and for private sector executives. MANAGE Programs are also customized in response to the requests from the GoI/States/UTs and the private sector.

1.10 Research at MANAGE focuses on themes of contemporary relevance. Evaluation of various Government programs/projects is also undertaken to assess their impact. MANAGE also takes up 'Action research' to pilot-test ideas / concepts / technologies in field situations. Apart from this, consultancy is also provided to agriculture and allied departments/agencies for developing strategies and programs in response to their request.

1.11 Another area of focus is Management Education. MANAGE offers a Post-Graduate Diploma in Agri-Business Management [PGDM (ABM)], which was launched in 1996, to prepare techno-managers. Another program ie. Post-Graduate Diploma in Agricultural Extension Management (PGDAEM), launched in 2007, is a continuing education program of one year duration, for in-service extension personnel, and offered on a distance education mode.

1.12 MANAGE is also implementing select Government of India Schemes such as "Agri-Clinics and Agribusiness Centres Scheme (AC&ABC), Kisan Call Centres (KCC), Diploma in Agricultural Extension Services for Input Dealers (DAESI), Skill Training of Rural Youth (STRY) and Farmers Capacity Assessment & Certification (FCAC).

The AC&ABC Scheme, launched in 2002, aims to supplement the efforts of public extension through agricultural professionals and create gainful self-employment opportunities for them.

The Kisan Call Centre attempts to leverage the national telecom infrastructure to deliver extension services to the farming community in local languages.

The DAESI program was initiated for imparting practical inputs on relevant technical aspects of agriculture to practicing input dealers on 'contact class-cum-distance education mode'.

STRY is aimed at imparting skill-based training to rural youth on agri-based vocational areas in agriculture & allied areas to promote employment in rural areas and for creation of skilled manpower to perform farm and non-farm operations.

FCAC is aimed at providing recognition to the farmers who have acquired desired skills in agriculture & allied areas but continued to be treated as un-skilled, in absence of a certificate.

1.13 Centers at MANAGE

There are eight theme based Centres at MANAGE and a School of Agribusiness Management.

The details on each Centre are given below:

1. Center for Agricultural Extension Policy, Reforms and Processes

Focus is on Agricultural Extension Management including aspects such as Distance Education for agricultural extension managers, developing online training and testing modules, facilitating agricultural extension solutions, evolving technology innovations and reforms in extension.

2. Center for Agri-Institution Capacity Building

This Center focuses on capacity building of institutions, extension functionaries and other stakeholders; developing methodology, systems and practices of capacity testing of various stakeholders; project planning and implementation; accreditation of training institutions and trainers; developing practices for achieving institutional excellence; developing and operationalising methodologies for impact assessment of extension efforts etc.

3. Center for Agricultural Markets, Supply Chain Management and Extension Projects

The focus of this Center is on developing models and practices for market-led extension, linking farmers to markets, orienting to supply chain process both at micro and macro levels. Focus is also on extension project planning & management, promoting convergence in extension projects and effective delivery of extension services with reference to marketing activities.

4. Center for Allied Extension

This Center focuses on developing concepts, systems and best practices for allied extension management; providing extension support for horticulture, fisheries, animal husbandry, dairy, agro-forestry, poultry and sericulture based integrated farming systems; water extension including development of management systems and approaches for command areas of large and medium surface irrigation projects; action research on various extension management practices followed in water and input management systems.

5. Center for Knowledge Management, ICT and Mass Media

This Centre focuses on developing concepts and operationalising a Knowledge Management Strategy for agriculture and allied sectors, developing a repository of relevant documents, preparing a database of extension recommendations, building capacity on Information and Communication Technologies (ICTs) and supporting software development for implementation of National Mission on Agricultural Extension and Technology (NMAET). In addition, the Center supports agri-tele services, e-extension, mass media and e-literacy at farmer level.

6. Center for Agripreneurship, Youth and PPP

Focus of this Center is on promoting Agripreneurship leading to generation of employment opportunities for youth and agripreneurs, at the same time providing trained manpower for agri-business and contributing to increased incomes to farmers. Additionally, the Center focuses on transforming agriculture to agribusiness and farmer to agripreneur; retaining youth in agriculture, promoting public-private partnership, etc.

7. Center for Women and Household Food and Nutritional Security, Urban Agriculture and Edible Greening

This Center focuses on women's empowerment by way of mainstreaming women in agricultural extension management, improving their awareness on

food and nutrition security of farm families, developing and operationalizing the concept of nutritional planning and budgeting, developing the concepts of moving from greening to edible greening and landscaping to edible landscaping, and developing appropriate training modules.

8. Center for Agrarian Studies, Disadvantaged Areas, NRM Extension and Social Mobilization

The focus of this Center is Agrarian studies which includes evolving specific extension strategies and practices for meeting the social and locational challenges of disadvantaged areas, promoting regional equity and natural resources management extension. Additionally, the Center focuses on social mobilization and social equity in NMAET and special programmes meant for various social groups apart from developing and operationalising "Farmers' Charter".

9. School of Agribusiness Management

The School offers Post-Graduate Diploma in Agri-Business Management to prepare young minds to face the challenges in Agribusiness management. Given the shift in focus to commercialization, the students are equipped to meet this challenge.

1.14 MANAGE at Krishi Unnati

MANAGE participated in Krishi Unnati, and showcased its initiatives and programs. This was a National Level Agriculture Fair-cum-Exhibition organized by the Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India at IARI, New Delhi from March 19-21, 2016. Five best Agripreneurs trained under Agri-Clinics and Agri-Business Scheme (AC&ABC) were invited to showcase their enterprises in the Mela.

Shri Radha Mohan Singh, Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare visiting MANAGE stall.

Institutional Collaboration

1.15 MANAGE and National Institute of Plant Health Management (NIPHM), Hyderabad joined hands to organize "Induction Training" for the newly recruited officers of State Departments of Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry, Seed Certification and Agriculture Marketing. The objective of the induction program was to impart knowledge and skills to mould the young minds for effective and efficient delivery of technologies to the farmers.

1.16 MANAGE entered into MoU with Indian Institute of Oilseeds Research (IIOR) under ICAR on 26th January 2016 to collaborate in research and extension projects. The purpose is to facilitate academic and research cooperation for exchange of visitors and trainees between the institutes.

1.17 A Memorandum of Understanding (MoU) was signed between MANAGE and the Department of Agriculture, Govt. of Odisha for capacity building activities & supporting other initiatives of Government of Odisha in the fields of e-Governance, CCKN-IA, escalation of Kisan Call Center, use of ICT in Agriculture, etc.

Institutional Innovations and News

1.18 Help Desk for Farmers Launched

Realizing the need for providing the right information to farmers on scientific and profitable methods of cultivation and counsel them to face challenges, MANAGE launched a Farmers Help Desk with an objective to provide necessary advisory to farmers through print and electronic media.

1.19 Certified Crop Advisor

MANAGE has come up with a program to link Extension Officers to ICAR Institutes through "Certified Crop Advisor" program. Here the officers are exposed to a three months online course, 15 days attachment to ICAR organizations on a particular crop along with handholding support.

1.20 Mobile App for MANAGE Training Programs

MANAGE developed an Android Mobile App for managing its training programs. Through this App, agricultural officers can browse details of MANAGE calendar training programs, choose the relevant training program and register for it through the same App. As soon as the details are stored in the database, an email is sent to the course coordinator and also to the applicant officer.

1.21 Incubation Centre at MANAGE

MANAGE entered into MoU with RenB, Mumbai to set up a Start-Up Incubator Center for PGDM-ABM students at MANAGE to maximize the exposure and offers an opportunity for students and alumni to help them to start a business based on their ideas and innovations. This will provide a platform for students and alumni to convert their ideas and innovations into a Start-Up venture.

Visitors

1.22 Senior administrators and faculty from Agriculture and Forestry University (AFU), Nepal visited MANAGE on 8th September, 2015. This visit was a part of Agricultural Innovation Partnership (AIP) project of USAID being implemented by Cornell-Sathguru, Hyderabad to build institutional capacity, develop human resources and improve organizational functioning.

1.23 An 11 member team from Afghanistan visited MANAGE on 1st October 2015. The visit was sponsored by the International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA). The team had representatives from ICARDA and Ministries dealing with Water Resources, Watersheds, Natural Resources, Forestry from Afghanistan.

1.24 Shri Rajendra Singh, popularly known as "Waterman of India" visited MANAGE on January 20, 2016. Shri Rajendra Singh is a well-known water conservationist working in Alwar district of Rajasthan and heads an NGO called 'Tarun Bharat Sangh' (TBS). He addressed executives and MANAGE Faculty and highlighted the importance of water conservation.

Shri Rajendra Singh addressing executives

2 Training Programs 2015-16

2.1 Organizing need-based training for senior and middle level agricultural extension functionaries is an important mandate of MANAGE. The Institute conducts training programs, workshops and refresher programs for the public extension functionaries working in agriculture, horticulture, animal husbandry, fisheries, sericulture departments of different States and UTs, scientists of Krishi Vigyan Kendras (KVK), ICAR Institutions and State Agricultural Universities (SAUs) and for the NGOs, private sector executives and agripreneurs. The programs provide conceptual understanding with an application orientation on various current themes in Agricultural Extension Management. The programs are designed and delivered to prepare the extension functionaries and other professionals to cope with challenges and effective implementation of flagship programs of the Government.

2.2 The Annual Academic Calendar is prepared based on the proceedings of the Annual Training Planning Workshop. In this workshop, the Directors of SAMETIs & EEIs, Training Coordinators / Representatives of Department of Agriculture & Allied areas and scientists of ICAR / SAU participate and provide valuable inputs. The workshop provides a platform for exchange of information on training needs, themes of the programs proposed and the innovative approaches followed and probable collaborations. The themes and content of the programs are weaved around the themes of eight centres of MANAGE. A total of 188 programs were proposed for the year 2015-16.

Methodology

2.3 A six day program was offered for the On-campus programs where in five days were earmarked for the core theme areas of the program and one day was exclusively devoted to soft skills covering aspects like motivation, communication, leadership, etc. A half-day module on Gender Main streaming in Agriculture and another half day module for ICT in Agriculture was included in most of the On-campus programs. The Off-campus programs ranged from 3-4 day duration depending upon the requirement of the theme.

2.4 Participatory methodology was employed to make the learning process experiential which results in better retention and application. Training methods such as lecture-cum-discussions, case studies, success stories, group exercises, management games, etc were used to make the learning useful for field application. Field and exposure visits were also organized to provide first-hand knowledge on the best practices.

Annual Training Planning Workshop

Training on Soft Skills

Training programs conducted during 2015-16

2.5 During the year 2015-16, a total of 198 programs were organized covering 5129 participants. The Centre-wise details of Training, Refresher Programs and workshops are given in the Table

Sl. No.	Name of the Centre	Programs organized			Total Programs Organized	No. of Participants
		Training programs	Workshops	Refresher programs		
1.	Center for Agricultural Extension Policy, Reforms and Processes	17	-	-	17	435
2.	Center For Agri-institution Capacity Building	21	1		22	580
3.	Center for Agricultural Markets, Supply Chain Management and Extension Projects	21	2	10	33	888
4.	Center for Allied Extension	15	-	-	15	406
5.	Center for Knowledge Management, ICT and Mass Media	35	3	10	48	1075
6.	Center for Agripreneurship, Youth and Public Private Partnership	6	2	20	28	744
7.	Center for Women and Household Food and Nutritional Security, Urban Agriculture & Edible Greening	16	1	-	17	398
8.	Center for Agrarian Studies, Disadvantaged Areas, NRM Extension and Social Mobilization	17	1		18	603
	T O T A L:	**147**	**10**	**41**	**198**	**5129**

The above programs also include the consultancy programs conducted for CARE-India and Coconut Development Board.

International Programs

2.6 MANAGE organized the Fourth U.S.-India-Africa Triangular International Training Program on New Dimensions in Agricultural Extension Management for 39 executives of Kenya, Liberia and Malawi during 16 July, 2015 to 13 September, 2015.

This two-month duration international program was an outcome of the partnership between India and U.S., supported by the U.S. Government's Global Hunger and Food Security Initiative 'Feed the Future'. The partnership aims to improve the agricultural productivity and support market institutions in Kenya, Liberia and Malawi.

Subsequent to completion of US-India-Africa Triangular International Training Program, as part of Participant Survey, the following three National Conventions were organized at Kenya, Liberia and Malawi.

1. National Convention in Kenya. 24th November, 2015 at Nairobi, Kenya
2. National Convention in Liberia. 27th November, 2015 at Monrovia, Liberia
3. National Convention in Malawi. 27th November, 2015 at Lilongwe, Malawi

New Themes initiated

2.7 MANAGE initiated the following new programs during the year:

Induction program for Newly Recruited Functionaries in Agriculture, Horticulture and Veterinary Departments

Green House Cultivation and Maintenance for Farmers

Industry oriented Agri Skill Development for Rural Youth

Refresher Training Program on Plant Health Management for extension functionaries and faculty of Nodal Training Institutions under AC&ABC Scheme in collaboration with NIPHM

Roof Top / Backyard Gardening for the residents of Hyderabad

Training Programs Organized by various Centres

1. Center for Agricultural Extension Policy, Reforms and Processes

A total of 17 programs of various durations including International programs for 60 days, Induction-cum Refresher programs for the officers of Department of Agriculture & Cooperation were organized by this Centre covering 435 executives. The details of the programs and number of executives are given in the following table:

Sl. No.	Title of the Program	No. of Programs	No. of Participants
1	Farmer-to-Farmer Extension	2	48
2	Farm Journalism Skills for Extension Functionaries	1	26
3	Agricultural Extension Management for the PGDPHM students of NIPHM	1	10
4	Innovative Extension Approaches	2	46
5	Trainers Training Program on Re-Visiting of SREP	2	79
6	Fourth U.S.-India-Africa Triangular International Training Program on New Dimensions in Agricultural Extension Management for extension functionaries of Africa and Asia	1	39
7	Refresher Training on Extension Reforms for SAMETI & ATMA Officers of Goa	1	37
8	Planning and Management for Sustainable Agricultural Livelihood	1	29
9	National Convention on US-India-Africa Triangular International Program at Nairobi	1	24
10	National Convention on US-India-Africa Triangular International Program at Monrovia, Liberia	1	28
11	National Convention on US-India-Africa Triangular International Program at Lilongwe, Malawi	1	29
12	Induction-cum-Refresher Program for the officers of Department of Agriculture & Cooperation	3	40
	Total	**17**	**435**

2. Center for Agri Institution Capacity Building

During the year, a total of 22 programs covering 580 executives were conducted by the Centre. The themes of the programs and the number of executives who attended are presented in the table below:

Sl. No.	Title of the Program	No. of Programs	No. of Participants
1	Self-Management through Personal Profiling	3	83
2	WTO and its Implications on Indian Agriculture	2	32
3	Training of Trainers on Planning and Management of Integrated Watershed Management Projects (IWMP)	2	52
4	Work Ethics for Developmental Professionals	2	60
5	Professional Skills for Trainers of Extension Institutes of Agriculture and Allied Departments	3	61
6	Training of Trainers on Formation and Management of Producers Groups (PGs) and Organizations	1	23
7	Effective Communication for Extension Functionaries	2	46
8	Management Games for Trainers	1	20
9	Managerial Skills for Convergence in Agricultural Extension	3	86
10	Management Development Program for Trainers	1	38
11	Facilitator Training on Agri-Entrepreneurship for CARE India Bhubaneshwar	1	10
12	Annual Training Planning Workshop	1	69
	Total	**22**	**580**

3. Center for Agricultural Markets, Supply Chain Management and Extension Projects

A total of 33 programs including three National workshops were organized by this Centre covering 888 executives. The details are presented in the following table:

Sl. No.	Title of the Program	No. of Programs	No. of Participants
1	Agricultural Marketing - the New Paradigms	6	160
2	Linking Farmers to Market	4	160
3	Supply Chain Management in Agriculture and Allied Sectors	5	123

Sl. No.	Title of the Program	No. of Programs	No. of Participants
4	Induction Training Program on Plant Health Management and Agricultural Extension	2	44
5	Project Planning and Management	1	30
6	Orientation Program for the Nodal Officers / Facilitators on Implementation of DAESI Program	1	32
7	Training program for the Directors of Coconut Producer Companies	2	48
8	National Workshop on Going beyond Production - Exploring "Market Focus" in Agricultural Extension	1	36
9	National Workshop on Sensitizing stakeholders on the Operational Guidelines of DAESI Program	1	26
10	Refresher Training Program for Input dealers trained under DAESI Program	10	229
	Total	**33**	**888**

National Workshop on Exploring Market Focus in Agricultural Extension

4. Center for Allied Extension

The Centre organized 15 training programs including 6 induction programs on the following themes covering 406 participants.

Sl. No.	Title of the Program	No. of Programs	No. of Participants
1	Extension Management Approaches for Meghalaya	1	10
2	Induction program for Newly Recruited Functionaries in Agriculture and Horticulture Departments	5	126
3	Farm Business Management for Animal Husbandry / Horticulture Sector	3	68
4	Extension Management Approaches for Promotion of Fisheries	1	25
5	Green House Cultivation and Maintenance for Farmers of Medak District	1	59
6	Workshop cum Training on Enabling extension Functionaries to address Field Level Problems in Animal Husbandry	1	37
7	Green House Cultivation and Maintenance for Farmers of Rangareddy District	1	40
8	Orientation Program on Documentation of the Re-Visited SREP for Telangana State	1	17
9	Induction Program for newly Recruited Functionaries in Animal Husbandry Departments	1	24
	Total	**15**	**406**

5. Center for Knowledge Management, ICT and Mass Media

The centre conducted 48 programs including three National workshops during the year covering 1075 executives. The details of the programs are presented in the table below:

Sl. No.	Title of the Program	No. of Programs	No. of Participants
1	Community Radio for Agricultural Development	3	67
2	Agricultural Knowledge Management	5	165
3	Trainers Training Program on mKisan and EMS	2	22
4	Social Media for Effective Sharing of Agricultural Information and Knowledge	4	115

Sl. No.	Title of the Program	No. of Programs	No. of Participants
5	Application of ICTs in Modified Extension Reforms Scheme	6	194
6	Writing for Print Media and Electronic Media	2	17
7	Application of Remote Sensing and GIS in Agricultural Development	2	49
8	Project Planning and Management using MS Project	2	40
9	Improving e-Governance in Agriculture	2	58
10	Process Documentation for Agricultural Innovations	4	85
11	ICTs in Agricultural Extension Management	2	52
12	Applications of ICTs under National Mission on Agricultural Extension and Technology	1	27
13	National Workshop on CCKN-IA	1	29
14	National Workshop on ICTs in Agriculture	1	42
15	National Workshop on Community Radio	1	17
16	Training - cum - Review Workshops for Kisan Call Centres experts - Level I and Level II	10	96
	Total	**48**	**1075**

6. Center for Agri-preneurship, Youth and Public Private Partnership (PPP)

The centre has conducted 28 programs including two Workshops, covering 744 executives. The details are given below:

Sl. No.	Title of the Program	No. of Programs	No. of Participants
1	Public Private Partnership in Agricultural Extension Management	2	42
2	Refresher Program on Agripreneurship Development among Rural Youth through establishment of Agri-Business Centres on PPP Mode	1	13
3	Orientation Program on Agripreneurship Development among Rural Youth through establishment of Agri-Business Centres on PPP Mode	1	32
4	National Diagnostic Workshop for Establishment of Agri-Ventures under AC&ABC	1	33
5	Study-cum-exposure visit of Kerala Officials on Implementation of AC&ABC in Maharashtra	1	6
6	National Level Nodal Officers Workshop under AC&ABC Scheme	1	64
7	Industry oriented Agri Skill Development for Rural Youth	1	39
8	Refresher Training Programs for Established Agripreneurs on Business Expansion Capabilities under AC&ABC	19	491
9	Refresher Training Program for Established Agripreneurs on Agripreneural Opportunities in Water Management under AC&ABC Scheme in collaboration with LINDSAY, USA & Wageningen University, Netherlands	1	24
	Total	**28**	**744**

7. Center for Women and Household Food and Nutritional Security, Urban Agriculture & Edible Greening

A total of 17 programs including a national workshop were organized by the Centre covering 398 executives. The themes of the programs are presented in the table below:

Sl. No.	Title of the Program	No. of Programs	No. of Participants
1	Refresher Training Program on Plant Health Management for extension functionaries and faculty of Nodal Training Institutions under AC&ABC Scheme in collaboration with NIPHM	4	80
2	Training Program on Urban Agriculture	1	27
3	Food and Nutritional Security of the Rural Households - Role of Women	1	21
4	Management Development Program for Women in Development Sector	1	22
5	Gender Budgeting for Mainstreaming Women in Agriculture	2	58
6	Climate Change and Agriculture	2	26
7	Training on Roof Top / Backyard Gardening for the residents of Hyderabad	2	82
8	Food, Nutrition and Health Concerns of the Rural Households - Role of Women	1	23
9	TOT on Gender Budgeting - Gender Mainstreaming	1	14
10	Review Workshop on Post Graduate Diploma in Agricultural Extension Management (PGDAEM)	1	19
11	Workshop cum Training on Sensitisation to DAESI program	1	26
	Total	**17**	**398**

8. Center for Agrarian Studies, Disadvantaged Areas, NRM Extension and Social Mobilization

The centre has conducted 18 programs covering 603 executives, as may be seen in the table below:

Sl. No.	Title of the Program	No. of Programs	No. of Participants
1	Training cum workshop on National Mission on Sustainable Agriculture (NMSA)	4	111
2	Development and Sustainability of Farmer Producer Organizations	4	142
3	Revitalization of Rainfed Agriculture (RRA) with special reference to Fisheries theme	3	84
4	Revitalization of Rainfed Agriculture (RRA) with special reference to Livestock theme.	2	64
5	Monitoring and Evaluation of Agriculture Projects	2	62
6	Writeshop on Documentation of Best Practices for Rainfed Agriculture	1	61
7	Training cum workshop on Integrated Watershed Management Program	1	39
8	Training cum workshop on Issues and Challenges of Farmer Producer Companies	1	40
	Total	**18**	**603**

3 Research

3.1 Research at MANAGE focuses on themes of contemporary relevance in areas relating to agricultural extension management, information and communication technology applications, gender issues, agricultural marketing, public-private partnership, natural resource management etc. MANAGE also takes up evaluation of various Government programs/projects in order to assess their impact. Action research is taken up to pilot-test ideas, concepts and technologies in field situations. Consultancy is also provided to agriculture and allied departments/agencies for developing strategies and programs in response to their request.

3.2 Research and Consultancy studies during 2015-16

1. Impact of the Interventions made for Gender Mainstreaming under Extension Reforms Scheme (Completed)
2. Agripreneurship development among rural youth in consortium mode (Completed)
3. A critical analysis of women entrepreneurs in farming sector (In Progress)
4. Design and Development of e-TNA for Extension Functionaries of Agriculture and Allied Departments (In Progress)
5. Role of Regulation in Adopting Modern Instruments of Agricultural Marketing - A comparative study (In Progress)
6. Analysis of Extension Approaches in Allied sectors (In Progress)

1. Impact of the Interventions made for Gender Mainstreaming under Extension Reforms Scheme

This study was taken up to assess the impact of the ATMA interventions on women farmers. Based on the physical and financial performance of the states, six states were selected namely, Jharkhand, Assam, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra and Uttarakhand. One district from each state and three to six blocks from each district were selected for interviewing women farmer beneficiaries. The study was completed and the final report submitted in July 2015.

The findings of the study include: Proper selection of women farmer representative at GB and BFAC level is very essential in addressing issues. It is recommended that the official should focus on proper selection and orientation trainings to BFAC women representatives about the Extension Reforms Scheme and their role in its implementation, so that, these women can play an active role in mobilizing women groups, identifying their needs, giving feedback in the meetings and ensuring that the women farmer needs are incorporated in action plans and budgets are earmarked for addressing these needs.

The study identified several good practices and approaches to mainstream gender issues under Extension Reforms. Women farmer representatives played main role in selection of villages, beneficiary women farmers followed by formation and nurturing of groups, facilitation in organizing extension activities and providing feedback to solve identified problems. Progressive women farmers when used as trainers (under Farmer to Farmer Extension Concept) in Maharashtra, Madhya Pradesh etc., found successful in reaching out to more women farmers. Women friendly tools such as conoweeder, paddy drum seeder, palmray fibre extractor, cocoa harvester, seed treatment drum, spiral soyabean separator etc. were given to the women / women groups through ATMA in different states and the women groups have felt that these technologies have benefited them by reducing the drudgery in handling the activity, saved time, improved the efficiency of the women farmers. It is recommended to popularize these tools and technologies on a large scale to benefit more number of women farmers. Group activities and collective marketing was done by few women

groups in the study area, which has benefitted the women. It is suggested to strengthen and replicate these good practices in other states.

2. Agripreneurship development among rural youth in consortium mode

MANAGE and Syngenta Foundation India (SFI) signed a MoU for operationalization of Action Research Programme titled "Agri-entrepreneurship Development among Rural Youth through Consortium Mode". The main aim of the programme was to transform unemployed rural youth into Agripreneurs providing value added extension services to farmers. Syngenta Foundation India is the lead of consortium, capacity building support was provided by MANAGE, Smart Steps a consultancy firm provided handholding support, IDBI Bank supported Agripreneurs with loans and service area farmers were linked to enterprises through PRADAN. MANAGE designed and developed a training module to help participants learn how to identify appropriate business opportunity, preparation of Detailed Project Report, explore the linkages between Agripreneurs and all the resources, services needed to successfully launch and sustain a small enterprise.

A total of 29 Agripreneurs (7 from Maharashtra, 9 from Jharkhand, 6 from Madhya Pradesh, 2 from Andhra Pradesh, 3 from Orissa and 2 from West Bengal) underwent a training conducted by MANAGE during 28th April - 7th May, 2014 at PRADAN, Madhya Pradesh. Out of 29 participants 22 candidates started Agri-ventures dealing with Agri-input shop, vegetable nursery, Seed production unit, Agri- consultancy etc. In the second phase of the action research, Syngenta Foundation-India and MANAGE jointly organized four days Refresher training programme during 23rd to 26th September, 2015 at BCT-KVK, Haripuram, Visakhapatnam, Andhra Pradesh for established Agripreneurs.

Impact of the action research programme is seen through important initiatives. These included: Thirteen candidates Agri-ventures, dealing with Agri-input shop, vegetable nursery, Seed production unit etc; SFI provided seed money of Rs.30,000/- for each Agripreneur to start business (purchase of basic equipment like weighing machines, set-up a shop, licenses); SFI signed an MoU with Industrial Development Bank of India (IDBI) Bank for extending loan to Agripreneurs; all Agripreneurs applied for licenses. They received Principal Certificates from major companies to trade their products.; Most of the Agripreneurs registered as Business Correspondent (BC) with respective IDBI Branches; A total of 150-200 farmers under each Agripreneur registered with IDBI and all registered farmers were given Kisan Credit Cards (KCC); Agripreneurs received commission of 0.5 per cent for every transaction that farmers undertook (deposit or withdrawal); and all Agripreneurs were connected to wholesale distributors (Agri-inputs), where Agripreneurs obtained at least Rs.2-3 lakhs of material on credit (on SFI's guarantee).

3. A critical analysis of women entrepreneurs in farming sector

The objectives of this study were to document success stories and analyze the factors contributing for success of the enterprise in farming sector among women, assess economic and social impact of entrepreneurship on women, analyze the gender based barriers in starting and sustaining the enterprises in farming sector among women and suggest strategies for replicating and up scaling the entrepreneurial among women in farming sector.

Three states namely Andhra Pradesh, Maharashtra and Tamil Nadu, were selected. From each state one district was selected for interviewing the women entrepreneurs in the farming sector. The data entry and analysis has been completed and the report is under preparation.

4. Design and Development of e-TNA for Extension Functionaries of Agriculture and Allied Departments

Training needs assessment (TNA) is an integral process of training aimed at identifying the expressed or implied organizational needs that

could be addressed by conducting appropriate training programs. Training needs assessment is a three phase process which includes collection of information, analysis and design of a training program. The hindrances of performing training needs assessment through a survey method (design, canvassing a questionnaire - paper and pencil method) could be overcome by performing the assessment online.

The obvious advantages due to the transition from conventional to online method include significant reduction in cost and time incurred and moreover, the respondent could easily undertake the self-assessment at his workplace or at the place which he/she may find comfortable and at their own time. With such perceived benefits in terms of cost, time, nature (dynamical) and options in ease of use, effectiveness, the present research study aims to: design and develop a platform for e-TNA (training needs self-assessment online) for agricultural officers at district level; find self-perception of agricultural officers on their training needs and measure the intensity of their self-perception; and find out the perceptions of HoDs, immediate supervisors on their subordinates' training needs. During the period under review, an online e-TNA proforma for assessing training needs of functionaries in the agricultural department has been designed and is being pretested in Telangana, Ranga Reddy district. Based on the feedback the e-TNA proforma will be revised.

5. Role of Regulation in Adopting Modern Instruments of Agricultural Marketing - A comparative study

This study aims at ascertaining the impact of market regulation on overall development of agriculture. The objectives of the study are to assess the level of regulation in Agricultural Marketing in the States of Karnataka and Odisha, find out the relation between the degree of regulation with factors such as crop diversification, export, processing, farmers income and Good Marketing Practices, establish the relation between the degree of regulation and the readiness of a State to absorb the modern instruments of agricultural marketing and suggest measures to overcome the impediments for absorption of modern instruments in the agricultural marketing system.

6. Analysis of Extension Approaches in Allied sectors

The objectives of this study are to explore extension approaches and methods followed by the line department officials, private and other extension service providers, NGOs and co-operatives in the allied sectors, assess the level of knowledge of officials about various extension approaches, know the perception of farmers towards the delivery of extension services, understand constraints in adoption of extension approaches and in convergence of extension services and suggest strategies for strengthening extension delivery mechanism in allied sectors.

4 Schemes

Agri-Clinics and Agri-Business Centres (AC&ABC) Scheme

4.1 Inadequate quality manpower in extension has been a bottleneck in effective delivery of extension services. At the same time, large number of agriculture professionals have not been finding gainful employment. Therefore, the Agri-Clinics and Agri-Business Centres (AC&ABC) Scheme was launched by the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India during 2002 to address these issues.

Apps on 'Cotton crop' and 'IPM' developed by Mr. Parikshit D. Bokare, Agripreneur, Ahmednagar, Maharashtra

4.2 The objectives of the AC&ABC Scheme are as follows:

1. To supplement the efforts of public extension by necessarily providing extension and other services to the farmers on payment basis or free of cost, as per the business model of the agripreneur, local needs and affordability of the target group of farmers;

2. To support agricultural development;

3. To create gainful self-employment opportunities to unemployed agriculture and allied graduates, agriculture diploma holders, intermediate pass-outs in agriculture, and biological science graduates with PG in Agri-related courses.

4.3 MANAGE is entrusted with the responsibility of coordinating training and handholding of the selected agricultural professionals under the scheme. MANAGE has been arranging 2-month free residential training in Agri-entrepreneurship development for eligible agricultural professionals in their respective states

Shri. Avinash Salunkhe, Agripreneur, Shrirampur, Maharashtra conducting training on Hydroponic Cultivation for women SHG

through a network of 73 Nodal Training Institutes (NTIs). The training is followed by one-year handholding support from the NTIs for establishing Agri-ventures. The trained agripreneurs are also assisted through start-up loans and credit-linked back-ended composite subsidy through banks and NABARD.

Salient features of the Scheme

4.4 Graduates in agriculture and allied disciplines from State Agricultural Universities (SAUs) and Central Agricultural Universities / Universities recognized by ICAR/UGC; Diploma Holders in agriculture and allied subjects from SAUs; Biological Science Graduates with post-graduation in agriculture and allied subjects; and candidates at intermediate level agriculture related courses with at least 55% marks are eligible to avail the benefits under the scheme.

4.5 The candidates are selected through a screening process at the NTI level involving stakeholders such as State Agriculture Department, NABARD, NTI, MANAGE, KVK, Bank and Agri-Business Company.

4.6 During the training, candidates are imparted basic knowledge on agricultural extension & Agri-entrepreneurship, exposed to Agri-ventures, guided to choose a project based on market survey and provided an opportunity for hands-on work experience, thus enabling them to prepare a Detailed Project Report (DPR) for submission to the banks. After completion of the

Dr. Jehrul Islam, Agripreneur, Assam, constructed a fish pond for conservation of indigenous carps

training, one-year handholding support is provided through NTIs to ensure successful establishment of Agri-ventures.

4.7 The project cost ceiling under the AC&ABC scheme for the purpose of subsidy is Rs.20.00 lakhs for individual projects and Rs.100.00 lakhs for group projects (5 members). The subsidy for general candidates is 36% of the Total Financial Outlay (TFO) and 44% for women candidates/SC/ST beneficiaries and candidates from North Eastern and Hill States. The loans are provided through scheduled banks, and credit-linked back-ended composite subsidy is routed through NABARD.

Progress of AC & ABC during 2015-16

4.8 During the year, 5258 candidates were trained through 73 Nodal Training Institutes (NTIs) and 2587 Agri-ventures were established, under 28 categories of activities, thus achieving a success rate of 49.22%. The details are in the Table:

Shri Hardik Rokad, Agripreneur, Amreli, Gujarat, providing consultancy on protected cultivation in Horticulture to farmers

Progress of AC&ABC Scheme during 2015-16

Sl. No.	State	No. of Candidates Trained	No. of Agriventures Established	No. of NTIs
1.	Andhra Pradesh	22	33	2
2.	Arunachal Pradesh	0	0	1
3.	Assam	69	11	1
4.	Bihar	279	93	2
5.	Chhattisgarh	114	27	3
6	Delhi	10	0	0
7.	Gujarat	154	41	2
8.	Haryana	62	17	1
9.	Himachal Pradesh	1	0	0
10	Jammu and Kashmir	88	5	1
11.	Jharkhand	49	13	2
12	Karnataka	132	88	7
13.	Kerala	2	0	1
14.	Madhya Pradesh	209	106	5
15.	Maharashtra	1488	753	15
16.	Manipur	24	3	1
17.	Meghalaya	1	0	0
18.	Nagaland	0	0	1
19.	Orissa	15	0	1
20.	Pondicherry	23	9	1
21.	Punjab	35	17	1
22.	Rajasthan	212	93	3
23.	Sikkim	0	1	1
24.	Tamil Nadu	806	426	6
25.	Telangana	58	9	3
26.	Uttar Pradesh	1197	743	8
27.	Uttaranchal	43	40	1
28.	West Bengal	165	59	3
	Total	**5258**	**2587**	**73**

Activity-wise categorization of Agri-ventures established during 2015-16

Sl. No.	Agri-venture	Number
1.	Agri-Clinics	444
2.	Agri-Clinics and Agri-Business Centres	462
3.	Animal Feed Unit	2
4.	Bio-fertilizer Production and Marketing	4
5.	Contract Farming	1
6.	Cultivation of Medicinal Plants	1
7.	Farm Machinery Unit	133
8.	Fisheries Development	37
9.	Floriculture	10
10.	Horticulture Clinic	32
11.	Landscaping + Nursery	2
12.	Nursery	50
13.	Organic Production/ Food Chain	1
14.	Pesticides Production and Marketing	5
15.	Value Addition	20
16.	Fishery clinic	1
17.	Seed Processing and Marketing	18
18.	Soil Testing Laboratory	1
19.	Vegetable Production and Marketing	50
20.	Vermicomposting / Organic manure	12
21.	Veterinary Clinics	27
22.	Crop Production	6
23.	Dairy/Poultry/Piggery/Goatery	1227
24.	Rural Godown	2
25.	Production & Marketing of Bio-Control Agents	4
26.	Sericulture	6
27.	Mushroom Cultivation	16
28.	Apiary	13
	Total	**2587**

Progress during 2002-2016

4.9 Since inception till 31st March 2016, a total of 47,815 candidates were trained and 20,450 Agri-ventures were established, thus achieving a success rate of 42.76%. The details are as follows:

Progress of Agri-Clinics and Agri-Business Centres Scheme during 2002 -2016

Sl. No.	State	No. of Candidates Trained	No. of Agri-ventures established
1	Andhra Pradesh	846	317
2	Arunachal Pradesh	32	3
3	Assam	632	206
4	Bihar	3422	1246
5	Chandigarh	3	1
6	Chhattisgarh	543	253
7	Delhi	26	3
8	Goa	9	4
9	Gujarat	1366	515
10	Haryana	614	205
11	Himachal Pradesh	418	108
12	Jammu and Kashmir	1333	176
13	Jharkhand	632	162
14	Karnataka	3102	1295
15	Kerala	184	51
16	Madhya Pradesh	1399	576
17	Maharashtra	10994	5178
18	Manipur	437	128
19	Meghalaya	11	3
20	Mizoram	34	0
21	Nagaland	174	21
22	Orissa	521	106
23	Pondicherry	124	77
24	Punjab	566	203
25	Rajasthan	2764	1012
26	Sikkim	9	1
27	Tamil Nadu	5493	2914
28	Telangana	1007	362
29	Tripura	2	1
30	Uttar Pradesh	9883	4929
31	Uttaranchal	414	138
32	West Bengal	821	256
	Total	**47815**	**20450**

Result Demonstration conducted by Shri Basaveshwar Souhardha Sahakari Niyamita, Hubli, under guidance of Shri. Chinnappa Zalaki, Agripreneur, Hubli, Karnataka

Progress of the Scheme in Jammu and Kashmir

4.10 During the year, 88 candidates were trained, and 5 candidates have established Agri-ventures through one NTIs in Jammu and Kashmir. Since inception, 1333 candidates were trained and 176 candidates have established Agri-ventures.

Progress of the Scheme in the North-Eastern States

4.11 In the North-Eastern States, five training centres are imparting training to agricultural professionals under the scheme. During the year, 94 candidates were trained and 14 candidates have established Agri-ventures. Since launching of the Scheme, 1331 candidates were trained and 363 have established Agri-ventures.

Publication of Agripreneur e-Bulletin:

4.12 In order to reach a large number of stakeholders in a cost effective manner, MANAGE published 12 issues of Agripreneur, a monthly e-Bulletin and circulated to 18,091 readers across the globe. This E-bulletin is translated to Hindi and published as Krishi Udyami. All the bulletins are available at www.agriclinics.net.

Dedicated website for Agripreneurs

4.13 A website www.agriclinics.net is updated regularly by MANAGE for the benefit of all stakeholders of the scheme. The website provides real time data on Agripreneurs trained, established, state and district wise categorization, pending projects, bulletins, success stories of Agripreneurs and Videos, latest government orders and all scheme related information.

Toll-free Helpline for Agripreneurs

4.14 In order to enhance the quality of services provided to all stakeholders of the AC&ABC Scheme, and to obtain feedback from all Stakeholders, MANAGE launched a toll-free helpline 1800-425-1556 in October, 2013.

The helpline assists the callers on information relating to:

1. NTIs offering AC&ABC training in their State
2. Eligibility criteria to undergo training under the Scheme
3. Loans and subsidy
4. Refresher Training Programmes

The Call Centre also receives feedback/suggestions on training and handholding, and updates the status of Agri-ventures and the contact details of Agripreneurs.

Refresher Training Programs in National Institutes

4.15 During 2015-16, MANAGE organized 20 Refresher Training Programs covering 513 established Agripreneurs across the country. The programs were conducted at National Institute of Rural Development & Panchayat Raj (NIRDPR), Hyderabad, National Institute of Plant Health Management (NIPHM), Hyderabad, State Bank Institute of Rural Development (SBIRD), Hyderabad, National Dairy Research Institute, Karnal, Extension Education Institute (EEI), Jorhat and Deep Narayan Singh Regional Institute of Cooperative Management (DNSRICM), Patna. The training focused mainly on specific sectors besides, sensitization on the revised AC&ABC guidelines, business networking among Agripreneurs and preparation of bankable projects for new / diversified / enhanced business activities of Agripreneurs.

Agripreneurs in a Refresher Program held at NDRI, Karnal, Haryana

National Level Nodal Officers Workshop under AC&ABC

4.16 During the year, MANAGE organized National Level Nodal Officers Workshop during 21-22 December, 2015 at MANAGE, Hyderabad, for Nodal Officers and Training Coordinators of NTIs. The workshop focused on reviewing the performance of the Nodal Officers of the NTIs, strengthening the AC&ABC Scheme based on the feedback of the NTIs, effective coordination between the Stakeholders such as DAC, MANAGE, Banks, NABARD, NTIs, Agripreneurs so as to refine the policies and redesign the scheme for longtime extension services to the farmers.

National Level Diagnostic Workshop for Establishment of Agri-ventures under AC&ABC scheme

4.17 A one-day national level diagnostic workshop for establishment of agro-ventures under AC&ABC scheme was held on 11th December, 2015, to understand the reasons behind non establishment of Agri-ventures by trained Agripreneurs. The delegates from Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, NABARD, and Nodal officers, un-successful Agripreneurs participated in the workshop. The workshop critically diagnosed the problems behind failure of Agri-ventures and worked on action to be taken.

Study-cum-Exposure visits

4.18 SAMETI, Kerala has evinced interest in partnering with MANAGE to become an NTI in the state of Kerala as part of AC&ABC scheme. Taking a proactive approach to strengthen AC&ABC scheme in that state, MANAGE arranged a study cum exposure visit for 6 Kerala State Agriculture department officials during 16th - 21st February, 2016, to Maharashtra, for understanding the various facets of the AC&ABC Scheme including its functioning and field level practical issues. During the visit, the officials interacted with all the nodal officers of different NTIs of Maharashtra and gained insight from their experiences, with regard to the successful conduct of the scheme. The officials also visited successful Agripreneurs in and around Pune to gain first-hand knowledge with regard to functioning and objectives of the scheme and also interacted with officials of ATMA. The visit ended with preparation of action plan to be implemented in Kerala.

Participation in India International Trade Fair (IITF)

Hon'ble Shri. Radha Mohan Singh, Union Minister of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India and Shri. Narendra Bhooshan IAS, Joint Secretary (Agril. Extn.), GoI interacting with Agripreneur

4.19 Ten Agripreneurs, from seven states participated in the IITF held during 14-27th November, 2015 at New Delhi, facilitated by MANAGE and the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, for creating awareness among various stakeholders about the potential of Agri-Entrepreneurship and its role in agricultural development.

Participation in Krishi Unnati -2015

4.20 Five Agripreneurs, from four states participated in the Krishi Unnati-2015 held at New Delhi, facilitated by MANAGE and the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India.

Smt. V. Usha Rani IAS, Director General, Dr. P. Chandra Shekara, Director (Agril. Extn), MANAGE with Agripreneurs in AC&ABC stall, Krishi Unnati-2015, New Delhi

Honors for Agripreneurs

4.21 Outstanding Agripreneurs honoured during the year 2015-16 for their contribution to Agricultural Extension.

Smt. M. Saritha Reddy, Hyderabad, Agripreneur honored with Best Women Entrepreneur of Telangana State

MS Swaminathan Foundation, Chennai, Tamil Nadu recognized Shri Virendra Singh, Agripreneur, Bareli, Uttar Pradesh and awarded him with a title "Torch Bearer of the Rural Knowledge Revolution". Jamsetji Tata National Virtual Academy also honored him with a fellowship for his invaluable services

Shri Sangappa Sankanagowda, Karnataka, an Agripreneur was felicitated by the Federation of Karnataka Chamber of Commerce and Industry (FKCCI). He won the first prize of Rs.1.5 Lakh in Green summit 2014 for designing and manufacturing of Solar Sprayer

Shri S. M. Dhanad, Agripreneur, Jalgaon, Maharashtra,honored with Maharashtra Bhushan Award

Mr. Rahul Belsare, Agripreneur, Amravati, Maharashtra honored with Yuva Krishi Award of Maharashtra State

Kisan Call Center

4.22 The Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, Govt. of India launched Kisan Call Centers (KCC) in 2004 with an objective to respond to the issues raised by the farmers across the country, in respective local languages. Queries related to agriculture and allied sectors are being addressed by Subject Matter Specialists from the State Agricultural Universities and the State Departments concerned. There are 25 such Call Centers operational across the country in different states.

Operational Mechanism

4.23 The KCC operates at three levels viz., Level-I, Level-II and Level-III. In order to access this service, the farmer is required to dial a toll-free number **1551** (from landline) or **1800-180-1551** (from mobile)**.** Once the farmer's call lands at the designated Call Center for the State, the Level-I functionaries, record the basic information of the farmer and respond to the farmer's query.

4.24 If the queries cannot be answered at Level-I, those relating to Crop Technology are escalated to designated Subject Matter Specialists of SAUs/ICAR, while those related to Programs/Schemes are escalated to Technical officials of State Departments of Agriculture, Animal husbandry, Horticulture, Fisheries, Marketing etc. functioning at Level-II.

4.25 If the queries cannot be answered even at Level-II, these are escalated to a Central Institute (functioning in that state) designated as Level-III by DAC, MoA, GoI, for responding to such queries within 72 hours of their receipt.

Role of MANAGE and Interventions

4.26 MANAGE has been identified as one of the Level-III institutions by Ministry of Agriculture and has the responsibility of coordinating the functioning of KCC-Hyderabad. MANAGE also organises need-based training programs for Level-I and Level-II functionaries.

Farmer Calls Received during 2015-16

4.27 The details of calls received by the KCC-Hyderabad during the year are as follows:

S. No.	2015-16 **		
	Month	Landed Calls	Answered Calls
1	April-15	31494	26644
2	May-15	27546	24481
3	June-15	38935	31888
4	July-15	44825	36262
5	August-15	51498	31399
6	September-15	59431	28526
7	October-15	53171	30575
8	November-15	60996	28957
9	December-15	41362	26458
10	January-16	38186	28609
11	February-16	28887	24700
12	March-16	20684	18940
	Total	**497015**	**337439**
	Monthly Average	**41418**	**28120**
	Daily	**1380**	**937**

**** Source: /KKMS/homepage.do**

Training Programs

4.28 Nine 'One-day Training-cum–review Workshops' were organized during the year for Level-I and Level-II functionaries of KCC-Hyderabad. These were organized at MANAGE and NIPHM. Details may be seen in the Table. MANAGE also facilitated video interactions between district-level agriculture officers and KCC functionaries on four occasions to discuss field level problems and solutions.

S.No.	Date held	Venue	No. of Participants
1.	May 12, 2015	MANAGE, Hyderabad	08
2.	June 29, 2015	MANAGE, Hyderabad	08
3.	August 19, 2015	MANAGE, Hyderabad	07
4.	September 21, 2015	MANAGE, Hyderabad	08
5.	November 03, 2015	MANAGE, Hyderabad	10
6.	December 11, 2015	NIPHM, Hyderabad	12
7.	December 15, 2015	NIPHM, Hyderabad	11
8.	March 15, 2016	NIPHM, Hyderabad	12
9.	March 16, 2016	NIPHM, Hyderabad	13

Diploma in Agricultural Extension Services for Input Dealers (DAESI)

4.29 MANAGE launched a one-year "Diploma in Agricultural Extension Services for Input Dealers (DAESI)" in 2003, in order to impart relevant agricultural knowledge to the dealers to transform them into para-extension professionals and enable them to address the field level problems of farmers.

4.30 Program Objectives

To orient the input dealers on location-specific crop production technologies.

To build capacity of input dealers in efficient handling of inputs.

To impart knowledge about laws governing regulation of agricultural inputs.

To make input dealers an effective source of farm information at the village level (one stop shop) for the farmers.

Methodology

4.31 The program is organized at district level on contact class-cum-distance education mode, with field visits. DAESI has been designed in such a way that the input dealer can pursue the program without adversely affecting his day-to-day business. The program is spread over a period of 48 weeks, with 40 classroom sessions and 8 Field visits to various institutions and farmers' fields. The classroom sessions and field visits are conducted on Sundays or local market holidays. The field visits are intended to acquaint the input dealers with location-specific field problems and expose them to relevant technologies. They are trained to identify pests, diseases and nutritional disorders. Study material is provided in local language and multi-media instructional devices are used in the classrooms.

Input Dealers on a field visit

Evaluation

4.32 The performance of the input dealers is evaluated based on bi-monthly quizzes, half-yearly and annual examinations and a final practical examination comprising of skill demonstration, identification of specimens of pests, diseases and nutritional disorders followed by a viva-voce. In order to qualify for the diploma, the candidate should have minimum 80 per cent attendance and secure minimum 40 per cent marks.

Course Fee

4.33 MANAGE launched the program on self-financing basis with a course fee of Rs. 20,000/- per input dealer. Realizing the importance of the program, Govt. of India has made DAESI as Central Sector Plan Scheme during October 2015, in which the course fee is subsidized to the extent of Rs. 10,000/- per input dealer by Govt. of India. However, the State Governments of Orissa and Tamil Nadu have mobilised RKVY funds for conducting DAESI program.

Program Implementation

4.34 As per the new guidelines, MANAGE is the National level Implementing agency whereas SAMETI is the Nodal agency at State Level. SAMETI in turn organizes the program through various Nodal Training Institutes such as Agricultural Colleges, KVKs, ATMAs and NGOs etc. at District Level.

Progress during 2015 -16

4.35 During 2015-16, a total of 586 input dealers have successfully completed the DAESI program in 16 batches in the states of Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Orissa and West Bengal.

Input Dealers on Exposure visit

4.36 In addition, a total of 1095 Input dealers are undergoing DAESI program in 26 batches with funding support from Central Sector Plan Scheme and RKVY funding support for one batch, in States such as Andhra Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Karnataka. An amount of Rs. 99.27 lakhs has been released to these eight states towards 50% course fee of GOI share for conduct of 26 batches of DAESI programs under Central Sector Plan Scheme.

4.37 Upscaling and strengthening DAESI

A National Workshop was organized at MANAGE on 01.12.2015 for sensitizing the Stakeholders on Implementation of DAESI as per the new guidelines in which senior Officials representing Dept. of Agriculture, SAMETIs, ATMA, representatives of NTIs/NGOs and Facilitators of DAESI participated.

A State level Workshop was organized at SAMETI, Gujarat on 11.01.2016 and the representatives of Dept. of Agriculture, SAUs and SAMETI were oriented about the new guidelines of DAESI .

A Two day Orientation training program on "Operationalization of DAESI program" was organized for the Nodal officers /Coordinators and identified facilitators of various states during 13-14 February, 2016 at MANAGE.

One day Workshop on sensitization of DAESI was organized for the Program Coordinators of KVKs, officials of ATMA, SAMETI and Dept. of Agriculture of Telangana State on 09.03.2016, at MANAGE.

During the year 2015-16 ten batches of Refresher training programs of two days duration were organized for input dealers trained under DAESI in collaboration with NIPHM covering 229 input dealers.

An amount of Rs 2.45 crores budget has been allocated to DAESI for the year 2016-17. Accordingly 62 batches have been allocated to 16 States.

Skill Training of Rural Youth (STRY) and Farmers Capacity Assessment & Certification (FCAC)

4.38 Skill Development of Rural Youth is a flagship scheme of the Government of India. The Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, in compliance with National Policy on Skill Development & Entrepreneurship 2015, has taken the initiative to implement the Skill Development Component viz., Skill Training of Rural Youth (STRY) and Farmers Capacity Assessment & Certification (FCAC) under Sub-Mission on Agricultural Extension (SAME) of National Mission on Agricultural Extension & Technology (NMAET) during 2015–16 and remaining period of XII Plan.

4.39 Skill Training of Rural Youth (STRY) is aimed at imparting skill-based training to rural youth on agri-based vocational areas in agriculture & allied areas to promote employment in rural areas and for creation of skilled manpower to perform farm and non-farm operations. Rural youth of the age group of 18 years and above with minimum qualification up to 5th standard passed (not mandatory) shall be considered for skill training. The Govt. of India has identified about 50 skilling areas spanning Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry, Dairy and Fisheries.

4.40 Farmers Capacity Assessment & Certification (FCAC) is aimed at providing recognition to the farmers who have acquired desired skills in agriculture & allied areas but continued to be treated as un-skilled, in the absence of a certificate. Farmers above the age of 18 years with minimum qualification preferably up to 5th Standard (not mandatory) shall be considered for assessment and certification.

4.41 The scheme was entrusted to MANAGE in November, 2015, for its implementation through SAMETIs of different States. The scheme is being implemented in ten identified States viz., Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Manipur, Mizoram, Odisha and Uttar Pradesh with allocation of 32.76 lakh for STRY and 17.24 lakh for FCAC. During 2015-16 five States out of ten identified States have responded to conduct the programs and accordingly funds 32.48 lakh for STRY and 9.04 lakh for FCAC have been released to these States of Arunachal Pradesh, Jharkhand, Manipur, Mizoram and Uttar Pradesh. Due to release of funds in the month of February / March 2016, except the State of Manipur, the remaining States could not conduct the programs before 31/03/2016. The SAMETIs of U.P. and Jharkhand for which bulk of the allocations has been made, have already geared up their district level organizations (KVKs/ATMAs) to complete their targets within the next quarter of the year.

5 Management Education Programs

Post-Graduate Diploma in Management (Agribusiness Management) [PGDM (ABM)]

Genesis

5.1 The policy of economic reforms has brought structural changes in the economy, which resulted in a major shift in the Indian agricultural scenario. The primacy of subsistence orientation yielding place to commercialization opened up vast opportunities for value addition, packaging and exports of agricultural products with high levels of technology. The policies of globalization have opened up unprecedented opportunities as well as great challenges. These are placing significant demand for competent techno-managerial manpower in the agribusiness sector.

5.2 MANAGE, in response to this need, launched a two-year residential Post Graduate Diploma in Management (Agribusiness Management) in 1996 on a self-financing basis. The program is recognized by the All India Council for Technical Education (AICTE) and accredited by National Board of Accreditation (NBA). The Association of Indian Universities has accorded equivalency to MANAGE PGDM (ABM) with MBA of an Indian University.

Objectives

5.3 The program aims to prepare business leaders and techno-managers for careers in sectors related to agriculture, food, agri-input, agri-banking, retail, supply chain management etc.

The objectives of the program are:

To develop adequate conceptual base in different subject areas of agribusiness, so as to prepare young minds as competent professionals;

To equip students with adequate knowledge, suitable skills and right attitude for managerial decision-making in the Agribusiness sector;

To encourage entrepreneurial spirit and mould the youngsters into effective catalysts of change in agriculture.

Admission Process

5.4 MANAGE has adopted objective criteria for short-listing and selection of candidates, which include the CAT Score, Group Discussion, Paper Writing, Extempore / Micro Presentation, Work Experience, Academic Record and Personal Interview.

Program Design

5.5 The program has been designed keeping in view the needs of the various segments of the agribusiness sector, and is divided into VII trimesters covering 116 credits. Forty-three subjects, broadly distributed into basic, functional, sectoral and general courses, are covered in the academic curriculum. Courses with focus on Agribusiness Management include Agri-input Marketing, Agri-export Management and International Trade, Procurement Management, Supply-Chain Management, Rural Advertising and Communication, Commodity Futures and Trading, Participatory Extension Management, Quantitative Aids for Agribusiness, Food Retailing, Micro-Finance, Rural Credit, Agri-Finance and Banking etc.

Summer Internship

5.6 Summer internship during the fourth trimester provides practical field experience to the students. During the internship, students take up an assignment offered by Agribusiness companies, which helps the students to refine their knowledge and sharpen their managerial skills through hands-on experience in field situations. The summer project is evaluated by the supervisor or an executive from the company. These projects carry 10 credits and are evaluated for 100 marks. All the students of the 2015-17 batch are placed for Summer Internship.

5.7 The companies, which offered internship to the students are: "Bharat Insecticides Ltd., Coromandel International Ltd., Dow Agrosciences India Pvt. Ltd., Gramco Infratech Pvt. Ltd., HDFC Bank, ICRISAT, ITC-ABD, Light Micro Finance, Mars International India Pvt. Ltd, Mordor Intelligence, Nagarjuna Group, NCDEX, National Innovation Foundation, PI Industries, PwC, Raasi Seeds, Samunnati, Sumitomo Chemical India Pvt. Ltd., Syngenta, T Stanes Ltd., TAFE, Tata Rallis". The students also take up other short-term projects and assignments.

Industrial Visit

5.8 The students undertake an industrial visit during the fifth trimester, with an objective to approach new companies and appraise them about the unique features and strengths of PGDM (ABM). This is also an opportunity to explore possibilities for final placement and summer internship with these companies. Students of PGDM (ABM) 2014-16 batch visited over 200 companies and made presentations to the senior executives.

SPICE

5.9 The students of PGDM (ABM) bring out a quarterly newsletter – SPICE. The newsletter features the latest campus news including industry-interface program, guest lectures, events, articles by students and faculty feedback. Four issues were published during the year.

Final Placement

5.10 Twenty eight companies visited the campus and recruitied all the graduates for the batch 2014-16. The CTC offered was in the range of Rs. 5.00 - 18.00 lakhs per annum with average CTC being Rs.7.7 lakhs per annum.

5.11 The companies which recruited the students are: "AB Vista, ADM, Coromandel International Ltd., DCM, Dhanuka, Dilasa, Excel Crop Care Ltd., HDFC Bank, ICICI Bank, IKSL, ITC-ABD, Janalaxmi, KRIBHCO, L&T Finance, Mahindra, Mahyco, Mordor Intelligence, NABCONS, PwC, Raasi Seeds, Samunnati, Skylark, Sumitomo, T Stanes, Tata Rallis, Telangana Seeds Corporation, UPL, Yes Bank".

Program Management

5.12 The program is guided by the Advisory Committee, Academic Committee, Examination Committee, Appeals Committee and Grievance Redressal Committee.

Ranking of PGDM (ABM)

5.13 This year too, MANAGE has been ranked as one of the best B-Schools in the country.

Ranks by OUTLOOK-2015

2nd Best Sectoral B-school
4th Best B-school in South India
10th Best Government B-school
10th Best B-school in Personality Development & Industry Exposure
13th Best B-school as per ROI
21st Best in Top 100 B-schools in India

Ranks by BUSINESS TODAY – 2015

1st Best B-School in Hyderabad
3rd Best B-School in Learning Experience
3rd Best B-School in South India
17th Best B-School in Living Experience
22nd Best B-School as per ROI
30th Best B-School in India

Ranks by BUSINESS WORLD – 2015

4th Best Sectoral B-School in India
9th Best B-School in Infrastructure and facilities
23rd Best B-School in India
25th Best B-School in Placements

Interaction with Business Leaders through 'Samanvay Guest Lectures'

5.14 Eminent persons from the Industry and Academia are invited to interact with the students as part of Industry interface. Some of the executives who interacted with students during the year are:

Sl.No.	Name	Organisation	Designation
1	Raman Singh Saluja	Gramco Infratech	Founder
2	Nitin Choudhary	Samunnati Valuechain Finance	Co-Founder
3	T Aravind	Syngenta Foundation India	Manager
4	Shailesh Kanani	ADM	Head - Commercial
5	Beth Osowski	ADM	Graduate Talent Coordinator
6	P Kulandaivel	Tata Rallis	Head - Seeds
7	Tushar Sethi	Janalakshmi Financial Services	Head - Talent Acquisition Janalaxmi
8	Tejaswy Rama	Ernst and Young	Executive Vice President
9	Dinesh Bhosale	AB Vista	Director South Asia
10	Velumurugan	Mahindra Agribusiness Division	Business Head Seeds
11	P Raveendran	T Stanes	Senior General Manager (Sales and Marketing)
12	T Gourishankar	Nagarjuna Agro Chemicals	Head - Human Resources
13	Ajay Kakra	PwC	Director - Agri and Natural Resources Division
14	Mihir Jyoti Mohanta	Mother Dairy	GM - Supply Chain
15	Sai Casula	Green Exchange- Commercial	Founder
16	Madhab Adhikari	Coromandel International	GM& Divisional Head - East
17	Gulshan Dhanjal	HUL	Global Procurement Manager- Commercial
18	Kamal Kumar	Dhanuka Agritech	HR Head- Commercial
19	Somnath Bera	PS International India Pvt. Ltd.	Director and Country Manager
20	Biswajit Nayak	Shriram Bioseeds Genetics India Ltd.	All India Product Manager
21	Asutosh Kumar Sinha	Villgro	Founder

Moments of Pride

5.15 Students participated in various competitions organized by other institutions and won prizes. Details are given below:

1st in "SPARDHA-2016" Extempore at VAMNICOM, Pune in February, 2016

1st in "SPARDHA-2016" Essay Writing at VAMNICOM, Pune in February, 2016

1st in "SPARDHA-2016" Business Quiz at VAMNICOM, Pune in February, 2016

1st in "MARK MANTRA Article Writing" at IIFT, Kolkata in January, 2016

3rd in "DRISHTI 2015" Management Case Study at SIBM (Symbiosis), Pune in December, 2015

5.16 MANAGE PGDM(ABM) organized "Krishi Chanakya" a B-Fest-2015 on 27th and 28th September, 2015. There were various events including i) B-Plan (Aakanksha), ii) Case study (Sushodh), iii) Chakravyuh (Debate) and iv) Paper presentation (Sameeksha) organized during the B-Fest. In addition to these events, HR Summit and several spot events such as Photography, Figure Making, Turn Coat, Face Painting were also organized. Eminent guests from industry as well as students from various B-Schools participated in the event.

5.17 MANAGE and M/s. Re-Engineering Business Solutions (RenB), Mumbai, signed MoU to start a **Start-Up Incubator** on MANAGE campus Hyderabad, which will enable the students/alumni to take their innovative ideas to the market and create their Start-up Firms which will benefit from this initiative. The School would utilize the existing infrastructure, faculty, and facilities for this purpose. The Proposal to start an Incubator in Collaboration with RenB Solutions is another step towards developing entrepreneurship by MANAGE. RenB Mumbai, a company specialising in Start-Up Incubator Management would provide the Management support and Start Up incubator Program with Industry link-ups for the Start-ups.

Post Graduate Diploma in Agricultural Extension Management (PGDAEM)

5.18 MANAGE launched a one-year Post Graduate Diploma in Agricultural Extension Management (PGDAEM) on a distance learning mode during 2007-08. The program is sponsored by the Department of Agriculture and Cooperation (DAC), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (MoA & FW), Government of India as a part of "Support to State Extension Programs for Extension Reforms Scheme".

5.19 The objectives of the PGDAEM Program are:

1. To enhance the techno-managerial competence of extension functionaries
2. To acquaint the extension functionaries on the latest developments in agriculture and allied sectors
3. To equip the extension functionaries with latest tools and techniques for participatory decision making,
4. To help them develop an insight into various extension models to enrich the agri value chain.

5.20 A total of 14726 candidates, have been enrolled in PGDAEM since its inception. The eighth batch of PGDAEM was completed in December 2015, enrollment of ninth batch is in progress.

5.21 This program is in line with the Mission of MANAGE which is to facilitate the acquisition of managerial and technical skills by extension officers, managers, scientists and administrators, in all sectors of agricultural economy with a view to enable them to provide the most effective support and services to farmers and fishermen for practicing sustainable agriculture.

5.22 The duration of the program is of one year spread over two semesters, each of 5 courses with a 32-credit load. The course fee is Rs.15,000/- for both public and private extension functionaries. The fee for public extension functionaries is met from funds under the Extension Reforms Scheme.

5.23 The program is conducted on a distance-learning mode supported by printed study material in Hindi and English, video lectures and contact classes in collaboration with SAMETI or at an identified institute within the State. The study material, pre-recorded video sessions and question bank are available online on MANAGE website.

5.24 Course modules

Semester I

Course 101:	Introduction to Agricultural Extension Management	(4 Credits)
Course 102:	Communication of Agricultural Innovations	(3 Credits)
Course 103:	Principles and Practices of Extension Management	(3 Credits)
Course 104:	Participatory Approaches in Agricultural Extension	(2 Credits)
Course 105:	Research Methods in Agricultural Extension	(2 Credits)

Semester II

Course 201:	Market led Extension	(4 Credits)
Course 202:	Agri-Business and Entrepreneurship Development	(3 Credits)
Course 203:	Project Management in Agricultural Extension	(2 Credits)
Course 204:	Information and Communication Technologies in Agriculture	(3 Credits)
Course 205:	Sustainable Livelihood in Agriculture	(3 Credits)
Course 206:	Project work	(3 Credits)

PGDAEM Workshop 18 January 2016

Progress

5.25 A total of 14726 candidates (14614 from public sector and 112 from private sector) have enrolled in this program from 34 states/UTs since its launch in 2007. Since inception, 10246 candidates have successfully completed the program. During the year under review, out of the 2119 candidates enrolled for the 8th batch, 1108 candidates successfully completed the program.

5.26 An opportunity was given to 1954 backlog candidates of 2007-08 to 2012-13 to appear in the Supplementary examination conducted in December 2015 along with backlog candidates of 2013-14. Of the backlog candidates who availed this opportunity, 349 candidates from 2007-08 to 2012-13 batches and 368 candidates from 2013-14 successfully completed PGDAEM.

Further, 1049 candidates from 23 states enrolled into the program in March 2016 as the 9th batch of PGDAEM. Admissions are in process.

5.27 Milestones

A national workshop was organized and attended by Directors/Course coordinators of 18 states and the project work guidelines were revised to include technical component and mandatory field work with project topics categorized as A - Technical, B - Government Schemes (State and Central) and C - Extension Approaches.

Considerable efforts were made by PGDAEM Cell to reduce the backlog and increase the pass percentage.

Under a collaborative program, jointly organized by MANAGE and NIPHM, to achieve appropriate blending of technology with extension management, skills were imparted to 55 participants (PGDAEM candidates) in the areas of Agro Eco System Analysis (AESA) based Plant Health Management and Plant Bio-security.

In order to develop a competent team of MANAGE facilitators, an exercise was taken up to identify potential candidates from the successful PGDAEM candidates of all the enrolled states and 60 candidates from 33 states were shortlisted for a MANAGE PGDAEM Facilitator Development Training.

A Review workshop on PGDAEM was conducted on 18 January 2016 in which 18 officers representing SAMETIs of 15 states participated, wherein participants interacted with MOA, Extension Reforms Unit, through video conference, to discuss the changed pattern of funding in PGDAEM.

6 Information, Documentation and Publications

6.1 MANAGE Library provides information and documentation services to faculty, participants and students in areas relevant to MANAGE and supports training, teaching, research and other projects and programs of the Institute.

Information Resources

6.2 The collection includes books, journals, reports, videocassettes, CDs/DVDs in agriculture and allied areas. The focus areas are agricultural extension, agricultural economics, management, marketing, human resource development, project management, natural resource management, participatory approaches, gender studies, agribusiness, entrepreneurship, trade, information technology etc.

Electronic Databases

6.3 MANAGE Library subscribed to electronic databases including 'Prowess', 'Commodities' and 'India Stats'. Prowess is a database of Indian companies, Commodities provides prices, market intelligence, historical data and forecasts for agricultural crops, while India Stats is an online database giving access to statistical information on India. The Institute also subscribed to an e-journal database 'ABI-Inform' which can be accessed by Faculty, staff and students.

Information Services

6.4 The library operations are managed through eGranthalaya software. Information Services include access to information, assistance in the use of databases and other information resources; reference services and literature search services. The library periodically alerts faculty to the new resources added to the collection by sending details of articles published in current journals. This is also posted on the Library page on the website.

Publications

6.5 MANAGE publishes a half-yearly 'Journal of Agricultural Extension Management' to disseminate information relating to extension systems and practices, research on extension, efficient organization of technology transfer and other socio-economic issues concerning agriculture and allied areas for the benefit of policy makers, scientists and extension functionaries. Two issues were published and disseminated during the period.

6.6 A bi-monthly MANAGE Bulletin focuses on various activities of MANAGE including training, education, research, consultancy, implementation of schemes, etc. The Bulletin is accessible online.

6.7 A Hand book on Marketing Extension for Extension functionaries was published by MANAGE.

Information Technology Support

6.8 The Information Technology support is provided through 150 computer systems connected to two leased lines of 100 mbps and 22 mbps with 24 hours Internet connectivity. Video-conferencing facility is available to facilitate communication with the Ministry and various other institutions. The campus is wi-fi enabled.

MANAGE on the Web

6.9 Information on MANAGE training and education programs, projects and publications, is updated on the website at www.manage.gov.in both in Hindi and English. The Academic Calendar is also available on MANAGE website with a mobile app for registration. Information about GoI sponsored schemes implemented by MANAGE, and updates on MANAGE Research and Consultancy projects are also accessible on the website.

7 Promotion of Official Language

7.1 During the year under review, quarterly meetings of the Official Language Implementation Committee were conducted regularly and reports sent to the Department of Official Language, Ministry of Agriculture, and the Regional Implementation Office, Department of Official Language, South Block, Bangalore.

7.2 Correspondence from MANAGE with the States under "Regions A and B" of Official Language Rules was in Hindi and English (bilingual). In compliance with Section 3 (3) of Official Language Act, efforts are on to prepare the documents in bi-lingual form. The 'Annual Report', 'Annual Accounts' and Annual Training Calendar for the year 2015-16 were prepared in bilingual format.

7.3 MANAGE website is in bi-lingual form and is updated regularly. A *Handbook on Marketing Extension for Extension functionaries* published by MANAGE was translated into Hindi and made available on the website. A book on Success stories of Agripreneurs was also translated into Hindi and placed on the MANAGE web site. One batch of a newly introduced proficiency course in Hindi "Parangat" was organized in MANAGE during February-March 2016. "Prabodh" was also organized for Group –'C' staff (earlier Group-D)

7.4 A National Workshop on "Hindi Main Takneeki Sahitya Ka Srujan Aur Uska Vistrut Sanchaar: Krishi Sahitya Ke Vishlesh Sandarbh Mein" was organized on 9-12-2015.

Twenty-eight participants from different organizations participated in the workshop. Participants included Senior Scientists, Hindi Officers, Hindi Translators of Central Government Organizations working in the field of Agriculture and allied areas.

7.5 MANAGE has been given the responsibility of Town Official Language Implementation Committee (TOLIC)-4 of Central Government Organizations by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, GoI. Fifty-one member organizations are covered under this TOLIC.

7.6 To promote usage of Official Language, Quarterly Hindi workshops were organized regularly. To encourage Hindi typing in official correspondence, staff were nominated for Basic Computer Training in Hindi organized under Hindi Teaching Scheme. Hindi Fortnight was organized during September 2015. Various competitions were organized and prizes distributed to the winners.

7.7 MANAGE Bulletin and Agripreneur e-bulletin were prepared in bilingual form and made available on MANAGE website.

8 Administration and Accounts

8.1 The general supervision of MANAGE vests with the General Council presided over by the Hon'ble Union Agriculture Minister, Government of India. There are two Vice Presidents of the General Council, the Hon'ble Minister of State for Agriculture and the Secretary (A&C), Ministry of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Government of India. The General Council exercises overall control on MANAGE and issues policy directions for its efficient management and administration. The composition of the General Council of MANAGE is given in Annexure - I.

8.2 Subject to the overall control and directions of the General Council, the Executive Council oversees implementation of policy matters and activities of MANAGE in accordance with the Rules and Bye-laws. The Executive Council is chaired by the Secretary (A&C). The composition of the Executive Council is at Annexure - II.

8.3 The Director General of MANAGE is appointed by Government of India and is responsible for the day-to-day functioning of the Institute. The Director General is assisted by Faculty, Administration, Accounts and Engineering Wings. The list of faculty, officers and staff is given at Annexure - III.

Funds

8.4 The DAC, MoA &FW, GoI releases grants-in-aid to MANAGE every year. Sixty per cent of the recurring expenditure, including that of training programs, is met from the grants released by DAC & FW, and the balance 40 per cent is met by MANAGE out of its own earnings. However, full expenditure of MANAGE infrastructure is met from the GoI funds.

Meetings

8.5 The following meetings were held during the period under report:

Executive Council

- The 67th Meeting of the Executive Council was held on 12th October 2015 at Krishi Bhawan, New Delhi.

- The 20th Meeting of the Academic Committee of MANAGE was held on March 1, 2016. The meeting was chaired by Smt. V. Usha Rani, IAS, Director General MANAGE. The Committee reviewed the academic activities of MANAGE and also reviewed and approved the Academic Calendar for 2016-17.

Academic Committee Meeting March 2016

ANNEXURES

Annexure - I

Composition of General Council of MANAGE as on 31/03/2016

Rule No. 3(a)	Composition of General Council	S. No.	Name & Address of the Member
i	**President of MANAGE**: The Minister In charge of the Ministry / Department, Government of India dealing with MANAGE.	1	Shri Radha Mohan Singh Hon'ble Union Minister for Agriculture Ministry of Agriculture & Farmers Welfare Krishi Bhawan New Delhi – 110 001
ii	**Two Vice-Presidents** of MANAGE: a) The Minister of State Agriculture, MOA, GOI and	2	Dr. Sanjeev Kumar Balyan, Hon'ble Minister of State for Agriculture, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare Government of India Krishi Bhawan, New Delhi – 110 001
	b) Secretary, Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, GOI	3	Shri Shobhana K Pattanayak, IAS Secretary (Agriculture & Cooperation) Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhawan New Delhi - 110 001
iii	One person from non-official Institution in India working in Agricultural Development and Allied fields – to be nominated by the President of MANAGE as member	4	Vacant (from 4th October, 2015)
iv	Three eminent persons who have made noteworthy contributions in the field of agricultural development and allied subjects.	5	Vacant (from 4th October, 2015)
		6	Vacant (from 4th October, 2015)
		7	Vacant (from January, 2016)
	Ex-Officio Members		
v	Director General, NIRD	8	Dr. W R Reddy, IAS Director General National Institute of Rural Development & Panchayati Raj, Rajendranagar, Hyderabad - 500 030
vi	Director General, NIAM	9	Smt. Irina Garg, IRS Director General National Institute of Agricultural Marketing (NIAM) Kota Road, Bambala, Near Sanganer, Jaipur – 303 906

vii	Director General, ICAR	10	Dr. Trilochan Mohapatra Secretary (DARE) & Director General Indian Council of Agricultural Research Krishi Bhawan New Delhi - 110 011
viii	a) Additional Secretary b) Joint Secretary in charge of Extension c) Financial Adviser in the Ministry / Department of Govt.of India dealing with MANAGE	11	Shri. Raghavendra Singh, IAS Addl. Secretary (Agril. Extn.) Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India Krishi Bhawan New Delhi – 110 001
		12	Shri Narendra Bhooshan, IAS Joint Secretary (Agricultural Extension) Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi – 110 001
		13	Shri Kumar Sanjay Krishna, IAS AS & Financial Adviser Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India, Krishi Bhawan New Delhi – 110 001
ix	Agriculture Commissioner, Govt. of India, Department of Agriculture and Cooperation, New Delhi	14	Agriculture Commissioner Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi
x	Secretary in the Department of Planning Commission, Govt. of India or nominees not below the rank of Joint Secretary to the Govt. of India	15	Secretary Planning Commission, Govt. of India Yojana Bhavan, New Delhi - 110 001
xi	Four Secretaries to the State Governments / Union Territories In charge of Agricultural Production (in rotation) or their nominees not below the rank of Deputy Secretary to the State Government.	16	Vacant
		17	Vacant
		18	Vacant
		19	Vacant

xii	Two Directors of Agriculture of States/Union Territories (to represent their regions of the country by rotation); or their nominees not below the rank of Additional Director of Agriculture or an officer of equivalent rank.	20 21	Vacant Vacant
xiii	The Director General of MANAGE appointed by the Government of India, Ministry of Agriculture. (Ex Officio Member & Member –Secretary)	22	Smt. V. Usha Rani, IAS Director General National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE) Rajendranagar, Hyderabad -500 030.
xiv	Two Vice-Chancellors of Agricultural Universities (by rotation) or their nominees not below the rank of Director (Ex-officio Members)	23 24	Vacant Vacant

Annexure - II

Composition of Executive Council of MANAGE as on 31/03/2016

Rule No.	Composition of Executive Council	S. No.	Name & Address of the Member (Chairman, Officials & Non-official Members)
5.I (i)	Ex-Officio Members		
a)	Secretary (A & C) as Vice President of MANAGE shall be chairman of the Executive Council	1	Shri Shobhana K Pattanayak, IAS Secretary (AC&FW) Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare Government of India, Krishi Bhawan, New Delhi 110 001.
b)	Additional Secretary in-charge of Extension in the Ministry / Department, Government of India dealing with MANAGE shall be the Vice-Chairman of the Executive Council	2	Shri Raghvendra Singh, IAS Additional Secretary (Extension) Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India, Krishi Bhawan, New Delhi 110 001.
c)	The Director General of MANAGE	3	Smt. V. Usha Rani, IAS Director General National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE) Rajendranagar, Hyderabad – 500 030.
d)	Joint Secretary in-charge of Extension and Financial Adviser in the Ministry / Department, Government of India dealing with MANAGE	4	Shri Narendra Bhooshan, IAS Joint Secretary (Extension) Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India, Krishi Bhawan, New Delhi 110 001.
		5	Shri Kumar Sanjay Krishna, IAS Additional Secretary & Financial Adviser, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India, Krishi Bhawan, New Delhi 110 001.

e)	**Non-official Members** Two eminent persons who have made note-worthy contributions in the fields of agricultural development/and allied subjects; to be nominated by the Government of India from among the members of the General Council	6	Vacant
f)	**One member** to be nominated by the General Council from among the non-official members of the General Council	7 8	Vacant Vacant

Annexure - III

MANAGE Faculty, Officers and Staff

Faculty
Smt. V. Usha Rani, IAS **Director General**
Dr. V.P. Sharma Director (ITDP) M.Sc. (Statistics); M.A. (Economics); MBA (Operations Management); Ph.D. vpsharma@manage.gov.in
Dr. Vikram Singh Director M.A. (Psychology), M.Phil; Ph.D. vikrams@manage.gov.in
Dr. P. Chandra Shekara Director (Agricultural Extension) and Center for Agri-Entrepreneurship Development (CAD) Ph.D. (Agricultural Extension) chandra@manage.gov.in
Dr. K. Anand Reddy Director (HRD) and & Principal Coordinator - PGDM (ABM) M.A. (Economics); Ph.D. (Management) anandreddy@manage.gov.in
Dr. B.K. Paty Director (OSPM) Ph.D, M.B.A, M.Com bkpaty@manage.gov.in
Dr. K. Uma Rani Director and Principal Coordinator - PGDAEM Ph.D. (Home Science, Extension Education) kumarani@manage.gov.in
Dr. R. Saravanan Director (Agricultural Extension) M.Sc. (Agricultural Extension); Ph.D. (Agricultural Extension) saravanan.raj@manage.gov.in
Dr. M.A. Kareem Deputy Director (Agricultural Extension) M.Sc. (Agricultural Extension); Ph.D. (Agricultural Extension) makareem@manage.gov.in
Dr. G. Jaya Deputy Director (HRD) M.B.A.; Ph.D. (Management Science); PGDAEM gjaya@manage.gov.in
Dr. Lakshmi Murthy Deputy Director (Documentation) M.A. (Economics); M.L.I.Sc.; Ph.D. (Library and Information Science); Advanced Diploma in French; PGDAEM lakshmi@manage.gov.in

Dr. N. Balasubramani
Deputy Director (OSPM)
M.Sc. (Agri.), Ph.D. (Agricultural Extension), MBA, PGDHRM
balasubramani@manage.gov.in

Dr. Karabasayya C. Gummagolmath
Deputy Director (M&E)
Ph.D. (Agricultural Economics)
kcgum@manage.gov.in

Dr. B. Renuka Rani
Assistant Director (HRD)
M.S.W.; Ph.D. (Women Studies); PGDPR (Public Relations); PGDAEM
brenuka@manage.gov.in

Shri. G. Bhaskar
Assistant Director (IT)
MCA, MBA, MCSE, M.A., Dip. in RDBMS & OOPS, PGDAEM
gbhaskar@manage.gov.in

Dr. P. Lakshmi Manohari
Assistant Director (Agricultural Extension)
M.Sc. (Agricultural Extension); Ph.D. (Communication-Agriculture)
plmanohari@manage.gov.in

Dr. Shahaji Sambhaji Phand
Assistant Director (Allied Extension)
M.V.Sc.(Veterinary Extension Education); Ph.D (Veterinary Extension Education)
shahaji@manage.gov.in

Dr. K. Venkateshwar Rao
Programmer
M.Tech. (CSE); M.Sc (Physics); PGDCA, PhD (Management)
kvrao@manage.gov.in

Dr. A. Srinivasacharyulu
Research Associate
M.L.I.Sc.; M.A (Phil); Ph.D (Library and Information Science);
PGDLAN; PGDAEM
ascharyulu@manage.gov.in

Dr. K. Sai Maheshwari
Research Associate
M.Sc., PG Diploma in Sericulture; Ph.D (Sericulture); PGDAEM
kmaheshwari@manage.gov.in

Dr. B. Venkat Rao
Research Associate
M.B.A. (Marketing); Ph.D. (Management)
bvrao@manage.gov.in

Dr. P. Kanaka Durga
Research Associate
MA (Economics); M.Phil (Economics); Ph.D. (Economics)
kanakad@manage.gov.in

Dr. A. Krishna Murthy
Documentation Assistant
M.A. (Pub.Admn.); M.LI.Sc, M.Phil.; Ph.D (Library and Information
Science);PGDLAN krishnam@manage.gov.in

Officers and Staff	
Shri. Shridhar Khiste Deputy Director (Admn.)	Shri Ch. Naga Mallikarjuna Rao Assistant Accounts Officer
Dr. Radha Rukmini Medical Officer	Smt. N. Usha Rani PS to Director General
Dr. K. Srivally Hindi Translator	Shri E. Nagabhushanam Stores Officer
Shri A V N N Gupta Office Superintendent	Shri E. Rajasekhar Office Superintendent
Shri. P. John Manoj Asst. Engineer (Civil)	Smt. V. Mangamma Sr. Accountant
Shri K. Jagan Mohan Rao Receptionist-cum-Caretaker	Smt P. Bharathi Rani Sr. Stenographer
Smt. B. Ramani Sr. Stenographer	Smt. K. Uma Maheshwari Sr. Stenographer
Smt. B. Meenakshi Sr. Stenographer	Smt. N. Asha Latha Sr. Scale Stenographer (CAD)
Shri B. Chakradhar Rao EDP Assistant	Shri M. Srinivasa Rao EDP Assistant
Shri K. Uday Verma Telephone Operator	Shri M. Venugopal EDP Assistant
Shri Veeraiah Junior Engineer (Elec)	Shri Sunil Kumar Mess Manager
Smt. Waheeda Munawer Jr. Accountant	Shri P. Rama Murty Cashier
Shri T. Nagaraju Jr. Accountant	Shri Girjesh Joshi House Keeper
Shri M. Siva Kumar Jr. Accountant	Smt. P. Jyothi Jr. Stenographer
Smt. G. Sandhya Rani UDC	Smt. M. Bhagya Lakshmi Asst. Cashier
Smt. K. Kamala UDC	Shri. V. Vamseekrishna UDC
Shri. T. Phani Kumar Jr. Stenographer	Ms. A. Ronitha Jr. Stenographer
Shri K. Krishna Murthy Staff Car Driver (Grade- II)	Shri B. Mallesha Driver

Shri S. Sathyanarayana Driver	Shri G.S. Padma Rao Binder
Shri N. Raghupathi Plumber	Shri. Nandan Giri Cook
Shri G. Narsimhulu MTS	Shri B. Yadagiri MTS
Shri C. Narayana MTS	Shri G. Rajababu MTS
Shri N.G. Kotaiah MTS	Shri B. Ellamaiah MTS
Smt. J. Vijaya MTS	Shri N. Sivalingam MTS
Shri B. Ramachander MTS	Shri B. Sathaiah MTS